राष्ट्रीय संस्करण

मनप्रीत बोले, टीम में जादुई ताकत >> 12

वर्ष 5 अंक 62

मूल्य ₹8 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 11 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

दागी राजनेताओं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

उम्मीदवारों का आपराधिक ब्योरा नहीं देने पर आठ दलों पर जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आदेश का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई, राजनीति के अपराधीकरण पर जताई चिंता
- पार्टियों ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का आपराधिक ब्योरा नहीं किया सार्वजनिक
- जदयू, राजद, लोजपा, कांग्रेस, भाजपा और भाकपा पर एक-एक लाख और माकपा व राकांपा पांच-पांच लाख का जुर्माना

राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने के निर्देश

- राजनीतिक दल उम्मीदवार के आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा वेबसाइट के होम पेज पर देंगे
- चुनाव आयोग एक मोबाइल एप बनाएगा, जिसमें उम्मीदवार की ओर से दिए गए आपराधिक ब्योरे की सूचना होगी
- चुनाव आयोग वोटरों को प्रत्येक उम्मीदवार के आपराधिक ब्योरे की जानकारी देने के लिए बड़ा जागरूकता अभियान चलाएगा
- जागरूकता अभियान इंटरनेट मीडिया, वेबसाइट, टीवी जैसे माध्यमों के जरिये चलाया जाएगा
- चुनाव आयोग आदेश के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाएगा, ताकि कोर्ट के आदेश का किसी भी पार्टी द्वारा पालन न किए जाने पर कोर्ट को तुरंत बताया जा सके
- राजनीतिक दल उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर उसका आपराधिक ब्योरा पब्लिश करेंगे
- अगर कोई दल आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देने में नाकाम रहा तो आयोग अनुपालन न होने की जानकारी कोर्ट को देगा

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा

- देश की दूषित हो रही राजनीति को स्वच्छ करना सरकार की तत्काल चिंता नहीं है, राष्ट्र इस बारे में इंतजार कर रहा है और उसका धैर्य अब जवाब दे रहा है।
- आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कानून निर्माता नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन न्यायालय की अपीलों पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही।
- भारत की राजनीतिक प्रणाली का दिन-प्रतिदिन अपराधीकरण बढ़ रहा है। इस मामले में तत्काल कुछ-न-कुछ करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए कानून निर्माताओं से अपील की है कि इसे रोकने के लिए कदम उठाएं। साथ ही कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का आपराधिक ब्योरा सार्वजनिक करने व आपराधिक छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने का कारण बताने के आदेश पर अमल नहीं करने पर आठ सियासी दलों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जदयू, राजद, लोजपा, कांग्रेस, भाजपा और भाकपा को एक-एक लाख रुपये और माकपा व राकांपा को पांच-पांच लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया है।

राजनीतिक दलों को आठ सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए विशेष खाते में यह रकम जमा करानी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक ब्योरे की जानकारी देने और जागरूक बनाने के लिए सियासी दलों व चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए हैं। इसके तहत दलों को उम्मीदवार चयन के 48 घंटे के भीतर उसका आपराधिक ब्योरा वेबसाइट के होम पेज पर सार्वजनिक करना होगा।

ये निर्देश न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी, 2020 के आदेश की अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिकाओं और रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चेताते हुए कहा कि उसके आदेश के बाद बिहार विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था। इसलिए वह नरम रुख अपना रहा है। लेकिन भविष्य में राजनीतिक दलों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 32 फीसद पर कोई न कोई आपराधिक केस था। अचरज की बात तो यह है कि जीतने वालों में से 68 फीसद पर आपराधिक मामला था।

चुनाव लड़ने वाली 10 पार्टियों में से आठ पर लगाया जुर्माना पेज>>3

हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर वापस नहीं लिए जा सकते जनप्रतिनिधियों के मुकदमे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विशेष अदालतों के जज अगले आदेश तक नहीं हटाए जाएंगे : सुप्रीम कोर्ट
- लोक अभियोजक की मुकदमा वापस लेने की शक्ति का हो रहा दुरुपयोग : न्यायमित्र

सांसदों और विधायकों के आपराधिक मुकदमों को वापस लेने के राज्य सरकारों के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संबंधित हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। साथ ही हाई कोर्टों से आग्रह किया है कि वे मुकदमा वापसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को देखते हुए मुकदमा वापसी के आवेदनों को जांचें-परखें। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सांसदों, विधायकों के मुकदमों की सुनवाई कर रही विशेष अदालतों के जज अगले आदेश तक नहीं हटाए जाएंगे।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों के लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे की मांग वाली अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। न्यायमित्र विजय हंसारिया ने कहा, लोक अभियोजक की मुकदमा वापस लेने की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों के खिलाफ बहुत से मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने उप्र, महाराष्ट्र व कर्नाटक आदि का हवाला दिया। मालूम हो कि सीआरपीसी की धारा 321 में लोक अभियोजक को अर्जी दाखिल कर मुकदमा वापस लेने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि धारा 321 में मिली शक्ति एक जिम्मेदारी होती है। उसका जनहित में उपयोग होना चाहिए। इसका इस्तेमाल बाहरी राजनीतिक वजहों से नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, उसने हाल ही में केरल के एक केस में धारा 321 के तहत मुकदमा वापस लेने के बारे में गाइड लाइन तय की है। इसमें मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट की सहमति को जरूरी किया गया है। लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मुकदमा वापस लेने के लिए सिर्फ साक्ष्य की कमी को दलील नहीं दे सकता। उसे न्यायहित को भी ध्यान में रखना चाहिए।

कोर्ट ने आदेश दिया कि सांसदों, विधायकों के मुकदमों की सुनवाई कर रहे विशेष अदालतों के जज अगले आदेश तक नहीं हटाए जाएंगे। तबादले पर रोक वाला यह आदेश सिर्फ संबंधित जज के सेवानिवृत्त होने या उनकी मृत्यु होने पर ही नहीं लागू होगा। कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को आदेश दिया है कि वे ब्योरा दें कि ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा कौन सा जज कितने दिनों से इस पद पर है? उसके पास कितने केस हैं और उसने कितने केस निपटाए हैं? कोर्ट ने मामले को बहस के लिए 25 अगस्त को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।

स्वतंत्रता के सारथी — महामारी से आजादी

सवा साल तक बिना छुट्टी लिए की मरीजों की सेवा

अमृतसर : संकट में नागरिकों की जीवनरक्षा का कार्य देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प है। कोरोना काल में अमृतसर के डाक्टर मदन मोहन ने सवा साल तक बिना अवकाश ड्यूटी कर यह संकल्प निभाया। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

कैबिनेट से हटे मंत्रियों को बंगला छोड़ने का नोटिस

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए कैबिनेट मंत्रियों को अपना मौजूदा बंगला छोड़ने को कहा गया है। इसके बदले में उन्हें दूसरा बंगला चुनने को कह दिया गया है। नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 27 सफदरजंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। इस बंगले में फिलहाल पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रह रहे हैं। जिन्हें बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया है, उनमें पूर्व मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा व प्रकाश जावडेकर शामिल हैं।

राजनीति ▸ पृष्ठ 4

सोनिया ने दी अमरिंदर कैबिनेट में फेरबदल को मंजूरी

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा की। सोनिया ने कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद कैप्टन विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा को लेकर संतुष्ट है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके दी।

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 5

उज्ज्वला से महिला सशक्तीकरण के संकल्प को बल मिला : पीएम

महोबा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी की तरह अब हर घर की रसोई तक गैस भी पहुंचेगी। पीएम ने मंगलवार को उप्र के महोबा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला-2.0 योजना का शुभारंभ किया। मोदी ने कहा, उज्ज्वला योजना के पहले चरण में आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। इससे मां, बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य, सुविधा व सशक्तीकरण के संकल्प को बल मिला। अब दूसरे चरण में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को फायदा मिलेगा।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 7

एटीएम में नकदी नहीं तो बैंक पर 10,000 रुपये जुर्माना

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा है कि अगर नकदी की कमी की वजह से ग्राहक को एटीएम से खाली हाथ लौटना पड़ा तो संबंधित बैंक पर पहली अक्टूबर से जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआइ ने कहा है कि किसी भी एटीएम में एक माह में 10 घंटे तक नकदी की कमी स्वीकार्य है। उससे ज्यादा देर तक किसी एटीएम में नकदी की कमी पाई गई तो बैंक को प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

ओबीसी की पहचान करने का राज्यों को फिर मिलेगा हक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से बहुमत से पारित
- विधेयक के पक्ष में पड़े 385 मत, खिलाफ में नहीं पड़ा एक भी वोट
- विपक्ष का रुख नरम, आज विधेयक के राज्यसभा से भी पास होने की संभावना

ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों का अधिकार फिर से बहाल होगा। लोकसभा ने मंगलवार को 127वें संविधान संशोधन के जरिए ओबीसी से जुड़े इस विधेयक के पक्ष में 385 मत पड़े। विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। हालांकि इस सर्वसम्मति के बावजूद चर्चा के दौरान राजनीति खूब हुई। पक्ष और विपक्ष की ओर से यह जताने की कोशिश भी कि गई कि दूसरे पक्ष ने ओबीसी की चिंता नहीं की। इस विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से भी पारित कराने की तैयारी है।

राज्यों के अधिकार बहाली से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, इस विधेयक से संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। राज्यों को फिर से उनके अधिकार मिलेंगे। जिसमें वे पहले की तरह ओबीसी जातियों की पहचान कर सकेंगे और उनकी सूची तैयार कर सकेंगे। ओबीसी के हित में वह और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, आज जो कांग्रेस पार्टी जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रही है जब वह सत्ता में थी तब इसे क्यों नहीं जारी किया। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है।

वीरेंद्र कुमार ने आरक्षण की 50 फीसद की सीमा खत्म करने संबंधी सवालों का भी जवाब दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह सीमा तय की है। हालांकि यह 30 साल पहले की परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट ने तय किया था। इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह समस्या केंद्र सरकार की वजह से नहीं पैदा हुई है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले के बाद कोर्ट ने राज्यों के अधिकार को खत्म कर दिया था। हम इसे ठीक कर रहे और राज्यों के अधिकार पुनः बहाल कर रहे हैं।

मंगलवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार। प्रेट्र

श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लंबे समय तक रोककर रखा था। जब भाजपा के समर्थन वाली सरकार केंद्र में आई, तो इसे लागू किया गया। ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने लिया। इसके बाद मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा के आल इंडिया कोटे में ओबीसी कोटा लागू करने का काम किया।

सभी पार्टियों ने ओबीसी बिल के बहाने अपने वोट बैंक पर लगाया दांव पेज>>3

भारत ने अपने नागरिकों को दी अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह

- मजार ए शरीफ में फंसे भारतीयों को निकालने को भेजा विशेष विमान
- उड़ानें बंद होने से पहले सब को स्वदेश लौटने की हिदायत

अफगानिस्तान के कुंदुज शहर पर कब्जे के बाद एक प्रवेश मार्ग पर खड़े तालिबान आतंकी। एपी

क्रिकेटर राशिद की मार्मिक अपील

दुनिया के प्यारे नेताओं, संकट के इस दौर में आप हमें अकेला छोड़कर न जाएं। मेरा देश मुसीबत में है। हर दिन हजारों बच्चे, औरतें और मासूम शहीद हो रहे हैं। घर और संपत्तियां उजाड़ी जा रही हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अफगानिस्तान में मारकाट और तबाही बंद होनी चाहिए। हम अमन चाहते हैं। -राशिद खान, अफगान क्रिकेटर

काबुल, प्रेट्र : अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती गिरफ्त के बीच भारत ने वहां मौजूद अपने सभी नागरिकों को देश तत्काल छोड़ने की सलाह दी है। अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर मजार-ए-शरीफ पर कब्जे को लेकर शुरू हुए घमासान के बाद भारत सरकार तेजी से हरकत में आ गई है।

भारत ने मजार-ए-शरीफ के वाणिज्य दूतावास के सभी राजनयिक, कर्मचारियों व नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भेजा। इस विमान ने देर शाम वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वाणिज्य दूतावास अभी बंद नहीं किया गया है। करीब 50 स्थानीय कर्मचारियों के साथ यह काम करता रहेगा।

भारत ने ताजा एडवाइजरी में अफगानिस्तान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे समय रहते अपने देश लौट आएं। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में इस समय करीब डेढ़ हजार भारतीय हैं। अफगानिस्तान से उड़ानें बंद होने से पहले वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों के कर्मियों को भी वापस लौटने को कहा गया है। कर्मचारियों से कहा गया है कि उन्हें अपने नियोक्ताओं से स्वदेश वापसी का इंतजाम करने का आग्रह करना चाहिए। अफगानिस्तान में कवरेज कर रहे मीडिया से जुड़े भारतीय पत्रकारों से भी कहा गया है कि वे दूतावास के संपर्क में निरंतर बने रहें। अगर वे कहीं कवरेज के लिए जा रहे हैं तो संबंधित अधिकारियों को पक्की सूचना दें और बेवजह जोखिम न उठाएं।

इधर तालिबान के चारों तरफ से मजार-ए-शरीफ घेरने के बाद नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वाणिज्य दूतावास ने अपील जारी करते हुए कहा है कि शहर के आसपास जो भी भारतीय हैं, वे विशेष विमान से दिल्ली पहुंचने के लिए संपर्क करें। इसके लिए वाणिज्य दूतावास ने टेलीफोन नंबर भी जारी किए हैं।

तालिबान ने मजार-ए-शरीफ को चारों ओर से घेरा पेज>>11

इंटरनेट मीडिया पर नहीं, अदालत में करें बहस : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं के इंटरनेट मीडिया पर समानांतर कार्यवाही व बहस करने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं को अनुशासित रहते हुए सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस विनीत सरन और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह बहस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है तो इस पर बहस यहीं होनी चाहिए। पीठ ने याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, 'देखिए, एक बार आप इस अदालत में आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बहस यहीं हो रही है और वे सवालों का जवाब देंगे। पक्षकारों को सिस्टम में कुछ विश्वास होना चाहिए।'

पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दी नसीहत

अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता जो कुछ भी कहना चाहते हैं वे अदालत में हलफनामा दाखिल कर कह सकते हैं, पीठ उनके द्वारा उठाए गए हर संदर्भ पर गौर करेगी। इसमें कुछ अनुशासन होना चाहिए।

सिब्बल ने पीठ से सहमति जताते हुए कहा कि वह सौ फीसद इससे सहमत हैं कि जब मामला अदालत में हो तो उस पर किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।

सालिसिटर जनरल ने मांगा वक्त पेज>>3

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने मेज पर चढ़ की नारेबाजी

- काले कपड़े पहनकर आए विपक्षी सांसदों ने सदन की मर्यादा लांघी
- सदन के भीतर का वीडियो बना बाहर भेजने पर सभापति गंभीर
- सरकार ने विपक्ष के कृत्य को हदें पार करने वाला बताया

राज्यसभा में मंगलवार को कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा के बीच विपक्ष ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा व रिपुन बोरा मेज पर चढ़कर नारे लगाते नजर आए। प्रेट्र

एक ओर से कृषि से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा कराई जा रही है, लेकिन कांग्रेस, आप और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है। दरअसल, कांग्रेस सरकार की किसानों को समृद्ध करने वाली नीतियों को पचा नहीं पा रही है। विपक्षी दलों के रवैए ने लोकतंत्र को झटका दिया है। -नरेंद्र तोमर (कृषि मंत्री)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद के मानसून सत्र के महज कुछ दिन और बचे हैं। मगर समूचा चालू सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी कांड, कृषि सुधार के कानूनों और महंगाई समेत अन्य कई मसलों को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा में मंगलवार को हालात इससे भी बदतर हुए। कृषि मुद्दे पर चर्चा शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आ गए और जमकर हंगामा किया। एक मौका ऐसा भी आया, जब कुछ विपक्षी सदस्य महासचिव की टेबल पर चढ़ गए। आप के संजय सिंह जहां मेज पर पालथी मारकर बैठ गए वहीं कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और रिपुन बोरा ने मेज पर खड़े होकर नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। मेज पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे सदस्यों ने आसन की ओर फाइल भी फेंकी लेकिन कोई वहां विराजमान नहीं था। करीब डेढ़ घंटे तक हंगामा होता रहा। बाद में मार्शल इन लोगों को सदन के बाहर ले गए। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही पुनः शुरू होने पर सदस्यों ने फिर मेज पर चढ़कर हंगामा किया।

सदन में विपक्ष के कई सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे। कुछ सदस्यों ने विरोध जताने के लिए काला मास्क लगा रखा था। विपक्षी सदस्यों के सदन के भीतर की कार्यवाही का वीडियो बाहर भेजने को भी सभापति ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने विपक्षी दलों के इस रवैए की तीखी आलोचना की है। दरअसल, कृषि संकट को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में तब्दील करने के फैसले पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताना शुरू किया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा,उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सदन की राय लिए बगैर अल्पकालिक चर्चा में तब्दील करना अनुचित है।

उपसभापति भुबनेश्वर कलिता ने कहा, यह फैसला सभापति का है, जिस पर सदन की सलाह की जरूरत नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर को बोलने के लिए बुलाया। सदन में हो रहे हंगामे के बीच तोमर ने कहा, ऐसे माहौल में कैसे बोला जा सकता है। इसके बावजूद तोमर बोलते रहे। इसके बाद बीजद के सदस्य प्रसन्ना आचार्य ने भी अपनी बात रखी। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में विपक्ष के हंगामे को असंसदीय और हदें पार करने वाला करार दिया। उन्होंने आसन को भी नहीं बख्शा, जमकर अपमान किया।

महामारी से जंग

कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के पुख्ता इंतजाम

देश भर में 277 सेंटिनल सेंटर बनाए गए, कोरोना के म्युटेशन पर रखी जा रही है नजर, 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों और बढ़ते आर नाट वाले राज्यों की भी की जा रही है निगरानी, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए हर हफ्ते 15 सैंपल भेजते हैं सेंटिनल सेंटर

नीलू रंजन, नई दिल्ली

44 जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा। इनमें से 10 जिले केरल और 29 जिले पूर्वोत्तर के राज्यों के हैं

नए वैरिएंट का तुरंत चलेगा पता : डा. एसके सिंह ने कहा कि इससे देश के हर कोने से कोरोना के नए वैरिएंट का पता चल सकेगा। साथ ही यह देखा जा सकेगा कि किस जिले में कौन सा वैरिएंट ज्यादा पाया जा रहा है। यदि किसी वैरिएंट की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो वह पूरे देश में तीसरी लहर का कारण बन सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र से शुरू हुए डेल्टा वैरिएंट के मामले में हुआ, जो पूरे देश में दूसरी लहर का मुख्य कारण बन गया। इंसाकाग में 28 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें जीनोम सिक्वेंसिंग का काम किया जा रहा है। सेंटिनल सेंटर जुलाई में शुरू हुए थे और उस माह 8,000 नमूने भेजे थे, जिनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जा चुकी है।

तीसरी लहर रोकने के लिए टीकाकरण जरूरी : स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार की कोशिश दिसंबर तक देश में सभी पात्र वयस्कों के टीकाकरण करने की है। कोरोना के वैरिएंट पर नजर रखने के साथ-साथ सरकार 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों और आर नाट बढ़ने वाले राज्यों पर नजर रखे हुए हैं, उसे नियंत्रित करने में राज्य सरकारों की मदद की जा रही है।

एक तरफ जहां राज्य सरकारें कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कर रही हैं, वहीं केंद्र सरकार भावी लहर को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने में जुटी है। इसके लिए देश में 277 सेंटिनल सेंटर बनाए गए हैं, जो हर हफ्ते 15 सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं। सरकार अधिक संक्रमण दर वाले जिलों और आर नाट पर नजर बनाए हुए हैं।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक डा. एसके सिंह ने कहा, कोरोना वायरस का म्युटेशन कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। इसलिए देश के हर जिले में वायरस के सैंपल की लगातार जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि म्युटेशन का पता और उसके प्रसार की जानकारी मिल सके। डा. सिंह ने डेल्टा प्लस वैरिएंट से तीसरी लहर की आशंका को खारिज करते हुए कहा, अप्रैल से अभी तक देश में इसके 86 केस ही मिले हैं, लेकिन कोरोना के आरएनए वायरस होने से उसमें म्युटेशन की आशंका बनी हुई है।

देश में तीसरी लहर की आशंका वाले वायरस के म्युटेशन की शुरू में ही पहचान कर लेने का ढांचा तैयार होने की जानकारी देते हुए सिंह ने कहा, इसके लिए पूरे देश में 277 सेंटिनल सेंटर बनाए जा चुके हैं। हर सेंटर को दो-तीन जिलों से वायरस के सैंपल लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंटसोर्टियम (इंसाकाग) की प्रयोगशालाओं में भेजने की जिम्मदारी सौंपी गई है। राज्यों को पांच जांच लेबोरेटरी और पांच मल्टी स्पेशलियटी अस्पतालों को हर सेंटर से जोड़ने को कहा गया है। हर सेंटिनल सेंटर को हर हफ्ते 15 सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजने को कहा गया है।

कई राज्यों में बढ़ रहा आर नाट : पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आर नाट 1.3 पहुंच गया है और यह बढ़ रहा है। उप्र में 1.1, आंध्र प्रदेश में 1.0 के साथ आर नाट में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। गुजरात, मप्र, गोवा व नागालैंड में 1.0 पर आर नाट स्थिर बना हुआ है। आर नाट वह पैमाना है जिसके जरिये मापा जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने स्वस्थ्य लोगों को संक्रमित कर रहा है।

15 अगस्त को ईस्ट किदवई नगर, रानी बाग और ईस्ट विनोद नगर में 100 फुट की ऊंचाई पर ध्वज लगाएगा लोक निर्माण विभाग। यह परियोजना दिल्ली सरकार के देशभक्ति बजट के तहत पूरी की जा रही है।

अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य तय समय में पूरे हों : सीएम

समीक्षा बैठक ▶ केजरीवाल ने अनधिकृत कालोनियों में चल रहे विकास कार्यों का हाल जाना

कालोनियों में चल रहे विकास कार्यों में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को अनधिकृत कालोनियों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनधिकृत कालोनियों में चल रहे सभी विकास कार्यों को तय समय-सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग इन कालोनियों में चल रहे सभी विकास कार्य पूरी गंभीरता के साथ करें, ताकि तय समयसीमा के अंदर विकास कार्य पूरे किए जा सकें।

इन जगहों पर चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को तय फंड को जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि विकास कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आने पाए। समीक्षा बैठक में सिसोदिया के साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि विभाग को 47 विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली 784 अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से 535 कालोनियों में पहले ही काम शुरू हो चुके हैं। इन 535 कालोनियों में 755 योजनाओं पर कार्य किया जाना है, जिसके लिए प्रशासनिक और व्यय से संबंधित स्वीकृति ली जा चुकी है। विभाग ने 755 योजनाओं में से 441 काम पूरे किए हैं, जबकि शेष में कार्य प्रगति पर है।

अनधिकृत कालोनियों के विकास को लेकर दिल्ली सचिवालय में बैठक लेते अरविंद केजरीवाल। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन व अन्य। सौ. दिल्ली सरकार

पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करा रहा है डीएसआइआइडीसी

डीएसआइआइडीसी अनिधकृत कालोनियों में सड़क और बरसात के पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करा रहा है। वर्तमान में डीएसआइआइडीसी11 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहा है। जिसमें छतरपुर, देवली, बिजवासन, करावल नगर, द्वारका, पालम, जनकपुरी, पटपड़गंज, कृष्णा नगर, रोहिणी, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, किराड़ी, विकासपुरी, गोकुलपुर और बवाना विधानसभा क्षेत्र में कुछ कालोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह इस निगम को 352 अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसमें से 172 कालोनियों में सड़क और बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 69 कालोनियों में कार्य प्रगति पर है और 111 कालोनियों में प्रस्तावित कार्य के लिए फंड जारी कर दिया गया है।

दिल्ली में जल्द शुरू होगा अगला सीरो सर्वे : जैन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली में जल्दी ही अगला सीरो सर्वे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए दूसरी लहर की तुलना में दो गुना आइसीयू बेड बना रही है। जिसमें 12 हजार आइसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। पिछली बार दिल्ली सरकार के पास छह हजार आइसीयू बेड और लगभग 22-23 हजार अन्य बेड थे। इस बार हम पिछली बार से डेढ़ गुना बेड बना रहे हैं। जैन ने आगे कहा कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर अभी 0.10 फीसद से कम है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश की दूसरी और दिल्ली की चौथी कोरोना की लहर में भी 80 फीसद से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए थे। हमने उस समय के सैंपल और और उसके बाद के सैंपलों की सीक्वेंसिंग करवाई है। दोनों में लगभग 80 फीसद डेल्टा वेरिएंट के ही मामले आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले सैंपल आइसीएमआर के पास जाते थे। उन्होंने भी डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि की थी। इसके आलावा दूसरी लहर के दौरान भी डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। हमने यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) अस्पताल में पुराने सैंपल की सीक्वेंसिंग भी करके देखी दूसरी लहर के दौरान लिए गए सैंपल की भी जांच की और यही पाया की 80 फीसद से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के ही थे। ताजा मामलों में भी 80 फीसद से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के ही सामने आ रहे हैं। जैन ने कहा कि देश और दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट आ चुका है।

आक्सीजन से हुई मौत को लेकर केंद्र ने नहीं मांगी रिपोर्ट : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- आक्सीजन की कमी से हुई मौत का सच सामने लाएगी दिल्ली सरकार
- केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार स्वत: सौंपेगी रिपोर्ट

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि उसने राज्यों से आक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा मांगा है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को इस बाबत अब तक कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। उन्होंने कहा कि आक्सीजन की कमी से हुई मौत का सच दिल्ली सरकार सामने लाएगी। इसके लिए सरकार स्वत: अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजेगी।

सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश आक्सीजन संकट से जूझ रहा था। अस्पतालों में लोग आक्सीजन की कमी से मर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से गंभीरता से सवाल किया, लेकिन केंद्र सरकार अब भी असंवेदनशील बनी हुई है।

उपमुख्यमंत्री ने समाचार पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ न्यूज रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों से आक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा मांगा है। अब तक 13 राज्यों ने जबाव दिया है और 12 उनमें से राज्यों ने बोला है कि उनके यहां आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। लेकिन, दिल्ली सरकार को अब तक इससे संबंधित कोई सूचना या चिट्ठी नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में ये झूठ फैला रही है कि राज्य जानकारियां नहीं दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र राज्यों से कुछ पूछ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बहुत पहले ही दिल्ली में आक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में आडिट के लिए जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर उपराज्यपाल द्वारा उसे खारिज कर दिया गया।

उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन का देशभर में जो संकट शुरू हुआ उसका दर्द अभी लोग भूले नहीं हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो आक्सीजन का संकट फिर हो सकता है। केंद्र सरकार इस महामारी को गंभीरता से ले और तीसरी लहर के लिए तैयारियां करे।

मनीष सिसोदिया। फाइल/इंटरनेट मीडिया

न्यूज गैलरी

सेंट स्टीफंस में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू

नई दिल्ली : सेंट स्टीफंस कालेज में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दिल्ली विवि समेत बाहरी छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के तहत फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, स्पैनिश, अरेबिक, परशियन, संस्कृत और उर्दू में दाखिला लिया जा सकेगा। कालेज प्रशासन ने बताया कि आनलाइन दाखिला प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है। छात्र तीन सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की पहली सूची 8 सितंबर, दूसरी 13 सितंबर और तीसरी 17 सितबर को जारी की जाएगी। सूची जारी होने के तीन दिनों के अंदर शुल्क जमा कर छात्र सीट सुनिश्चित करा सकेंगे। कालेज ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों की कक्षाएं अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगी। (जासं)

डीयू स्नातक पाठ्यक्रमों में 1 लाख 81 हजार पंजीकरण

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के नौवें दिन पंजीकरण एक लाख 81 हजार का आंकड़ा पार कर गया। डीयू प्रशासन ने बताया कि मंगलवार रात आठ बजे तक कुल 1,81,152 छात्रों ने पंजीकरण किया। वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक लाख 10 हजार 206 छात्रों ने पंजीकरण किया। एमफिल-पीएचडी में पंजीकरण का आंकड़ा 15,124 तक पहुंच चुका है। डीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से प्रारंभ हुई थी। 31 अगस्त तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। (जासं)

इन्फ्लुएंजा के मरीज बढ़े, स्वाइन फ्लू के मामले भी आए

नई दिल्ली: राजधानी में पिछले कुछ समय से कोरोना का संक्रमण कम है लेकिन अस्पतालों में सामान्य इन्फ्लुएंजा (फ्लू) के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मामले भी देखे जा रहे हैं। दो निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के सात मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। डाक्टर कहते हैं कि स्वाइन फ्लू भी अब सामान्य फ्लू की तरह ही है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लोग सतर्क रहें। फ्लू से बचाव के लिए टीका भी लगवाया जा सकता है। कोरोना और फ्लू के टीके में एक माह का अंतर होना चाहिए। जो लोग कोरोना का टीका ले चुके हैं, वे फ्लू का टीका ले सकते हैं। (राब्यू)

25 से शुरू होंगी कंपार्टमेंट और सुधार परीक्षाएं : सीबीएसई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और सुधार परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दीं। परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होंगी। सीबीएसई के अधिकारियों ने परीक्षा तारीखों को जारी करते हुए कहा कि जो छात्र बोर्ड परिणाम में कम अंक से असंतुष्ट हैं या जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, वह 25 अगस्त से होने वाली परीक्षा के लिए 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच फार्म भर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा जारी तारीख के मुताबिक 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होकर आठ सितंबर तक चलेगी। वहीं, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगी। इन परीक्षाओं का परिणाम 30 सितंबर, 2021 को जारी किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि इन परीक्षाओं में छात्रों को मिले अंक ही अंतिम अंक माने जाएंगे और उनका परिणाम भी इसी आधार पर बनाया जाएगा।

परीक्षा की तारीख

- 10वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षाएं 25 अगस्त से होंगी। 25 अगस्त को पहला पेपर आइटी, 27 अगस्त को अंग्रेजी, 31 अगस्त को विज्ञान, दो सितंबर को हिंदी, तीन सितंबर को होम साइंस, चार सितंबर को विज्ञान (थ्योरी), सात सितंबर को कंप्यूटर और आठ सितंबर को गणित का पेपर होगा ।
- 12वीं के छात्रों का पहला पेपर अंग्रेजी, 26 अगस्त को बिजनेस स्टडीज, 27 अगस्त को राजनीति विज्ञान, 28 अगस्त को शारीरिक शिक्षा, 31 अगस्त को अकाउंट्स, एक सितंबर को अर्थशास्त्र, दो सितंबर को समाज शास्त्र, तीन सितंबर को रसायन विज्ञान, चार सितंबर को मनोविज्ञान, छह सितंबर को जीव विज्ञान, सात सितंबर को हिंदी, आठ सितंबर को कंप्यूटर साइंस (न्यू), नौ सितंबर को भौतिक विज्ञान, 11 सितंबर को भूगोल, 13 सितंबर को गणित, 14 सितंबर को इतिहास और 15 सितंबर को होम साइंस का पेपर होगा।

यति नरसिंहानंद समझ मंदिर में सो रहे साधु पर जानलेवा हमला, गंभीर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना देवी मंदिर की सुरक्षा की पोल एक बार फिर खुल गई है। दो जून को मंदिर परिसर में घुसे दो संदिग्धों के बाद मंगलवार तड़के मंदिर परिसर में सो रहे साधु पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का आरोप है कि यह हमला उन पर किया जाना था, लेकिन गलतफहमी में साधु नरेशानंद पर हमला किया गया। उनके गले व पेट पर गंभीर चोट आई हैं। उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई गई है।

मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के करीबी अनिल यादव ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल से दो टूटे हुए पेपरकटर बरामद किए हैं। घटना के बाद एटीएस, दिल्ली की स्पेशल सेल व एलआइयू समेत अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मामले में अभी जांच की जा रही है।

घायल साधु नरेशानंद को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने घटनास्थल से दो टूटे हुए पेपर कटर किए बरामद

बिहार के समस्तीपुर निवासी साधु नरेशानंद सात अगस्त को डासना देवी मंदिर में आकर रुके थे। वह आठ अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर हुए धरने में शामिल होने के लिए आए थे। इस धरने में शामिल होने के लिए आए पांच अन्य लोग भी डासना देवी मंदिर में आकर रुके थे। सोमवार रात करीब 12 बजे नरेशानंद मंदिर परिसर में बने अतिथि गृह के बाहर रखे तख्त पर सो गए। उनके साथ कौशांबी निवासी मनोज भी उसी तख्त पर सोए हुए थे। सुबह करीब साढ़े तीन बजे किसी ने नरेशानंद पर पेपर कटर से हमला कर दिया। इस हमले में उनके गले व पेट पर गंभीर चोट आई। इसके बाद वह उठकर सामने कमरे में पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बाहर गेट पर तैनात पीएसी जवानों को सूचना देकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। नरेशानंद के बराबर में सो रहे मनोज को इस घटना की भनक नहीं लग पाई। मनोज का कहना है कि उन पर भी हमला किया गया तो उनकी नींद खुली। पेपर कटर के टूट जाने के कारण हमलावर चोट नहीं पहुंचा सके। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के मुताबिक नरेशानंद ने घायल अवस्था में भागते समय बताया था कि हमलावर मंदिर की दीवार फांदकर भागा है।

यति नरसिंहानंद का कहना है कि जिस तख्त पर नरेशानंद सोये हुए थे, अक्सर वह इस तख्त पर विश्राम करते हैं। हमलावर गलतफहमी में नरेशानंद पर हमला कर गए। नरेशानंद भी यति की तरह ही भगवा वस्त्र पहने हुए थे।

नोएडा एयरपोर्ट की निर्माण लागत बढ़ी, एसबीआइ देगा 3,725 करोड़ का कर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निर्माण लागत बढ़कर 5,730 करोड़ रुपये हो गई है। एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण के लिए पूर्व में 4,588 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की वित्तीय औपचारिकताओं को भी पूरा कर फाइनेंशियल क्लोजिंग की गई। निर्माण पर खर्च होने वाली कुल धनराशि का 65 फीसद हिस्सा 3,725 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) कर्ज के रूप में देगा।

शेष धनराशि की व्यवस्था ज्यूरिख करेगी। इसके लिए मंगलवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल), विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच मंगलवार को यमुना प्राधिकरण कार्यालय में समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए।

यमुना प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार को तीनों के बीच सब्सटिट्यूशन व एस्क्रो अकाउंट के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। समझौता पत्र पर नियाल के सीईओ डाक्टर अरुणवीर सिंह, ज्यूरिख के सीईओ क्रिस्टोफ शेलमेन व सीडीओ निकोलस शेंक, एसबीआइ के एजीएम बिजेंद्र सिंह राठौर व निदेशक नागरिक उड्डयन बिशाक जी अय्यर ने हस्ताक्षर किए। प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने सब्सटिट्यूशन और एस्क्रो समझौता पत्र प्रस्तुत किया।

एयरपोर्ट के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं रही है। ज्यूरिख को जमीन के दस्तावेज सौंपकर कब्जा हस्तांतरण की कार्रवाई की जा चुकी है। माना जा रहा है कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधारशिला रख सकते हैं। इसके बाद निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो जाएगा। नियाल का दावा है कि 2024 में एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बदलाव को लेकर जंतर
- मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में लगे थे आपत्तिजनक नारे

भड़काऊ नारेबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर बीते रविवार को जंतर-मंतर स्थित बैंक आफ बड़ौदा के पास आयोजित कार्यक्रम में इन लोगों पर भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है।

इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक नारेबाजी संबंधी वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लेकर पहले अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे उपाध्याय समेत अन्य आरोपितों को जांच में शामिल होने के लिए कनाट प्लेस थाने बुलाया गया। यहां क्राइम ब्रांच की टीम ने उनसे करीब छह घंटे पूछताछ की। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी नई दिल्ली जिला दीपक यादव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों में अश्विनी उपाध्याय के अलावा प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा व विनीत बाजपेयी शामिल हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

पिंकी चौधरी समेत अन्य आरोपितों की तलाश जारी

वायरल वीडियो के आधार पर चार अन्य की भी पहचान कर ली है। इनमें गाजियाबाद का पिंकी चौधरी भी शामिल है। उस पर नारेबाजी करने का आरोप है। पिछले साल जेएनयू में हुए बवाल में पिंकी चौधरी ने हमला करने की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस सभी आरोपितों को तलाश कर रही है।

जंतर-मंतर पर कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं ली थी : डीसीपी दीपक का कहना है कि पुलिस ने जंतर-मंतर पर कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं दी थी। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहले 50 लोग एकत्र हुए बाद में भीड़ बढ़ गई। मुकदमा दर्ज होने पर अश्विनी उपाध्याय की तरफ से डीसीपी को पत्र भेजकर दावा किया गया कि नारेबाजी करने वाले उनके समर्थक नहीं थे। वह उन्हें नहीं जानते हैं। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर रविवार को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वक्ताओं का कहना था कि घटिया व बेकार कानून जब तक खत्म नहीं होंगे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण खत्म नहीं होगा। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो इसी कार्यक्रम में जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई थी।

अंकित गुज्जर मामले में जेलकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- जेल संख्या तीन के चार अधिकारियों को किया गया निलंबित

दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या तीन में बंद अंकित गुज्जर की पिटाई से हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। संभावना है कि जल्द ही पुलिस अधिकारी आरोपित जेलकर्मियों से पूछताछ कर छानबीन आगे बढ़ाएंगे। उधर जेल प्रशासन ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में एक उपाधीक्षक, दो सहायक अधीक्षक व एक वार्डर शामिल हैं।

दिल्ली के थाने में दर्ज मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से नरेंद्र मीणा पर एक लाख रुपये रिश्वत नहीं देने पर अंकित को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि 50 हजार का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन शेष रकम के लिए अंकित को परेशान किया जाता था। पीड़ित पक्ष का दावा है कि दो अगस्त को अंकित ने फोन पर जेल में परेशान किए जाने की बात स्वजन को बताई थी। उसने कहा था कि उसे जेलकर्मी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप यह भी है कि अंकित को जब अस्पताल ले जाया गया, तब वहां भी उसका सही तरीके से उपचार नहीं कराया गया। एफआइआर में पुलिस की ओर से कहा गया है कि एम्स में चिकित्सकों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें चोट की वजह से अंदरूनी हिस्से में खून के रिसाव को मौत का कारण बताया गया। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि जब जेलकर्मियों से पुलिसकर्मियों ने इस घटना के बाबत सवाल पूछे तो कहा गया कि अंकित की सेल की तलाशी के दौरान एक डाटा केबल व चाकू मिला था। इसके बाद अंकित व उसके साथ बंद दो अन्य कैदियों को दूसरी जगह भेजा जाना था, लेकिन इस दौरान तीनों ने जेलकर्मियों के साथ हाथापाई की, जिसमें जेलकर्मियों को भी चोटें आईं । कहा गया कि चार अगस्त को अंकित सेल में अचेत मिला। उसे तुरंत तिहाड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सेल में बंद गुरप्रीत और गुरजीत भी घायल मिले थे।

तैयारी पूरी

ट्रायल के रूप में अभी दो रूटों पर चलेंगी वातानुकूलित 25 फीडर बसें, ये बसें कैशलेस और कंडक्टरलेस होंगी, मेट्रो के स्मार्ट कार्ड या मेट्रो डीटीसी स्मार्ट कार्ड के जरिये यात्री किराया भुगतान कर सकेंगे

कल से चलेंगी मेट्रो फीडर ई-बसें, भुगतान भी होगा कैशलेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) गुरुवार से सड़कों पर 25 लो फ्लोर फीडर ई-बसें (इलेक्ट्रिक बसें) उतारेगा, जो वातानुकूलित होंगी। ट्रायल के रूप में अभी पूर्वी दिल्ली के दो रूटों पर 25 फीडर बसों का परिचालन होगा। ये बसें कैशलेस और कंडक्टरलेस होंगी। मेट्रो के स्मार्ट कार्ड या मेट्रो डीटीसी स्मार्ट कार्ड के जरिये यात्री किराया भुगतान कर सकेंगे। इसलिए इन बसों में सिर्फ स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्री ही सफर कर पाएंगे। इससे मेट्रो स्टेशन से गंतव्य तक का सफर भी आरामदायक हो सकेगा। इन फीडर बसों में सामान्य यात्रियों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

डीएमआरसी अक्टूबर के अंत तक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में 10 रूटों पर 100 मेट्रो फीडर ई-बसों का परिचालन करेगा। इसका मकसद मेट्रो स्टेशन से गंतव्य तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करना है।

डीएमआरसी की लो फ्लोर फीडर ई-बसें। सौ. मेट्रो

किराया

दूरी	किराया
चार किलोमीटर तक	10 रुपये
चार से आठ किलोमीटर	15 रुपये
12 किलोमीटर	25 रुपये

इन बसों में 24 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी और 14 मेट्रो स्टेशनों तक आवागमन की सुविधा बेहतर हो जाएगी।

डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा कि यह अत्याधुनिक बसें सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस सिस्टम से लैस होंगी। इसलिए यात्रियों को बस के अंदर हर बस स्टैंड की सूचना भी मिल सकेगी। बसों को दिव्यांग व बुजुर्गों के अनुकूल बनाया गया है। इसलिए रैंप के जरिये व्हील चेयर से वे बस में सवार हो सकें। शास्त्री पार्क व मजलिस पार्क में इन बसों के लिए डिपो बनाया गया है। उन डिपो में बसों की निगरानी के लिए केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस निगरानी केंद्र से परिचालन के दौरान बसों पर नजर रखी जा सकेगी। इन बसों में दूरी के अनुसार 10 से 25 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इन फीडर बसों के चार्जिंग के लिए 2.5 मेगावाट बिजली का कनेक्शन दिया गया है।

मेट्रो की तरह ही आटोमेटिक होगा प्रवेश व निकास : इन फीडर बसों में कंडक्टर नहीं होंगे। मेट्रो की तरह किराया भुगतान के लिए बस के अंदर प्रवेश व निकास गेट के पास टर्नस्टाइल (घूमने वाला दरवाजा) लगाया गया है। स्मार्ट कार्ड टच करने पर यह गेट स्वत: खुलेगा और बंद होगा। इसलिए इन फीडर बसों में मेट्रो की तरह ही प्रवेश व निकास की सुविधा होगी। किराये के लिए नकद राशि नहीं ली जाएगी। डीएमआरसी का कहना है कि इन फीडर बसों में सिर्फ मेट्रो के यात्रियों को सफर करने की सुविधा मिलेगी। इसलिए मेट्रो स्टेशन से चलने वाली फीडर बसों से यात्री चिन्हित बस स्टैंड पर सिर्फ उतर सकेंगे लेकिन यात्री बस में चढ़ नहीं पाएंगे।

मेट्रो स्टेशन जाने वाली फीडर बसों से बीच में नहीं उतर सकेंगे यात्री : मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली फीडर बसों में सवार यात्री सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर ही उतर सकेंगे। बीच के किसी बस स्टैंड पर नहीं उतर पाएंगे। स्टैंड से यात्री सिर्फ बस में सवार हो सकेंगे।

ई-नीलामी से सीएनजी स्टेशन के लिए आवंटित होगी जमीन

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

आने वाले समय में दिल्ली में बड़े स्तर पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) के स्टेशन दिखाई देंगे। सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ा फैसला किया है। अब ई-नीलामी के माध्यम से सीएनजी स्टेशन के लिए जगह का आवंटन किया जाएगा। सीएनजी स्टेशन प्लाटों के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और दक्षता बढ़ाने के लिए डीडीए ने इनकी ई-नीलामी की नीति को अनुमोदित किया है। मंगलवार को आयोजित डीडीए बोर्ड बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस निर्णय को स्वीकृति दे दी।

अब डीडीए ई-नीलामी के माध्यम से सीएनजी स्टेशन के लिए और अपने आशय-पत्र धारकों को स्टेशन साइटों का आवंटन करेगा। साथ ही राजधानी में ग्रीन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने जमीन की लाइसेंस फीस (आरक्षित फीस) भी मार्केट प्राइस से 50 फीसद कम रखने का निर्णय लिया है। यह लाइसेंस फीस पड़ोसी राज्यों में देय शुल्क की तुलना में काफी कम है। उपराज्यपाल एवं डीडीए के चेयरमैन अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की आनलाइन बैठक में नई नीति के तहत यह भी निर्णय लिया गया कि लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष होगी और इसका 30 वर्षों तक नवीनीकरण किया जा सकेगा। लाइसेंस फीस में वृद्धि निर्धारित दर पर होगी। इससे पहले भूमि पांच वर्ष के लिए आवंटित की गई थी और दरों में वृद्धि भी निश्चित नहीं थी क्योंकि यह औसत नीलामी दरों से संबंधित थी। बैठक में मल्टी लेवल पार्किंग के मानदंडों को भी अनुमोदित किया गया।

1989 से लेकर पांच अगस्त, 2019 तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 5,886 सुरक्षाकर्मी मारे गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू-कश्मीर सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवादी हिंसा से प्रभावित रहा है।

सभी पार्टियों ने ओबीसी बिल के बहाने अपने वोट बैंक पर लगाया दांव

पैंतरेबाजी ▶ कांग्रेस ने आरक्षण सीमा 50 फीसद से बढ़ाने की पैरोकारी की

सपा, जदयू, बसपा सरीखे दलों ने जातीय जनगणना कराने की उठाई मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यों को ओबीसी की पहचान कर सूची बनाने का अधिकार देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए आरक्षण की पैरोकारी में एक-दूसरे को पछाड़ने का जमकर दांव चला। इस बिल को पारित कराने के लिए संसद के संग्राम को विराम देने वाली कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करते हुए दो कदम आगे बढ़कर आरक्षण की मौजूदा 50 फीसद की अधिकतम सीमा को बढ़ाए जाने की पैरोकारी की तो जदयू, सपा, बसपा से लेकर द्रमुक जैसे दलों ने भी अपनी राजनीति को साधते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उठाई।

पेगासस पर तीन हफ्ते से जारी घमासान के बीच तमाम पार्टियों ने चाहे अपनी सियासी वोट बैंक को साधने के लिए भरपूर दांव लगाया, मगर इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की एकजुटता भी बेमिसाल रही।

लोकसभा में ओबीसी सूची से संबंधित इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले तो पेगासस जासूसी के मुद्दे को उठाया। इसके बाद बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की चूक से राज्यों का ओबीसी सूची का अधिकार छिन गया था और इस विधेयक के जरिये सरकार अपनी गलती को सुधार रही है। अब समय आ गया है कि सरकार आरक्षण की मौजूदा अधिकतम 50 फीसद की सीमा की समीक्षा कर इसे बढ़ाने के रास्ते पर विचार करे। अधीर रंजन ने कहा कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी फैसले की कानूनी बंदिश की बाधा विधायी रूप से कैसे दूर की जा सकती है।

सपा नेता अखिलेश यादव ने भी बिल का समर्थन करते हुए जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उठाई और कहा कि केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना नहीं कराई तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हम जाति गणना कराएंगे। उन्होंने भी अधीर रंजन की तरह आरक्षण की मौजूदा 50 फीसद की अधिकतम सीमा को खत्म कर इसे बढ़ाने की मांग की।

जदयू के राजीव रंजन सिंह ललन ने सरकार की नीयत को सही बताया, लेकिन जातीय जनगणना की हिमायत करते हुए ललन ने भी सरकार से इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा। बसपा के रितेश पांडेय ने भी इसी तरह की राय जाहिर की। द्रमुक के टीआर बालू ने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए आरक्षण की 50 फीसद सीमा खत्म कर इसे बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। शिवसेना ने भी इसका समर्थन किया और मराठा आरक्षण पर अपनी सियासत साधने के लिए पार्टी नेता विनायक दामोदर ने तो 50 फीसद आरक्षण सीमा खत्म करने के लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी दे दिया। हालांकि, उनका संशोधन प्रस्ताव बहुमत से खारिज हो गया। माकपा नेता एएम आरिफ ने बहस में हिस्सा लेते हुए बिल का समर्थन तो किया मगर भाजपा सरकार पर उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव को ध्यान में रखकर विधेयक को लाने का आरोप लगाया। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने चर्चा में हिस्सा तो लिया, मगर विधेयक पर बात कहने के बजाय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया।

होसबाले ने कहा, आरएसएस आरक्षण का प्रबल समर्थक

- संघ के सरकार्यवाह ने कहा, जब तक समाज में असमानता है तब तक जारी रहना चाहिए आरक्षण
- देश के इतिहास को पिछड़े और दलितों के इतिहास के बगैर अधूरा बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघ आरक्षण का प्रबल समर्थक है और जब तक समाज का एक विशेष वर्ग असमानता का अनुभव करता है तब तक इसे जारी रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास पिछड़े और दलितों के इतिहास के बगैर अधूरा है। वे सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने आरक्षण को सकारात्मक कार्रवाई का जरिया भी बताया। 'मेकर्स आफ माडर्न दलित हिस्ट्री' शीर्षक वाली एक पुस्तक के विमोचन के लिए इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में होसबाले ने यह बात कही।

आरक्षण की बात करते हुए होसबाले ने दो-टूक कहा कि वह और उनका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 'आरक्षण के पुरजोर समर्थक हैं। सौहार्द और सामाजिक न्याय हमारे लिए राजनीतिक रणनीतियां नहीं हैं। ये दोनों हमारे लिए आस्था की वस्तु हैं।' संघ के सरकार्यवाह ने भारत के लिए आरक्षण को एक 'ऐतिहासिक जरूरत' बताया और कहा कि यह तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक समाज के एक वर्ग विशेष को असमानता का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण और समन्वय (समाज के सभी वर्गों के बीच) साथ-साथ चलना चाहिए। होसबाले ने यह भी कहा कि सामाजिक बदलाव का नेतृत्व करने वाली विभूतियों को 'दलित नेता' कहना अनुचित होगा, क्योंकि वे पूरे समाज के नेता थे। उन्होंने ने कहा, 'जब हम समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से आरक्षण जैसे कुछ पहलू सामने आते हैं। मेरा संगठन और मैं दशकों से आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। जब कई परिसरों में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब हमने पटना में आरक्षण के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया और एक संगोष्ठी आयोजित की थी।'

दत्तात्रेय होसबाले। जागरण आर्काइव

सालिसिटर जनरल ने मांगा वक्त

प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि उन्हें याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के संबंध में सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस पर पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की। एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील सीयू सिंह ने पीठ से कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इस पीठ ने कहा कि इस पर सोमवार को वह विचार करेगी, तब तक इंतजार करें।

कई याचिकाएं की गई हैं दाखिल

सुप्रीम कोर्ट इजराइल के जासूसी साफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले की स्वतंत्र जांच कराने के अनुरोध वाली अनेक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें से एक याचिका 'एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया' ने दाखिल की है। गौरतलब है कि पांच अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि पेगासस से जासूसी कराए जाने संबंधी आरोप 'गंभीर प्रकृति' के हैं, अगर इससे संबंधित खबरें सही हैं तो।

पीएम ने रास में मतदान के दौरान अनुपस्थित सदस्यों की सूची मांगी

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रेट्र

- विपक्षी सांसदों ने अधिकरण सुधार विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के समक्ष भेजने का रखा था प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री से उन सदस्यों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है, जो सोमवार को राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित थे। विपक्ष के कई सांसदों ने अधिकरण सुधार विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से उन लोगों की सूची देने करने को कहा जो मतदान के दौरान सदन से अनुपस्थित थे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ओलिंपिक पदक विजेताओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। उन्होंने भाजपा सांसदों से क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी अपने क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। पीएम ने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करें और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें। बैठक के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलिंपिक में भारत के प्रदर्शन का विस्तृत ब्योरा पेश किया। इसके बाद जुलाई तक खेल मंत्रालय का काम देख रहे मौजूदा विधि मंत्री किरण रिजिजू ने खेलों को लेकर की गई तैयारियों से लोगों को अवगत कराया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बारे में विचार रखे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की सोमवार को अध्यक्षता की।

'जन आशीर्वाद' यात्रा पर 16 से निकलेंगे 39 नए केंद्रीय मंत्री : भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले नए और प्रोन्नत किए गए 39 मंत्री 16 अगस्त से 'जन आशीर्वाद' यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान भाजपा नेता 19 राज्यों, 265 जिलों, 212 लोकसभा क्षेत्रों तथा 19,567 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे। वे लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों, खासकर गरीबों के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे।

- लोगों को सरकार की उपलब्धियों और गरीबों के लिए किए गए कार्यों की देंगे जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिपरिषद के विस्तार में महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर ध्यान दिए जाने के बाद पार्टी ने घोषणा की थी कि नए मंत्री लोगों तक पहुंचने के लिए यात्रा करेंगे। इस यात्रा के समन्वयक व भाजपा के महासचिव तरुण चुघ ने संवाददाताओं को बताया कि राज्यमंत्री 16-18 अगस्त तक, जबकि कैबिनेट मंत्री 19-21 तक यात्रा करेंगे। पार्टी ने सभी नए मंत्रियों को कहा है कि वे जिन राज्यों के रहने वाले हैं उनके तीन लोकसभा क्षेत्रों व चार जिलों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पीएम मोदी ने सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया है।

आइएएनएस के अनुसार, इस यात्रा की योजना भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इसके लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम. चुबा, महासचिव तरुण चुघ, सचिव अरविंद मेनन, विनोद सोनकर, सुनील देवधर, सत्या कुमार व पंकजा मुंडे शामिल हैं।

'स्थानीय भाषाओं की सखी के रूप में हो हिंदी का विकास'

- केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती में राजभाषा का बड़ा योगदान

नई दिल्ली, जेएनएन : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसमें राजभाषा हिंदी का विकास सहज रूप से स्थानीय भाषाओं की सखी के रूप में हो। हिंदी अगर कालबाह्य नहीं हुई है तो इसका यही कारण है कि हमने इसे कभी थोपने का प्रयास नहीं किया।

संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा, 'बहुत हर्ष का विषय है कि हमने समिति के 10वें प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के पास भेजने की मंजूरी दे दी है। हम समय लेकर उनके पास जाएंगे।' उन्होंने कहा कि हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। अगर कोई मूल्यांकन करे तो वह कह सकता है कि इन वर्षों में हमने लोकतंत्र की जड़ों को गांव व कस्बों तक पहुंचाया है। हमारा पथ सही व लक्ष्य की ओर है और हम लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इसमें हमारी स्थानीय भाषाओं और विशेषरूप से राजभाषा हिंदी का बड़ा योगदान है। कई देशों की लिपियों और भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि आजादी के बाद हमने बोलियों और भाषाओं को संरक्षित व संवर्धित किया है। स्थानीय भाषाओं व राजभाषा ने देश को एक करने का काम किया है।

शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तकनीकी व औषधीय शिक्षा का भी संपूर्ण अभ्यासक्रम राजभाषा में अनुदित कराने का काम शुरू किया गया है। इसके बाद हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी इंजीनियर व डाक्टर बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। न्याय व्यवस्था में भी हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए न्यायविदों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। टोक्यो ओलिंपिक में पहली बार हिंदी में कमेंट्री की व्यवस्था की गई, यह हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है।' बैठक में गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा व संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक को संबोधित किया। प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद होने के बाद दो बाहरी लोगों ने संपत्ति खरीदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद से केवल दो बाहरी लोगों ने दो संपत्तियां खरीदी हैं। यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दी। सरकार से यह सवाल किया गया था कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद क्या देश के अन्य राज्यों के लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के बाहर के दो लोगों ने अगस्त, 2019 से अब तक दो संपत्तियां खरीदी हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय सरकार और अन्य राज्यों के लोगों को किसी कठिनाई या बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, राय ने कहा, सरकार को ऐसी कोई घटना नहीं बताई गई है।

राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अभी कोई फैसला नहीं : केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने पूरे देश के लिए राष्ट्रीय भारतीय नागरिक पंजिका (एनआरआइसी) तैयार करने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021 की जनगणना के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का फैसला किया है।

राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआइसी) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तक केवल असम में ही एनआइआरसी अपडेट किया गया है। 2019 में जब एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई, तो 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को इससे बाहर कर दिया गया, जिसके बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया।

लोकसभा प्रश्नोत्तर

केंद्र ने आइएसआइएस को आतंकी संगठन करार दिया

नई दिल्ली, एएनआइ : राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने इस्लामिक स्टेट आफ इराक एंड लेवेंट (आइएसआइएल) या इस्लामिक स्टेट आफ इराक एंड सीरिया (आइएसआइएस) उर्फ दाएश को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया है। राय ने कहा कि केरल सहित विभिन्न राज्यों के लोगों के इस संगठन में शामिल होने के कुछ उदाहरण केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और राज्य पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज कर कार्रवाई की है।

देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 2,15,504

नई दिल्ली, एएनआइ : राय ने लोकसभा को सूचित किया कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 2,15,504 है। एक जनवरी, 2020 तक महिला पुलिस कर्मियों की तादात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,91,488 पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या की 10.30 फीसद है।

'रोहिंग्या मुसलमान अवैध गतिविधियों में लिप्त'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार के पास रिपोर्ट है कि प्रवासी रोहिंग्या मुसलमान अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। लोकसभा में नित्यानंद राय ने बताया कि वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में आए रोहिंग्या प्रवासियों के अवैध गतिविधियों में शामिल होने की खबरें हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं कि वे अवैध प्रवासियों की तत्काल पहचान के लिए उचित कदम उठाने के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील बनाएं, कानून के प्रविधानों के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर उनको प्रतिबंधित करें।

देश में बढ़ा साइबर क्राइम, 18 राज्यों में फोरेंसिक लैब

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों के साथ, 18 राज्यों को अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण लैब मिल गई हैं। गृह मंत्रालय की मदद से स्थापित इन लैब ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सहित साइबर अपराध के हजारों मामलों को सुलझाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद की है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, 2017, 2018 और 2019 में दर्ज साइबर क्राइम के मामले क्रमशः 21,796, 27,248 और 44,546 थे। इस अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66एफ के तहत दर्ज साइबर आतंकवाद के 46 मामले शामिल हैं।

चुनाव लड़ने वाली 10 पार्टियों में से आठ पर लगाया जुर्माना

प्रथम पृष्ठ से आगे

बिहार विधानसभा चुनाव में 10 मान्यता प्राप्त दलों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से आठ पर जुर्माना लगाया गया है। वैसे कोर्ट ने दोषी नौ दलों को ठहराया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। हालांकि इस पार्टी का विलय अब जदयू में हो चुका है। यह अलग से दल नहीं रह गया है।

बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसे कोर्ट ने अवमानना का दोषी नहीं ठहराया है। कोर्ट उसकी ओर से दो उम्मीदवारों का ब्योरा नहीं देने के बारे में दी गई सफाई से संतुष्ट है। लेकिन साथ ही बसपा को कोर्ट ने सावधान किया है कि वह सिर्फ आदेश पर जुबानी जमाखर्च न करे, बल्कि आदेश का पूरी तरह पालन करे।

अदालत ने कहा, शक्तियों के बंटवारे को देखते हुए बंधे हैं हाथ : कोर्ट ने कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दिन-प्रतिदिन अपराधीकरण बढ़ रहा है। यह अदालत एक बार फिर कानून निर्माताओं से अपील करती है कि वे उठें और जरूरी संशोधन करें, ताकि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश प्रतिबंधित हो। राजनीतिक दलों ने गहरी नींद से जागने से इन्कार कर दिया है। लेकिन संविधान में किए गए शक्तियों के बंटवारे को देखते हुए उसके हाथ बंधे हैं। वह विधायिका के तय कार्यक्षेत्र में नहीं जा सकती। वह सिर्फ कानून निर्माताओं से अपील कर सकती है और उम्मीद करती है कि वे जल्दी ही जागेंगे और राजनीति के अपराधीकरण को दूर करने के लिए बड़ी कार्रवाई करेंगे।

असम-मिजोरम सीमा पर घटी घटना से पीएम व्यथित : सरमा

नई दिल्ली, प्रेट्र : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया है कि असम-मिजोरम सीमा पर हालिया हिंसा जैसी घटनाएं देश को पीड़ा देती हैं।

सरमा ने यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वे 26 जुलाई की घटना के बाद से प्रधानमंत्री के नियमित संपर्क में हैं और उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा ऐसा होने से देश को पीड़ा होती है। उल्लेखनीय है सीमा पर संघर्ष के बाद मिजोरम पुलिस की गोलीबारी में असम पुलिस के पांच जवानों और एक नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक घायल पुलिसकर्मी ने बाद में दम तोड़ दिया था। सरमा ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें अब एक-दूसरे से बात कर रही हैं और अमन-चैन के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक या दो इंच जमीन के लिए रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। आखिर ये भारतीय जमीन है। उन्होंने कहा कि विवादित क्षेत्रों के मुद्दे को हल करने के लिए, असम और मेघालय दोनों पांच सिद्धांतों - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रशासनिक सुविधा, संवैधानिक सीमा की निकटता और सबसे महत्वपूर्ण लोगों की इच्छा पर जाने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि असम-नगालैंड सीमा के बारे में भी निपटान की प्रक्रिया चल रही है। नगालैंड की वाणिज्यिक राजधानी दीमापुर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दीमापुर नगालैंड का क्षेत्र है और वहां रहने वाले लोग नगा हैं।

744 जिलों में आयोजित होगा 'फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0'

नई दिल्ली, आइएएनएस : 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर 13 अगस्त को 'फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0' का आगाज करेंगे। मंत्रालय ने 7.50 करोड़ युवाओं व लोगों तक पहुंचने तथा उन्हें इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है।

खेल सचिव उषा शर्मा ने बताया कि पहले दिन देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर 75 शारीरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दो अक्टूबर तक हर हफ्ते 75 जिलों और उन सभी के 75-75 गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि समग्र रूप में 744 जिलों और उन सभी के 75-75 गांवों के अलावा देशभर के 30 हजार शैक्षणिक संस्थानों में भी यह कार्यक्रम आयोजित होगा।

बदलाव

ज्योतिरादित्य सिंधिया को 27 सफदरजंग रोड का बंगला आवंटित, हर्षवर्धन, निशंक, सदानंद गौड़ा और जावडेकर को छोड़ना पड़ेगा बंगला

कैबिनेट से हटे मंत्रियों को बंगला छोड़ने का नोटिस

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए कैबिनेट मंत्रियों को अपना मौजूदा बंगला छोड़ने को कहा गया है। इसके बदले में उन्हें दूसरा बंगला चुनने को कह दिया गया है। नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 27 सफदरजंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। इस बंगले में फिलहाल पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावडेकर को बंगला छोड़ने का नोटिस भेज दिया गया है। रामविलास पासवान के स्वजन को बंगला खाली करने को कहा गया है। इसमें फिलहाल सांसद चिराग पासवान अपनी मां के साथ रहते हैं।

कैबिनेट मंत्रियों को लुटियंस जोन में टाइप-आठ का बंगला आवंटित किया जाता है, जो लगभग तीन एकड़ में तैयार शानदार आठ कमरों का होता है। सभी सुख सुविधाओं से लैस इन बंगलों को कैबिनेट मंत्री पद से हटते ही खाली करने का प्रविधान है। शहरी विकास मंत्रालय का एस्टेट डिपार्टमेंट इनका रखरखाव करता है, जबकि इन बंगलों का आवंटन संसद की आवासीय समिति करती है। डाक्टर हर्षवर्धन के नाम आठ, 30 जनवरी मार्ग का बंगला है, जबकि रमेश पोखरियाल निशंक को 27 सफदरजंग रोड का बंगला मिला है। यह बंगला पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के नाम लंबे समय तक आवंटित रहा। इस बंगले से उनके बेटे व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत लगाव है। सूत्रों के मुताबिक, टाइप-आठ के इस बंगले का आवंटन सिंधिया के नाम हो गया है। निशंक को टाइप-सात के बंगले में जाने का विकल्प दिया गया है, जिसके वह हकदार हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। उन्होंने अपना बंगला छोड़ भी दिया है। 12, जनपथ रोड वाले पासवान के बंगले में कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री ही रह सकता है। वरिष्ठता के हिसाब से चिराग पासवान उसके योग्य नहीं हैं। छह, कुशक रोड वाले बंगले में प्रकाश जावडेकर रहते हैं, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले ही टाइप-सात के बंगले में रहते हैं, जिसके वह हकदार हैं। डीबी सदानंद गौड़ा को एक, त्यागराज मार्ग का टाइप-आठ का बंगला मिला हुआ है, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा।

शहरी विकास मंत्रालय की ओर से पहला नोटिस जारी हो चुका है, जबकि जल्दी ही दूसरा नोटिस भी जारी किया जा सकता है। उन्हें बंगला खाली कर टाइप-सात के बंगलों में जाने को कहा गया है। टाइप-आठ के इन बंगलों को दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के नाम आवंटन भी शुरू कर दिया गया है। बंगलों को खाली करने में होने वाली अनपेक्षित देरी पर इन सांसदों को न्यूनतम किराये का भुगतान भी करना पड़ सकता है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि बंगलों के आवंटन अथवा छोड़ने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाती है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावडेकर को बंगला छोड़ने का नोटिस भेज दिया गया है। जागरण आर्काइव

कह के रहेंगे

माधव जोशी

89 बहुमुखी खेल आपदा आश्रय स्थल एवं चिकित्सालय उपयोगी इनडोर स्टेडियम बनेंगे ओडिशा में। इसके लिए प्रदेश सरकार 693.35 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

चुनावी अभियान से पहले जनता से फीडबैक ले रहे प्रधानमंत्री

केंद्र, राज्य सरकार और विधायकों के कामकाज पर ली जा ही है राय

लोगों से विपक्षी एकता के बारे में भी पूछा जा रहा सवाल

आशुतोष झा, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के आगामी चुनाव से पहले हर दल ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान में जाने से पहले खुद जनता से ही फीडबैक लेना शुरू कर दिया है, ताकि हर राज्य ही नहीं वहां के लोकप्रिय नेताओं, वहां की समस्या, स्थानीय विधायक, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर संतोष व असंतोष तक हर मुद्दे पर जमीनी और बेबाक जानकारी मिल सके। जाहिर है कि यह फीडबैक चुनावी अभियान के मुद्दे से लेकर उम्मीदवार और भावी मुख्यमंत्री तक के बारे में राय बनाने में मदद करेगा।

जनता से सीधे संपर्क के अलग-अलग माध्यमों को लेकर हमेशा सक्रिय रहे प्रधानमंत्री मोदी के नमो एप पर एक नया फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के बारे में लोगों की राय जानी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति राज्य और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण आर्काइव

विधानसभा क्षेत्र चुनने के बाद आगे बढ़ सकता है। इसमें कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधन से लेकर शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान कल्याण जैसे मुद्दे शामिल हैं।

जनता के लिए यह विकल्प है कि वह इन मुद्दों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के बारे में राय दे सकता है। जाहिर तौर पर यह सर्वे बताएगा कि किसी बात पर नाराजगी है तो किस स्तर पर। इसे बहुत खराब से लेकर अति उत्तम तक के मापदंड पर अंक दिया जा सकता है। सर्वे यहीं नहीं रुक रहा है, बल्कि यह भी पूछता है कि क्या विपक्षी एकता का उनके विधानसभा क्षेत्र पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वह मानते हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रहने से विकास में सहायता होती है? क्या भविष्य में वह अपने राज्य के विकास को लेकर आशावान हैं? भाजपा में जनता की नाराजगी दूर करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे विधायकों का टिकट काटने की परंपरा रही है। जाहिर तौर पार्टी के स्तर पर भी सर्वे होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। सर्वे में विधायकों के कामकाज, जनता की उन तक पहुंच, उनकी लोकप्रियता के बारे में सवाल हैं। राजनीति के केंद्र में जाति रही है। चुनाव के नजदीक आते ही यह फिर से तेज होने लगी है और विभिन्न दलों की ओर से जाति आधारित जनगणना की मांग होने लगी है। लिहाजा इसी सर्वे में यह भी पूछा गया है कि वह जाति के आधार पर वोट देंगे, धर्म के आधार पर या फिर विकास के लिए। इसी तरह का सर्वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और नोटबंदी के बाद भी किया गया था। ध्यान रहे कि इसी एप के जरिये प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए भी लोगों की अपेक्षाओं का आकलन करते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि वह आगामी चुनाव को अगले पायदान पर ले जा चुके हैं।

जदयू अध्यक्ष ने कहा, जातीय जनगणना के बिना ओबीसी के साथ नहीं होगा इंसाफ

राज्य ब्यूरो, पटना : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि बगैर जातीय जनगणना के देश की ओबीसी आबादी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। वह मंगलवार को लोकसभा में संविधान के 127वें संशोधन के पक्ष में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस संशोधन का इसलिए समर्थन कर रही है, क्योंकि ओबीसी के विकास के मामले में सरकार की नीयत साफ है। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन किया गया था। वह 102वां संशोधन था।

ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारी समझ से यह निहायत जरूरी है। 1931 के बाद किसी जनगणना में जातियों की गणना नहीं की गई। इस अंतराल में सबकी आबादी बढ़ी है। समाज के विभिन्न तबके के लोग जातियों का जो आंकड़ा दे रहे हैं, उसे जोड़ दें तो देश की आबादी तीन गुना बढ़ जाएगी।

सही आंकड़ा जानने के लिए यह जरूरी उपक्रम : उन्होंने कहा कि यह भ्रम है कि जातीय जनगणना से समाज में भेदभाव बढ़ेगा। सच यह है कि समाज का हरेक तबका इसके पक्ष में है। जातीय गणना भी सबके हक में है। एक बार यह हो ही जाए, ताकि विभिन्न जातियों की संख्या के बारे सही आंकड़ा मिल जाए।

सोनिया ने दी पंजाब कैबिनेट में फेरबदल को मंजूरी, नए चेहरों को मिल सकता है मौका

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- राजकुमार वेरका और राणा केपी सिंह को मिल सकती है कैबिनेट में जगह
- कैप्टन मिले सोनिया से, सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम पर हुई चर्चा

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा की। सोनिया गांधी ने कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद कैप्टन विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा को लेकर संतुष्ट है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके दी।

कांग्रेस के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार, कैप्टन ने सोनिया के साथ कैबिनेट में नए चेहरों को लाने की बात भी की। क्योंकि कैप्टन न केवल एक खाली सीट को भरना चाहते हैं बल्कि कैबिनेट में दो नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार, वह कैबिनेट में दलित मंत्री को उप मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं ताकि दलित समुदाय में कांग्रेस को लेकर सकारात्मक संदेश जा सके।

सूत्रों के अनुसार, सोनिया की मंजूरी मिलने के बाद अब अगले सप्ताह तक कैबिनेट में फेरबदल संभव है। कांग्रेस में कैबिनेट फेरबदल की लंबे समय से चर्चा चल रही है। जिसका मुख्य कारण कैबिनेट में एक सीट का खाली होना भी है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब मुख्यमंत्री कैबिनेट में फेरबदल करना चाहते हैं। पार्टी के उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में दलित कोटे से राजकुमार वेरका और हिंदू कोटे से विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह भी शामिल हो सकते है। पिछले दिनों राणा केपी सिंह ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी और इसके बाद वह काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे थे।

सिद्धू के सरकार के खिलाफ बयान को लेकर भी हुई चर्चा: सूत्रों के अनुसार, कैप्टन ने सोनिया गांधी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर भी चर्चा की। क्योंकि प्रदेश की कमान संभालने के बाद गाहे-बगाहे सिद्धू अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। कैप्टन ने सोनिया गांधी से यह भी कहा कि इससे पार्टी की छवि खराब होती है। गौरतलब है कि इन दिनों पंजाब कांग्रेस में धड़ेबंदी चरम पर है। सोमवार को जब कैप्टन सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे तो कांग्रेस के पांच मंत्रियों और तीन विधायकों ने पत्र लिखकर सोनिया गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था। इन मंत्रियों में तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और रजिया सुल्ताना शामिल है। उन्होंने इश पत्र में यह भी कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के 18 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करने को लेकर गंभीर नहीं है।

कैप्टन ने गृह मंत्री शाह से मांगी केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों की 25 कंपनियां

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- कहा, पंजाब में सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध करवाए जाएं एंटी ड्रोन उपकरण

पाकिस्तान से राज्य की सुरक्षा को बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कैप्टन ने मांग की कि पंजाब को केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों की 25 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को ड्रोन नष्ट करने वाले उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं।

कैप्टन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान की आइएसआइ एजेंसी की गतिविधियां बढ़ रही हैं। राज्य में हथियारों, हैंड ग्रेनेड और आईईडी की बड़ी स्तर पर घुसपैठ का हवाला देते हुए उन्होंने शाह को बताया कि सुरक्षा की स्थिति बहुत भयानक है। इसे देखते हुए केंद्र को तुरंत दखल देना चाहिए।

कैप्टन ने शाह से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, बठिंडा, फगवाड़ा और मोगा के लिए केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों की मांग की। केंद्रीय व प्रांतीय एजेंसियों और गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ में सामने आईं जानकारियों का हवाला देते हुए कैप्टन ने कहा कि रेलों, बसों और मंदिरों के अलावा प्रमुख किसान नेताओं (पांच किसान नेता जो सुरक्षा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एएनआइ

की पेशकश ठुकरा चुके हैं), पंजाब से संबंधित आरएसएस शाखाओं व कार्यालयों, भाजपा व शिव सेना नेताओं, डेरा, निरंकारी भवन सहित जलसों पर संभावित खतरा बना हुआ है। उन्होंने सीमा पार से भेजी गई आरडीएक्स, अन्य विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, टाइमर उपकरण, अत्याधुनिक लैब में बनाए गए टिफिन बम की जानकारी भी दी। कैप्टन ने कहा कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च में संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तानी एजेंसी आइएसआइ बहुत से आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों पर आतंकवादी कार्यवाही को अंजाम देने के लिए दबाव बना रही है।

कैप्टन ने कहा कि भारत-पाक सीमा पर कंटीली तार आइएसआइ और पाकिस्तान आधारित खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों की ओर से विकसित विशाल समर्थन के समक्ष प्रभावहीन हो गई है। पंजाब में ड्रोन के जरिये हथियार और नशे भेजे जा रहे हैं। यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता के तौर पर उभरा है।

सीमा पार से कुछ दिनों में भेजे गए 30 से अधिक पिस्तौल, एक एमपी-4 राइफल, एक एके-47 राइफल, करीब 35 ग्रेनेड, टिफिन बम, छह किलोग्राम से अधिक आरडीएक्स और आईईडी (नौ डेटोनेटर, एक मल्टीपल टाइमर डिवाइस और फ्यूज-वायर) पकड़े जा चुके हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से तीनों कृषि सुधार कानूनों को तुरंत रद करने की मांग भी की। कैप्टन ने कहा कि इससे पंजाब व अन्य राज्यों के किसानों में भारी रोष पनप रहा है। किसानों की चिंताओं का स्थाई हल किया जाए। केंद्र ने जून 2020 में जब अध्यादेश लागू किए थे तब से ही पंजाब में प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी यह शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें गुस्सा बढ़ता महसूस हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू होने के बाद 400 से ज्यादा किसानों व खेत मजदूरों की जान जा चुकी है।

न्यूज गैलरी

उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट भी निलंबित

देहरादून : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इससे खफा गोदियाल ने कहा, वह अपने जनों की आवाज उठाते रहेंगे। गोदियाल ने खुद ही इंटरनेट मीडिया पर अपना ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने की जानकारी दी। ट्विटर इन दिनों निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। बीते दिनों राहुल गांधी के साथ भी ट्विटर ऐसा ही कदम उठा चुका है। (राब्यू)

आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लखनऊ : लखनऊ में भाजपा विधायक अजय सिंह ने मंगलवार शाम को आप पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि और छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ला के मुताबिक अजय सिंह, हरैया सीट से भाजपा के विधायक हैं। मंगलवार को उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया कि संजय सिंह ने बीते आठ अगस्त को प्रेसवार्ता की थी। उन्हें और सरकार को बदनाम करने व छवि धूमिल करने के लिए मीडिया को फर्जी दस्तावेज दिखाए। अजय सिंह के मुताबिक, संजय सिंह ने प्रसिद्धि पाने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह साजिश रची है। भाजपा विधायक ने बताया कि संजय सिंह ने उनका प्रपत्र जल शक्ति विभाग के संबंध में दिखाया, जबकि उन्होंने जो प्रश्न उठाए थे वह सिंचाई विभाग के संबंध में थे। भाजपा विधायक के मुताबिक, उनका जल शक्ति मंत्रालय से कोई सरोकार नहीं है। (जासं)

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने को भाजपा का प्रदर्शन

कोलकाता : बंगाल के हावड़ा जिले में बोल नहीं पाने वाली महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के विरोध में भाजपा ने समूचे बंगाल में प्रदर्शन किया। पार्टी ने दावा किया कि वारदात सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने की है, क्योंकि पीड़िता का पति भाजपा का समर्थक है। इस मामले में पुलिस ने अब तक दो तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार किया है। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल के पास प्रदर्शन किया। (राब्यू)

आखिर भाजपा को निकालना ही पड़ा पूर्व विधायक बबलू को

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सांसद रीता बहुगुणा का घर जलाने के आरोपित को छह दिन पहले किया था शामिल
- पार्टी की किरकिरी, बहुगुणा की आपत्ति व नड्डा के दखल पर कार्रवाई

महज छह दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए बसपा के दागी पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को आखिरकार पार्टी को बाहर निकालना ही पड़ा। भाजपा की ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपित बबलू को गले लगाकर पार्टी नेताओं ने अपनी किरकिरी करा ली। पार्टी विद डिफरेंस की नीति पर सवाल खड़े हुए, सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर आपत्ति जताई, तब जाकर कार्रवाई की गई।

अयोध्या के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू बसपा छोड़कर चार अगस्त को भाजपा में शामिल हुए थे। उनके गले में भगवा गमछा पड़ते ही मामला गर्मा गया क्योंकि 15 जुलाई, 2009 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने की घटना के आरोपितों में बबलू भी शामिल हैं। मुकदमा चल रहा है। रीता अब भाजपा की सांसद हैं। मामला चर्चित है। इसके बावजूद दागी पूर्व विधायक को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता दिला दी गई। सांसद ने उसी दिन दिल्ली से बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी। कड़े शब्द नहीं बोले, लेकिन पीड़ा जाहिर करते हुए कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मामला उठाएंगी। मामला तूल पकड़ चुका था, तब भी पार्टी ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। माना जा रहा है कि बबलू को भाजपा में लाने वाला मध्यस्थ प्रभावशाली रहा होगा मगर, गत दिवस राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिन के लखनऊ प्रवास पर आए। लखनऊ में आयोजित बैठक में शामिल होने रीता बहुगुणा भी पहुंचीं। उन्होंने बबलू को भाजपा में शामिल कराए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। नड्डा के दखल के बाद ही मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष ने बबलू की सदस्यता रद की है।

बाढ़ पर विस में चर्चा न होने से नाराज कांग्रेस विधायक ने खुद का कुर्ता फाड़ा

विधानसभा परिसर में विरोधस्वरूप अपने कपड़े फाड़ते कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल। नईदुनिया

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाढ़ से हुई तबाही और राहत कार्यों में लापरवाही पर विधानसभा में चर्चा नहीं होने पर कांग्रेस विधायक ने खुद का कुर्ता फाड़ लिया। विस में चर्चा की मांग कर रहे श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने चर्चा का मौका न मिलने पर मीडियाकर्मियों के सामने अपना विरोध दर्ज कराते हुए यह कदम उठाया।

उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है और बाढ़ पीड़ित लोगों के पास खाने-पीने की सामग्री, पहनने के लिए कपड़े और जूते-चप्पल तक नहीं हैं। सब कुछ तबाह हो गया है और सरकार विस में इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती है।

बंगाल के घाटाल में बाढ़ की भयावह स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार : ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटाल में बाढ़ की भयावह स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को घाटाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घाटाल मास्टर प्लान वर्षों पहले तैयार किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसी कारण घाटाल में बाढ़ की इतनी भयानक स्थिति होती है। मुख्यमंत्री ने घाटाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद देव को दिल्ली जाकर इस बाबत केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का निर्देश दिया। ममता ने कहा कि वह कोलकाता लौटकर घाटाल में बाढ़ की स्थिति को लेकर खुद भी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेंगी।

बंगाल के कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रही हैं। मंगलवार को पश्चिम मेदिनीपुर में स्थिति का निरीक्षण करती ममता बनर्जी। प्रेट्र

'खेला होबे दिवस' पर सनातन धर्मावलंबियों ने जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- राज्यपाल से मिलकर दिन परिवर्तन की लगाई गुहार
- जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर दी जानकारी

बंगाल विधानसभा चुनाव में धूम मचाने वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नारे 'खेला होबे' को भुनाने के लिए सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को राज्य में 'खेलो होबे दिवस' मनाने का एलान किया है। इस पर मुख्य विपक्षी भाजपा ने पहले ही आपत्ति जताई थी, अब मंगलवार को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सनातन धर्मावलंबियों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर आपत्ति जताते हुए दिन परिवर्तन की मांग की।

राज्यपाल ने ट्वीट किया कि सनातन धर्मावलंबियों के प्रतिनिधियों ने खेला होबे दिवस की तारीख में बदलाव की मांग करने के लिए मुलाकात की, क्योंकि यह दिन 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की भयानक यादों की याद दिलाता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उनकी एकमात्र आपत्ति खेला होबे दिवस की तारीख पर थी और सरकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार को भावनाओं से अवगत कराया जाएगा।

फिर दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर गए राज्यपाल

इस बीच, राज्यपाल जगदीप धनखड़ मंगलवार शाम को अचानक फिर दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर निकल गए। इसको लेकर सियासी गहमा-गहमी फिर बढ़ गई है। डेढ़ महीने के भीतर राज्यपाल की यह दिल्ली की तीसरी यात्रा है। दरअसल, राज्यपाल का ममता सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव चल रहा है। हालांकि, राज्यपाल किस उद्देश्य से गए हैं, इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है।

मुकुल को पीएसी अध्यक्ष बनाने पर बढ़ सकती है ममता सरकार की मुश्किल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में वापसी करने वाले मुकुल रॉय को विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा की ओर से मुकुल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से 12 अगस्त तक हलफनामा जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

गौरतलब कि ऐसी परंपरा रही है कि विस में पीएसी का अध्यक्ष पद विपक्ष के किसी विधायक को दिया जाता है। लेकिन भाजपा की आपत्ति के बावजूद मुकुल को विस अध्यक्ष ने पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मुकुल ने भाजपा छोड़ने के बावजूद विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था। विधानसभा के रिकार्ड में मुकुल अब भी भाजपा के ही विधायक हैं। हालांकि टीएमसी का तर्क है कि पीएसी अध्यक्ष पर नियुक्ति विस अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।

सियासत

कपिल सिब्बल के डिनर में 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता पर चर्चा के दौरान अकाली नेता गुजराल ने कांग्रेस को दी सलाह तो मौजूद नेताओं में छा गई खामोशी

परिवार से इतर देखने की गुजराल की सलाह कांग्रेस को नागवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजनीति की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए 2024 के चुनाव में कांग्रेस को एक खास परिवार से इतर देखने की अकाली दल नेता नरेश गुजराल की सलाह पार्टी को बेहद नागवार लगी है। मगर सियासी वजहों से पार्टी इसे तूल न देना ही मुनासिब मान रही है।

सोमवार रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के डिनर में विपक्षी दलों के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। इस जमावड़े में आकाली दल के नरेश गुजराल ने कहा कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष एकजुट हो। एकजुटता के लिए उन्होंने लगे हाथ मौजूद कांग्रेस नेताओं को एक परिवार से अलग हटकर सियासी दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे डाली।

सूत्रों ने बताया कि डिनर के दौरान अकाली नेता ने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता और नेतृत्व के लिहाज से कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के पहलुओं की बात उठाते हुए कहा कि पार्टी को परिवार की परिधि से बाहर निकलकर देखने की जरूरत है। गुजराल की यह टिप्पणी सीधे तौर पर कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व की मौजूदा समय में राजनीतिक स्वीकारोक्ति की चुनौतियों की ओर साफ इशारा करती है।

नरेश गुजराल। फाइल फोटो

क्या कहा था गुजराल ने

2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष एकजुट हो। एकजुटता के लिए उन्होंने लगे हाथ मौजूद कांग्रेस नेताओं को एक परिवार से अलग हटकर सियासी दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे डाली।

सूत्रों के अनुसार गुजराल ने जब यह टिप्पणी की तो इस डिनर वार्ता में अचानक कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई और किसी अन्य विपक्षी नेता ने इस बारे में कोई टीका-टिप्पणी करने से परहेज किया। वहीं डिनर में मौजूद कांग्रेस नेताओं की ओर से भी गुजराल के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। डिनर टेबल पर हालांकि इसके साथ ही 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता से लेकर राजनीतिक पहलुओं पर खुलकर चर्चा की गई। कपिल सिब्बल ने अपने जन्म दिन के दो दिन बाद अपने राजनीतिक मित्रों के साथ विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था।

कांग्रेस के जी 23 समूह के नेताओं गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण और पी.चिदंबरम के साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन व कल्याण बनर्जी, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, द्रमुक के त्रिची शिवा आदि जैसे विपक्षी दिग्गज इसमें शरीक हुए।

खास बात यह भी रही कि सिब्बल के सियासी डिनर में विपक्षी खेमे से अब तक बाहर रहे अकाली दल के गुजराल के अलावा बीजेडी के पिनाकी मिश्रा, वाइएसआर कांग्रेस और टीआरएस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये चारों दल संसद के बाहर ही नहीं भीतर भी विपक्ष के खेमे से दूरी रखते रहे हैं और ऐसे में 2024 में विपक्षी नेताओं की मंत्रणा की मेज पर इनका आना दूरगामी राजनीति के लिहाज से मायने रखता है। कांग्रेस ने हालांकि डिनर में हुई जुटान और चर्चाओं पर किसी तरह की प्रतिक्रिया से परहेज किया मगर पार्टी नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अकाली दल से पंजाब में कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। अगले छह महीने में चुनाव हैं। इसी तरह तेलंगाना में टीआरएस से और ओडिशा में बीजेडी उसकी मुख्य विरोधी है और इस लिहाज से इन दलों के साथ साझेदारी की गुंजाइश ही नहीं है।

यूपीएससी के प्रश्न-पत्र में बंगाल में चुनावी हिंसा पर सवाल, विवाद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- तृणमूल कांग्रेस ने जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा के प्रश्न-पत्र में बंगाल में चुनावी हिंसा के संबंध में सवाल पूछे जाने पर विवाद हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे प्रश्न-पत्र से अविलंब हटाने को कहा है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उधर, भाजपा ने कहा है कि जानकारी के लिए परीक्षार्थियों से सवाल पूछा गया है।

गौरतलब है कि यूपीएससी के तहत होने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न-पत्र में परीक्षार्थियों को बंगाल में चुनावी हिंसा पर करीब 200 शब्दों में रिपोर्ट लिखने को कहा गया था। गत आठ अगस्त को हुई परीक्षा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए रिपोर्ट लिखने को भी कहा गया था। अन्य विषय के तौर पर दिल्ली में आक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की समस्या भी थी। अब टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विरोध जताते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह नियुक्तियां भाजपा करा रही है। वह प्रशासन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कुणाल घोष ने इसके लिए जिम्मेदार यूपीएससी के अधिकारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है। दूसरी तरफ बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जब बंगाल बोर्ड के पाठ्यक्रम में सिंगुर आंदोलन को शामिल किया जा सकता है तो इसमें हर्ज क्या है? प्रार्थियों को देश के मौजूदा हालात की कितनी जानकारी है, यह जानने के लिए ही इसे प्रश्न-पत्र में शामिल किया गया था।

उज्ज्वला से महिलाओं के सशक्तीकरण के संकल्प को बल मिला : पीएम

दौड़ेगा विकास का इंजन ▶ प्रधानमंत्री ने उप्र के महोबा से किया उज्ज्वला-2.0 का वर्चुअल शुभारंभ

कहा-पानी की तरह अब हर घर की रसोई तक गैस भी पहुंचेगी

शैलेंद्र शर्मा, महोबा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी की तरह अब हर घर की रसोई तक गैस भी पहुंचेगी। पीएम ने मंगलवार को उप्र के महोबा से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला-2.0 योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उज्ज्वला योजना के पहले चरण में आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। इससे मां, बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य, सुविधा व सशक्तीकरण के संकल्प को बल मिला। अब दूसरे चरण में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को फायदा मिलेगा। पीएम ने बताया कि उज्ज्वला 2.0 के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रवासियों को अब पते का प्रमाणपत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार या प्रवासी श्रमिक अब खुद के द्वारा सत्यापित (सेल्फ डिक्लेरेशन) पते का आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। गन्ने के अवशेष से उप्र के 70 जिलों में बायोफ्यूल गैस प्लांट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बदायूं, गोरखपुर और पंजाब के बठिंडा में बायोफ्यूल बनाने के लिए बड़े कांप्लेक्स बनाए जा रहे हैं। किसानों को कचरे का दाम मिलेगा, जबकि हजारों युवा रोजगार पाएंगे।

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर लाभार्थियों से संवाद किया। एएनआइ

इससे देश के विकास का इंजन दौड़ेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री के उज्ज्वला-2.0 योजना लांच करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन सौंपे। देश में एक करोड़, प्रदेश में एक लाख से अधिक और महोबा जिले में एक हजार लाभार्थियों को पहले दिन कनेक्शन दिए गए। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रत्येक लाभार्थी को भरा हुआ एक सिलेंडर, रेगुलेटर व गैस चूल्हा दिया गया। पहले चरण में छूटे लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2016 में उप्र के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडेय की धरती से उज्ज्वला गैस योजना का पहला चरण शुरू हुआ था।

यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं। लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे लाखों परिवारों को उज्ज्वला 2.0 योजना सबसे अधिक राहत देगी।

–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह भी बोले प्रधानमंत्री

- कोरोना काल में काम-धंधे बंद रहे तो छह माह तक फ्री गैस सिलेंडर मां-बहनों तक पहुंचे।
- ओलिंपिक में देश के खिलाड़ियों ने मान बढ़ाया तो बुंदेलखंड की धरती से जुड़े दद्दा मेजर ध्यानचंद के नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की। दद्दा का नाम युवाओं को प्रेरित कर रहा है।
- सीएनजी आधारित यातायात पर फोकस है। उप्र के 50 जिलों में 21 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन से लैस किया जा रहा है।
- गन्ने से इथेनाल बनाने से आना-जाना सस्ता होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। उप्र में इथेनाल उत्पादकों से सात हजार करोड़ रुपये की खरीद हुई है।
- 25 साल में समर्थ और सक्षम होगा देश। दूसरे चरण में मुफ्त गैस कनेक्शन व चूल्हा मिल रहा है। बहनों से रक्षाबंधन का अग्रिम आशीर्वाद भी मिले।

मोदी जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

उज्ज्वला 2.0 योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को बात कर गदगद गोरखपुर के सहजनवां के पाली ब्लाक की ग्राम पंचायत कोदरी टोला डीहुलीपार निवासी किरन ने कहा, 'मोदी जी, रसोई गैस कनेक्शन मिलने से बहुत मदद मिली है। अब हमारा समय बचता है, इससे हम काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। जब रसोई गैस नहीं थी तो हम काम करके थक कर घर आते तो कभी-कभार खाना ही नहीं बनता था। बारिश के दिनों में लकड़ी सुखाओ या काम करो, बहुत दिक्कत होती थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सब कुछ आसान हो गया है। हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आप ऐसे ही बने रहें।' प्रधानमंत्री मोदी ने किरन व इंटर में पढ़ने वाली उनकी बेटी साधना से पांच मिनट तक वर्चुअली बात की। कक्षा आठ पास किरन को उज्ज्वला योजना 1.0 में 2016 में रसोई गैस कनेक्शन मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरन को नमस्ते करने के साथ बात की शुरुआत की। किरन ने बताया कि वह बांस का बेना, पंखा, डलिया बनाती हैं। सिलाई भी करती हैं।

महंगी रसोई गैस के कारण उज्ज्वला योजना विफल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि दावों से उलट यह योजना भी सिर्फ जुमला साबित हुई है और इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले सात साल में मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर रसोई गैस के दाम को दोगुना कर दिया और इसकी वजह से रसोई गैस गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी है। सिलेंडर के दाम घटाकर 400 रुपये प्रति सिलेंडर करने की मांग करते हुए कहा है कि जब तक कीमतें नहीं घटाई जातीं तब तक इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।

पिछले कुछ साल में भारत में बढ़ी शेरों की आबादी : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विश्व शेर दिवस' पर इस वन्यजीव के संरक्षण में जुटे लोगों को बधाई दी और कहा कि देश को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ साल में भारत में शेरों की आबादी में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, 'शेर राजसी और साहसी होते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। विश्व शेर दिवस पर मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इसके संरक्षण को लेकर गंभीर हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है।'

100 फीट ऊंचा तिरंगा

जम्मू-कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिसार्ट गुलमर्ग में सैलानियों को अब 100 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता तिरंगा नजर आएगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की शृंखला के तहत सेना ने मंगलवार को गुलमर्ग में धातु से तैयार 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। जागरण

मुकदमा सेटल कराने के नाम पर 50 करोड़ ऐंठे, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से अदालतों में चल रहे मुकदमों को सेटल कराने के एवज में 50 करोड़ रुपये ऐंठने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर व उसके दो साथियों को इस मामले गिरफ्तार किया है। तीनों को स्पेशल सेल ने आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया है। सुकेश के दोनों साथी दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली की जेल से यह अब तक की सबसे बड़ी उगाही व धोखाधड़ी की राशि है, जो जेल से कैदियों द्वारा चलाए जा रहे अपराध को उजागर करती है। बता दें, बेंगलुरु का रहने वाला सुकेश राजनेताओं के रिश्तेदार के रूप में खुद को पेश कर लोगों से ठगी करता था।

सूत्रों के मुताबिक कुछ माह पहले सुकेश ने कारोबारी से संपर्क कर उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू होने की जानकारी दी और सेटलमेंट के लिए मोटी रकम की मांग की। कारोबारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में कुछ मामले विचाराधीन हैं। उक्त मामले को सेटल कराने के लिए उसने अपनी ऊंची पहुंच का झांसा देकर कारोबारी को पैसे देने को मजबूर किया। सुकेश के साथियों ने कारोबारी से पैसे एकत्र किए। मामला नहीं सुलझने पर कारोबारी ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। सेल ने सुकेश व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था।

टीटीवी दिनाकरन मामले में हुआ था गिरफ्तार

चंद्रशेखर को पांच साल पहले टीटीवी दिनाकरन से चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में 50 करोड़ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चुनाव आयोग में संपर्क होने का दावा करके उसने उक्त रकम ऐंठने की कोशिश की थी। उसे दिल्ली के एक होटल के कमरे से 1.3 करोड़ रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया था।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले : राहुल गांधी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को अविलंब राज्य का दर्जा प्रदान करने पर जोर देते हुए कहा कि मेरी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम अपनी नीतियों से देश में हिंसा और नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है। संसद हो, न्यायपालिका हो या प्रेस, वह प्रत्येक संस्थान पर आघात कर रहे हैं। मैं उनसे लड़ूंगा और उन्हें हराऊंगा।

राहुल गांधी श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने के बाद राहुल गांधी का यह पहला कश्मीर दौरा है। उन्होंने अगस्त 2019 में कश्मीर आने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया था। अब वह गत सोमवार को कश्मीर आए थे और मंगलवार शाम को दिल्ली लौट गए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सुबह जम्मू-कश्मीर में स्थित मां क्षीर भवानी मंदिर में पूजा-अर्चना की। मां क्षीर भवानी को कश्मीरी पंडितों की प्रमुख आराध्य देवी माना जाता है। एएनआइ

संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता : राहुल गांधी ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर की आवाज संसद में उठाना चाहता हूं, लेकिन वहां मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज आक्रमण सिर्फ जम्मू-कश्मीर पर नहीं हो रहा है, पूरे भारत पर हो रहा है। मैं संसद में भ्रष्टाचार, पेगासस, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल सकता। मीडिया के मित्र सच नहीं लिख सकते, अगर लिखें तो नौकरी जाने का खतरा है।

आजाद नहीं चाहते जम्मू-कश्मीर का शासन कोई उपराज्यपाल चलाए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू-कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा मिले, इसके बाद विधानसभा चुनाव करवाएं जाएं।

सभा से एक किमीदूर ग्रेनेड हमला, 10 घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किए गए कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आतंकियों ने मंगलवार को कश्मीर में दो हमले किए। श्रीनगर के लाल चौक के साथ सटे हरि सिंह हाईस्ट्रीट क्षेत्र में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें दो महिलाओं समेत 10 नागरिक घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिस जगह यह हमला हुआ, वहां से लगभग एक किलोमीटर दूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

इसके बाद राहुल का सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर गत सोमवार को श्रीनगर आए थे। इससे पूर्व सुबह आतंकियों ने शोपियां में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक सीआरपीएफ कर्मी जख्मी हो गया। दोनों हमलों की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है।

आतंकी फंडिंग में दो गिरफ्तार, 25.81 लाख रुपये बरामद

संवाद सहयोगी, पुंछ : सुरक्षाबलों ने पुंछ जिले में हवाला के जरिये आतंकी फंडिंग के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25.81 लाख रुपये की हवाला राशि बरामद की गई है। इनसे पूछताछ के बाद आतंकी फंडिंग से जुड़े और भी लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि नियंत्रण रेखा के पास बालाकोट सेक्टर के कांगा गली इलाके के कुछ लोग पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के आकाओं से संपर्क हैं। ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। सूचना मिली थी कि क्षेत्र में पाकिस्तान से हवाला राशि के जरिये जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक रकम पहुंचाई जा रही है।

गलवन संघर्ष के बाद क्षमता बढ़ाने पर वायुसेना का ध्यान

नई दिल्ली, प्रेट्र : वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवन घाटी में संघर्ष के बाद क्षमता बढ़ाने पर वायुसेना ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके तहत ज्यादा सटीकता से लक्ष्य पर हमला करना, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करना और नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।

एक प्रमुख थिंक टैंक को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों पर वायुसेना को बढ़त हासिल है। यह तेजी से जवाब दे सकती है और लक्ष्य को निशाना बना सकती है। राफेल जेट के शामिल होने से अगले स्तर का परिचालन संबंधी बदलाव आया है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बारे में भदौरिया ने कहा कि वायुसेना इसको लेकर कई कदम उठा रही है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए अगली पीढ़ी के जैमर खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह हमला मुमकिन ही नहीं होता, यदि दो-तीन महीने बाद ऐसा प्रयास किया जाता। वायुसेना की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए भदौरिया ने उस सामान्य समझ का जिक्र किया, जिसके तहत इसका काम सिर्फ आक्रामक कार्रवाई मानी जाती है। आम तौर पर कुछ खास परिस्थितियों में इसकी भूमिका से इन्कार किया जाता है। लेकिन भदौरिया ने कहा कि परिदृश्य बदल चुका है। पिछले महीने एक सेमिनार के दौरान चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि वायुसेना की भूमिका सिर्फ सहायक बल की है। इससे असहमति जताते हुए भदौरिया ने कहा था कि वायुसेना को बड़ी भूमिका निभानी होती है।

श्रीनगर में ग्रेनेड के साथ न्यूज एजेंसी का उप संपादक गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : सुरक्षाबलों ने मंगलवार को हरि सिंह हाईस्ट्रीट में ग्रेनेड हमले के लगभग डेढ़ घंटे बाद लालचौक में तलाशी अभियान के दौरान एक स्थानीय न्यूज एजेंसी के उपसंपादक आदिल फारुक को दो हैंड ग्रेनेड संग दबोच लिया। उसका एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। फारुक 2019 में राष्ट्रविरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल काट चुका है। पकड़ा गया आदिल जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) काम करता था।

आदिल फारुक ग्रेनेड के साथ दबोचा गया। सौ. इंटरनेट मीडिया

मां के सामने दो नाबालिग बेटियों से हुआ सामूहिक दुष्कर्म, फिर जहर देकर मारा

जागरण संवाददाता, सोनीपत

▶ चार आरोपितों ने मां को मुंह खोलने पर दी थी जान से मारने की धमकी

▶ हत्या पर पर्दा डालने को मां से दिलाया सांप के डंसने का बयान

हरियाणा में सोनीपत जिले के कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव में मां के सामने ही दो नाबालिग बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद आरोपितों ने दोनों बेटियों को कीटनाशक पिला दिया। दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। आरोपितों ने लड़कियों की मां को उसके बेटों को मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने की धमकी दी। साथ ही बेटियों की मौत सर्पदंश से होने की बात कहने पर मजबूर कर दिया,लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म व कीटनाशक से मौत का पता लगने के बाद राज खुल गया। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सभी बिहार के रहने वाले हैं।

मूलरूप से बिहार की रहने वाली विधवा महिला अपनी दो बेटियों व दो बेटों के साथ कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव के बाहर बने मकान में किराये पर रहती है। उसके पड़ोस के दूसरे मकान के कमरों में बिहार के युवक भी रहते हैं। महिला पांच अगस्त की रात को कमरे में अपनी 14 व 16 साल की बेटियों के साथ सो रही थी। उसके बेटे छत पर सो रहे थे। रात में करीब दो बजे वह लघुशंका के लिए कमरे से बाहर निकली तो पड़ोस में रहने वाले चार युवक कमरे में घुस गए। उन्होंने कमरे में उसकी बेटियों को दबोच लिया। इसी बीच महिला वापस आई तो आरोपितों ने उसका मुंह दबाकर एक तरफ बैठा लिया। आरोपितों ने दोनों नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद दोनों को कमरे में रखा कीटनाशक पिला दिया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। आरोपितों ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके बेटों को भी मार देंगे। उन्होंने महिला से कहा कि कोई पूछे तो बता देना कि इनको सांप ने डंस लिया है। सुबह तक दोनों लड़कियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। मकान मालिक की मदद से दोनों को दिल्ली में नरेला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

कुंडली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला ने सर्पदंश से बेटियों की मौत होने की बात कही। इस पर नरेला में दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया था। उसकी रिपोर्ट सोमवार को मिलने पर पुलिस को लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने और कीटनाशक पिलाने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बयान कर दी। पुलिस ने दरभंगा के गांव महागही के रहने वाले अरुण, गांव मुसहेरी के फूलचंद, धयोकली के रहने वाले दुखन और समस्तीपुर के रहने वाले रामसुहाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मतांतरण मामला : मोबाइल में कैद है डा.फराज का षड्यंत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

गहरी साजिश के तहत मतांतरण कराने वाले गिरोह का अहम हिस्सा रहा डा. फराज शाह अपने साथियों के साथ फोन पर भी जहर उगलता था। रामेश्वर कांवरे उर्फ एडम व कौसर आलम के मोबाइल फोन से मिली आडियो क्लिप से एटीएस को फराज के खिलाफ ठोस साक्ष्य भी मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि आडियो क्लिप में फराज कुछ लोगों के मतांतरण की प्रक्रिया को लेकर एडम से बात कर रहा है। फराज व उमर गौतम के बीच भी फोन पर लंबी बातचीत होती थी। एटीएस अब फराज के कुछ अन्य साथियों की भी छानबीन में जुट गई है। शुरुआती छानबीन में फराज का केरल कनेक्शन भी सामने आया है। एटीएस की विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपित फराज की सात दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। पुलिस रिमांड की अवधि बुधवार दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी। एटीएस अब उससे नए सिरे से पूछताछ करेगी।

एटीएस को महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी एडम व उसके साथियों की गतिविधियों की जानकारी मिली है। एडम के मोबाइल से मिले साक्ष्यों के जरिये ही एटीएस ने फराज पर शिकंजा कसा है। फराज दिल्ली स्थित उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के अलावा ऐसे कई अन्य संगठनों से भी सीधे जुड़ा था। कुछ कट्टरपंथी संगठनों से उसके जुड़ाव को लेकर भी जांच चल रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े कुछ अन्य लोगों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की तैयारी भी है। उल्लेखनीय है कि एटीएस साजिशन एक हजार से अधिक हिंदुओं का मतांतरण कराने वाले उमर गौतम से जुड़े रहे उसके साथियों पर एक-एक कर शिकंजा कस रही है।

प्रयागराज में गंगा-यमुना लाल निशान के पार

जागरण टीम, लखनऊ

प्रयागराज में गंगा-यमुना ने मंगलवार को खतरे का निशान पार कर लिया। इसके साथ ही नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। बनारस, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात सहित कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जलधार गांव घेर कर ग्रामीणों को डरा रही है। संगमनगरी में लगातार तीसरे दिन गंगा और यमुना उफान पर रहीं। मंगलवार रात आठ बजे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.09 मीटर ऊपर था और यमुना का 95 सेंटीमीटर। रात आठ बजे के आसपास इस समय गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 85.82 व छतनाग में 85.03 मीटर था तथा नैनी में यमुना का 85.65 मीटर। तीनों ही स्थान पर खतरे का निशान 84.73 मीटर है। करीब 12 हजार मकान शहर में ही डूब क्षेत्र में आ गए हैं। बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मीरजापुर, भदोही में हाहाकार मचा हुआ है। बलिया में आठ घंटे में गंगा आठ सेमी बढ़ी है।

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में भी गंगा उफनाई हुई है। जलस्तर बढ़ने के साथ घाट और अंत्येष्टि स्थल जलमग्न हो गए हैं। इसके चलते लोगों को शवदाह में मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। प्रेट्र

बिहार में गंगा-कोसी उफान पर, खगड़िया में टूटा बांध

जागरण टीम, पटना : बिहार के कई जिलों में बीते दो-तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियां फिर उफान पर हैं और कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बाया, बागमती समेत पहाड़ी नदियों का कहर बरपा रही हैं। कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है, वहीं कोसी का पानी भी कई गांवों में फैल गया है। खगड़िया में जमींदारी बांध टूटने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है।

'पाकिस्तान के लिए वीजा नियमों को और सख्त बनाने की जरूरत'

जागरण संवाददाता, राजौरी

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीरी युवाओं के शिक्षा या पर्यटक वीजा पर पाकिस्तान जाने और आतंकी संगठनों में शामिल होने के मामले सामने आने के बाद पाकिस्तान के लिए पर्यटक, शिक्षा वीजा के नियमों को सख्त बना दिया गया, लेकिन इसे और सख्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में कश्मीर से 57 युवक पर्यटक और शिक्षा वीजा पर पाकिस्तान चले गए और आतंकी संगठनों में शामिल हो गए। इनमें से 17 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 13 अभी भी सक्रिय हैं, जिनकी पहचान हो गई है। शेष युवक अभी गुलाम कश्मीर में हैं।

मंगलवार को राजौरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीजीपी ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार स्थित लांचिंग पैड पर अभी भी 250 से 300 आतंकी मौजूद हैं, जो घुसपैठ की कोशिश में हैं।

सीमावर्ती जिला राजौरी के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तानी की सेना के बीच 26 फरवरी के संघर्ष विराम समझौते के बाद, शांति की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आतंकवाद के मोर्चे पर प्रारंभिक चुप्पी के बाद, घुसपैठ के प्रयासों में अचानक तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में राजौरी में एलओसी से घुसपैठ के चार प्रयासों के बारे में जानकारी है। इनमें से घुसपैठ करने वाले एक समूह को सुंदरबनी के दादल में, दूसरे को नौशहरा में और तीसरे समूह को चार रोज पहले थन्ना मंडी भंगाई में मार चुके हैं। डीजीपी ने कहा कि एक अन्य समूह राजौरी में मौजूद हो सकता है, जिनकी तलाश में सुरक्षाबलों के जवान लगे हुए हैं।

देश में 147 दिन बाद मिले सबसे कम 28 हजार नए मामले

राहत ▶ 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 13 हजार से अधिक की गिरावट

केरल में नहीं सुधर रहे हालात, आधे से अधिक नए मामले मिले और सौ से ज्यादा लोगों की गई जान

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कुछ राहत के संकेत मिले हैं। 147 दिन बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम 28,204 नए मामले पाए गए हैं और 41,511 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसकी वजह से सक्रिय मामलों में 13,680 की कमी आई है और यह 139 दिनों के रिकार्ड निचले स्तर पर आ गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक केरल में स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। 28 हजार में से 13 हजार केस केरल में ही पाए गए हैं और इस दौरान हुई कुल 373 मौतों में से भी 105 मौतें केरल से ही हैं। महाराष्ट्र में 68 लोगों की जान गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक वैक्सीन की 51.45 करोड़ डोज लगाई गई हैं।

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	28,204
कुल सक्रिय मामले	3,88,508
24 घंटे में टीकाकरण	54.91 लाख
कुल टीकाकरण	51.45 करोड़

मंगलवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	28,204
कुल मामले	3,19,58,158
सक्रिय मामले	3,88,508
मौतें (24 घंटे में)	373
कुल मौतें	4,28,682
ठीक होने की दर	97.45 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	1.87 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.36 फीसद
जांचें (सो.)	15,11,313
कुल जांचें (सो.)	48,32,78,454

कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज गंभीरता से विचार : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा वीके पाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने टीके की बूस्टर डोज देने पर विचार किया है और इसे बहुत गहराई से देखा जा रहा है। पाल ने कहा कि इसे इस कार्य में प्रगति के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञान अब भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है।

कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की जरूरत पर किए गए सवाल के जवाब में पाल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने अपनी पिछली बैठक में टीके की बूस्टर डोज लगाने के मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा, 'मैं कहना चाहूंगा कि हम इस तरह की जरूरतों के लिए विज्ञान पर बहुत सावधानी से निगाह बनाए हुए हैं। देश में कुछ अध्ययन किए गए हैं और हम इसे बहुत गहराई से देख रहे हैं।'

स्वतंत्रता के सारथी | **महामारी से आजादी**

सवा साल तक बिना छुट्टी की ड्यूटी

टेस्टिंग, ट्रेसिंग व ट्रीटमेंट में मार्च 2020 से लगातार जुटे रहे अमृतसर के डा. मदन मोहन

नितिन धीमान • अमृतसर

संकट काल में नागरिकों की सेवा और जीवनरक्षा का कार्य देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प है। कोरोना काल में अमृतसर के डाक्टर मदन मोहन ने करीब सवा साल तक बिना एक भी अवकाश लिए, ड्यूटी कर यही संकल्प निभाया। बीते साल और इस वर्ष वायरस इतनी तेजी से फैला कि संभलने का मौका नहीं मिला। अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलाजिस्ट डा. मदन मोहन ने संक्रमण के बीच वायरस से लोगों को बचाने के लिए, लगातार ड्यूटी की। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने फील्ड में जाकर मरीजों की सुध न ली हो।

वार्ड बनवाने से लेकर इलाज तक: अमृतसर में पहला केस 19 मार्च, 2020 को रिपोर्ट हुआ था। डा. मदन मोहन कहते हैं, इसके तत्काल बाद हमारी टीमें अलर्ट पर आ गईं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अटारी बार्डर पर स्वास्थ्य टीमें डट गईं। शहर में लगातार कोरोना मरीज आने लगे। 100 से 200 और फिर हजार। इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनवाना बड़ी चुनौती थी। हमने तेजी से काम शुरू किया। मरीजों को दवा, खाना व उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई। क्वारंटाइन केंद्रों में उपचाराधीन मरीजों की देखरेख के लिए खुद जाकर सुबह-शाम अपडेट लिया। शहर में जहां भी कोरोना पाजिटिव मरीज मिला, उसके पूरे परिवार का टेस्ट करवाना, उसके संपर्क में आए कम से कम बीस लोगों को ट्रेस करना इत्यादि कार्यों में दिन-रात जुटे रहे। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट व ट्रेसिंग के लिए सुबह आठ से रात ग्यारह बजे तक कोरोना ड्यूटी करते रहे। न खाने का वक्त मिला, न सोने का। आइसोलेशन वार्डों की स्थापना, दवाओं की उपलब्धता, आक्सीजन का प्रबंध करने का जिम्मा भी डा. मदन मोहन ने बखूबी निभाया। इस वर्ष जुलाई माह से उन्होंने अवकाश लेना शुरू किया है। फिर भी वह अवकाश के दिन शाम को एक-दो घंटे के लिए आफिस जरूर जाते हैं।

अन्य भी हुए प्रेरित: सीनियर मेडिकल आफिसर डा. चंद्र मोहन कहते हैं कि डा. मदन मोहन ने जिस संजीदगी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई, उसने कई अन्य स्वास्थ्य कर्मियों व डाक्टरों को प्रेरित किया। डा. मदन ने कहा कि कोरोनाकाल में अफवाहों से लड़ना भी बड़ी चुनौती है। सेहत विभाग के कई योद्धा इस वायरस से मुकाबला करने के लिए सीना ताने खड़े हैं।

अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास एरिया में झुग्गी बस्तियों में लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करते डाक्टर मदन मोहन • जागरण

नियमों का कराते पालन

कोरोना के नोडल अधिकारी होने के साथ डा. मदन मोहन के पास स्वास्थ्य सेवाओं की कई जिम्मेदारियां भी हैं, जिनका निर्वहन वह संजीदगी से कर रहे हैं। डा. मदन के परिवार में दो बेटे और पत्नी है। घर से निकलने से पहले वह मास्क अवश्य पहनते हैं। शारीरिक दूरी के नियम का बराबर पालन करते हैं। संक्रमित मरीजों के बीच रहने की वजह से उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इस कारण उन्होंने खुद भी कोरोना दिशा-निर्देश का पालन किया और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।

अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलाजिस्ट डा. मदन मोहन • जागरण

टीकाकरण है जरूरी...

कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देशभर में टीकाकरण अभियान चल रहा है। बड़े शहरों सहित मैदानी इलाकों में इस काम को काफी गति मिल चुकी है, लेकिन अब दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह जोर पकड़ चुका है। भारी बारिश से हुए भूस्खन की परवाह न करते हुए जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम स्थानों पर पहुंच कर लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मंगलवार को टीकाकरण के लिए जाती महिला स्वास्थ्यकर्मी। एएनआइ

जागरूकता फैलाने के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र पर लिया गया है प्रधानमंत्री का चित्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर कोविड-अनुकूल व्यवहार का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाने वाले संदेश पर बल देने के लिए लगाई गई है। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कोविन की ओर से जारी किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र मानकीकृत और टीकाकरण प्रमाणपत्र सत्यापन डब्ल्यूएचओ निर्देश के अनुरूप हैं। वह इस सवाल का उत्तर दे रही थीं कि क्या कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापना आवश्यक और अनिवार्य है।

पीएमजीकेपी योजना में स्वास्थ्य कर्मियों के 1,016 दावे निपटाए गए : एक अन्य लिखित उत्तर में पवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय बीमा योजना (पीएमजीकेपी) के तहत पांच अगस्त तक 1,016 दावों का निपटारा कर भुगतान कर दिया गया। 276 दावे या तो राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वापस ले लिए गए या वे पात्र नहीं पाए गए। दस्तावेज अपूर्ण होने या राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से दस्तावेज विलंब से मिलने के कारण 111 दावे अभी लंबित हैं।

456 गर्भवती महिलाओं को लग चुकी है टीकों की दोनों खुराक : उन्होंने कहा कि कोविन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, चार अगस्त तक कुल 3,05,938 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए हैं। इनमें से 3,05,482 को पहली खुराक और 456 को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए राज्यों को लक्ष्य दिए गए हैं। अभी तक कुल 91,104 खुराक ट्रांसजेंडरों को दी गई है। इनमें से 77,457 को पहली खुराक, जबकि 13,647 को दोनों खुराक दी जा चुकी है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत कोविड संबंधी 20.32 लाख जांच अधिकृत

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 25 जुलाई तक कोविड-19 से संबंधित 20.32 लाख जांच और 7.08 लाख अस्पताल में भर्ती रोगी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत अधिकृत हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) एबी-पीएमजेएवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

कोरोना ने बढ़ा दिए नींद के घंटे

जयशंकर बिहारी, पटना

कोरोना काल में लोग सामान्य दिनों की तुलना में 30 मिनट से दो घंटे तक अधिक नींद ले रहे हैं, हालांकि जल्दी सोने की आदत में सुधार नहीं हुआ है। लोग देर से बिस्तर पर जा रहे और सुबह में देर से जाग रहे हैं। यह तथ्य पटना विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा राज्य के पांच हजार लोगों पर कोरोना काल में उनके सोने व जागने के समय में आए बदलाव पर किए गए सर्वे में सामने आए हैं। शहरी क्षेत्र की आबादी पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

इस वजह से ले रहे अधिक नींद : सर्वे के अनुसार लोगों ने नींद के घंटों में वृद्धि के कई कारण बताए हैं। इनमें बच्चों का स्कूल बंद होना, वर्क फ्राम होम, पार्क, धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर घूमने के सीमित विकल्प, स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी और कोविड संक्रमण के कारण कमजोरी हैं। सर्वे के समन्वयक अभिषेक आनंद ने बताया कि अधिसंख्य महिलाओं ने स्वीकार किया कि बच्चे के स्कूल नहीं जाने के कारण सुबह में जल्दी उनके लिए नाश्ता-भोजन नहीं बनाना पड़ रहा है। घर में सभी के रहने के कारण रसोई में सामान्य दिनों की तुलना में सहयोग ज्यादा मिलता है। इस कारण पूरी नींद ले रही हैं। सर्वे में पांच हजार में 345 परिवार के सदस्य वर्क फ्राम होम में रहे। सर्वे के अनुसार 65 फीसद लोगों ने स्वीकार किया है कि पहले की तुलना में बिस्तर पर मोबाइल ज्यादा देखते हैं। इस कारण देर से सोते हैं। एम्स, पटना के कोरोना नोडल पदाधिकारी डा. संजीव कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में कमजोरी व सुस्ती की शिकायत आम है। आइसीयू में भर्ती 71 फीसद और वार्ड में भर्ती 62 फीसद लोगों की शिकायत की है। कमजोरी के कारण भी नींद के घंटे बढ़ गए हैं।

यहां किया गया सर्वे

पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मोतिहारी, दरभंगा, नालंदा, रोहतास और कटिहार।

राष्ट्रीय फलक

शरत पंत व मल्लिका के परिचितों के घरों पर छापेमारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : कोरोना जांच फर्जीवाड़े के आरोपित दंपती शरत पंत व मल्लिका पंत की गिरफ्तारी के लिए एसआइटी ने उनके नोएडा व नैनीताल में रहने वाले परिचितों के घरों पर छापेमारी की है। एसआइटी की एक टीम नोएडा में ठहरी हुई है, दूसरी टीम नैनीताल पहुंच गई है। हालांकि दोनों आरोपित अभी एसआइटी की पकड़ से दूर हैं।

हरिद्वार कुंभ 2021 में श्रद्धालुओं की कोविड जांच में फर्जीवाड़े में एसआइटी ने मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरत पंत व मल्लिका पंत को मुकदमे में नामजद कर दिया है। इसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते एसआइटी को उनकी लोकेशन नोएडा व उत्तराखंड के नैनीताल में मिली थी। मगर जब तक एसआइटी की टीम नैनीताल पहुंची, आरोपित वहां से निकल चुके थे। इसके बाद दोनों के नोएडा में होने की जानकारी मिली। कानूनी शिकंजा कसने के लिए एसआइटी ने आरोपितों की कुर्की व गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।

जेड प्लस सुरक्षा के बिना मंडी आकर दिखाएं मुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, मंडी

- हिमाचल की जनता को 15 अगस्त को घर पर रहने की हिदायत दी
- कहा, पंजाब को आजाद करवाकर उसमें हिमाचल का करेंगे विलय

सिख फार जस्टिस संस्था के कानूनी प्रतिनिधि एवं केंद्र सरकार की तरफ से घोषित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फिर धमकी दी है। आडियो संदेश जारी कर पन्नू ने कहा कि अगर जयराम ठाकुर अपने देश को इतना प्यार करते हैं और सच में बहादुर हैं तो 15 अगस्त को मंडी में बिना जेड प्लस सिक्योरिटी व बुलेट प्रूफ कार से आकर दिखाएं।

पन्नू ने हिमाचल की जनता को 15 अगस्त को अपने घर पर रहने की हिदायत दी है। पन्नू ने लोगों को चेताया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। वह हिमाचल की जनता के विरुद्ध नहीं है। पंजाब को आजाद करवाकर हिमाचल का उसमें विलय करेंगे। पन्नू पिछले कई दिनों से आडियो संदेश जारी कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य नेताओं को धमकी दे चुका है। वह कभी हिमाचल को पंजाब का हिस्सा बता रहा है तो कभी इसके पंजाब में विलय की बात कर रहा है। पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा फहराने से रोकने वाले को 10 हजार यूएस डालर इनाम देने की बात कही थी। प्रदेश पुलिस को भी कई प्रभोलन दिए थे। पन्नू की धमकी को देखते हुए गृह विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को मंडी जिले के ऐतिहासिक सेरी मंच पर होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में तिरंगा झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसे लोगों की धमकी से वह डरने वाले नहीं हैं। स्वतंत्रता समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा।

तत्काल तीन तलाक के मामलों में आई 80 फीसद कमी : आरिफ

नई दिल्ली, एएनआइ : केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम लागू होने के बाद से मुस्लिम समुदाय में तत्काल तीन तलाक के मामलों में 80 फीसद की कमी आई है। उपराष्ट्रपति निवास में 'एक्सेलरेटिंग इंडिया : सेवेन इयर्स आफ मोदी गवर्नमेंट' के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आरिफ ने कहा, सरकार ने तत्काल तीन तलाक की अप्रिय प्रथा को समाप्त कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मनमाना होने के साथ ही इस कुप्रथा ने भारत के संविधान का भी उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा कि कानून लाए जाने से पहले यह कुप्रथा जारी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने एक परिचित के साथ तत्काल तीन तलाक के अत्याचारों का अनुभव किया। मदद करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उन्होंने कहा, सरकार को उन लोगों की देखभाल करनी है, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है। तत्काल तीन तलाक के मामले में सरकार ने इतिहास रच दिया है।

गंगा के लिए हाथ-पैर बांधकर 18 किमी तैरे दो तैराक

जुनून : लहरों से मुकाबला करते हुए दोनों तैराक पंकज और रोहित। संजय यादव

जागरण संवाददाता, कानपुर

तैराकी के क्षेत्र में नए आयाम दर्ज करने के लिए कानपुर के मास्टर तैराक पंकज जैन और राष्ट्रीय तैराक रोहित निषाद ने हाथ-पैर बांधकर डेढ़ घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तक गंगा में तैराकी की। साहसिक तैराकी के जरिये अविरल गंगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आयोजक तैराकों के इस उपलब्धि को गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड के लिए भेजेंगे।

मंगलवार को कानपुर के अटल घाट से पंकज व रोहित ने अपने अभियान की शुरुआत की। पंकज और रोहित ने एक घंटे 31 मिनट में 18 किमी का सफर गंगा में तैराकी कर पूरा किया।

पाक में मंदिरों को तोड़ने व मतांतरण के खिलाफ हैं बरेलवी उलमा

जागरण संवाददाता, बरेली : पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाए जाने और वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ पर उलमा ने नाराजगी जताई। दरगाह आला हजरत से जुड़े तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मंगलवार को कहा कि किसी को जबरन या लालच देकर मुसलमान नहीं बनाया जाना चाहिए।

प्रेसवार्ता में मौलाना बोले, इस्लाम का सिद्धांत है कि सिर्फ जुबान नहीं, दिल से भी धर्म स्वीकारा जाए। पाकिस्तान में खराब सोच के कुछ संगठन ऐसी हरकतें कर रहे, जो इस्लामिक सिद्धांत के विरुद्ध हैं। जबरन मतांतरण की निंदा करते हैं। बोले, इतिहास साक्षी है कि इस्लाम सूफी संतों के उच्च आचरण और स्वभाव से फैला है। उनकी खानकाहों से आज भी भारतवर्ष की गंगा जमुनी तहजीब की किरणें अपनी छठा बिखेर रही हैं। उन्होंने जबरन मतांतरण कराने वाले पाकिस्तान के मौलवियों को सिरफिरा और जाहिल करार दिया। उन्हें आला हजरत की लिखी पुस्तकें पढ़कर इस्लाम को समझने की हिदायत भी दी।

धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में 22.75 फीसद मदरसे

- धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में ईसाई समुदाय की हिस्सेदारी 71.96 फीसद

नई दिल्ली, प्रेट्र : धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में मुस्लिम अल्पसंख्यक स्कूलों की हिस्सेदारी महज 22.75 फीसद है और समुदाय के स्कूलों में गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या का फीसद सबसे कम है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में ईसाई समुदाय की हिस्सेदारी 71.96 फीसद है, जबकि कुल धार्मिक आबादी में समुदाय की हिस्सेदारी 11.54 फीसद है। आयोग के अध्ययन का मकसद अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिल सके ऐसे तरीके का पता लगाना था।

अध्ययन में पाया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 22.75 फीसद है और उनके अल्पसंख्यक स्कूलों में गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम 20.29 फीसद है। अध्ययन के मुताबिक, 'सभी समुदायों में, 62.50 फीसद विद्यार्थी गैर-अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है जबकि 37.50 फीसद अल्पसंख्यकों समुदायों से ताल्लुक रखते हैं।' अध्ययन के मुताबिक, ईसाई समुदाय के स्कूलों में गैर-ईसाई समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 74.01 फीसद है।

मजहबी तालीम दी जाती है मदरसे में। फाइल फोटो

एक करोड़ साल पुराने फाल्ट से दून में भूकंप

सुमन सेमवाल, देहरादून

- दून के शहंशाही आश्रम फाल्ट के सक्रिय रहने का प्रमाण है यह भूकंप
- भविष्य में सात या आठ रिक्टर स्केल का बड़ा भूकंप आने का अंदेशा

देहरादून के साहिया क्षेत्र में मंगलवार को आया 3.8 मैग्नीट्यूट का भूकंप यूं तो बहुत छोटा है। मगर इससे करीब एक करोड़ साल पुराना शहंशाही आश्रम फाल्ट फिर से चर्चा में आ गया है। क्योंकि, यह भूकंप इसी फाल्ट के दायरे में आया है। शहंशाही आश्रम फाल्ट को मेन बाउंड्री थ्रस्ट (एमबीटी) भी कहा जाता है और ताजा भूकंप यह बताता है कि फाल्ट आज भी सक्रिय है। हालांकि मंगलवार को आए भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

उत्पत्ति के बाद करोड़ों साल से हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इसी का परिणाम रहा कि करीब 1600 किलोमीटर लंबे सब-हिमालय का निर्माण हुआ। मेन बाउंड्री थ्रस्ट इस निर्माण का एक उदाहरण है। मंगलवार को आए भूकंप के अलावा फाल्ट की सक्रियता जानने के लिए वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने पूर्व में शहंशाही आश्रम क्षेत्र में अध्ययन किया था। तब संस्थान ने पाया कि शहंशाही आश्रम में 100 करोड़ से अधिक साल पुरानी चट्टानें महज 25 हजार साल पुराने दून के अवसादों के ऊपर चढ़ रही हैं। जबकि, सामान्य परिस्थिति में पुरानी चट्टानों को नीचे होना चाहिए। साफ है कि फाल्ट की सक्रियता के चलते पुरानी चट्टानें ऊपर बढ़ रही हैं।

वाडिया संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी डा. सुशील रोहेला के मुताबिक फाल्ट की सक्रियता बताती है कि भूगर्भ में तनाव जारी है और इससे भूकंपीय ऊर्जा पैदा हो रही है। गंभीर बात यह है कि उत्पन्न ऊर्जा के अनुरूप बेहद छोटे भूकंप ही आ रहे हैं। अंदेशा है कि भविष्य में यहां कभी भी सात या आठ रिक्टर स्केल का बड़ा भूकंप आ सकता है। लिहाजा, सरकार को भूकंपरोधी भवनों पर अधिक ध्यान देना होगा। वैसे भी दून भूकंप के अति संवेदनशील जोन चार व पांच में आता है। वर्तमान में यहां छोटे भूखंडों पर ऊंचे भवन खड़े करने या 30 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन बनाने की कवायद चल रही है। ऐसे में संबंधित एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ताकि बचाव के लिए कदम उठाए जा सकें।

भूकंप के प्रति संवेदनशील इलाका है देहरादून। इसे जोन चार में रखा गया है। फाइल फोटो

छत्तीसगढ़ में पुजारियों को भी मिलेगा 'न्याय'

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के भूमिहीनों के लिए एक नई न्याय योजना शुरू करने जा रही है। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें भूमिहीन मनरेगा और कृषि मजदूरों के साथ ही भूमिहीन धोबी, नाई, लोहार और पुजारी को भी शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के दायरे में राज्य के करीब 15 लाख परिवार आएंगे। इस तरह की योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।

नई योजना को सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अनुसार इस योजना के तहत हितग्राहियों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना को इसी वर्ष चालू करने का लक्ष्य है। सरकार ने इसके लिए अनुपूरक बजट में दो सौ करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को इसी वर्ष शुरू करने की घोषणा की है। इसे देखते हुए विभागों ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार योजना की शुरुआत नवंबर से होने की उम्मीद है।

गोधन न्याय योजना का भी मिल रहा लाभ : राज्य के भूमिहीनों को गोधन न्याय योजना का भी लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले 76,783 भूमिहीन हैं। इस योजना में करीब दो लाख से ज्यादा पशुपालक और ग्रामीण पंजीकृत हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तीसरा बड़ा फैसला : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूमिहीनों के लिए न्याय योजना राज्य सरकार का तीसरा बड़ा फैसला है। गोधन न्याय योजना की सराहना पूरे देशभर में हो रही है। संसद की स्थायी समिति ने इसे देशभर में अपनाने की अनुशंसा की है।

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 11 अगस्त, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को दिए 9,871 करोड़

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति मद में पांचवीं मासिक किस्त के तहत 9,871 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके साथ ही पात्र राज्यों को अब तक चालू वित्त वर्ष में 49,355 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्यों को यह क्षतिपूर्ति 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दी जा रही है। (प्रेट्र)

मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार और नियामक मिलकर टेलीकाम सेक्टर में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि सेक्टर निवेश के लायक बना रहे।
— सुनील मित्तल
चेयरमैन, भारती एयरटेल

सेंसेक्स	54,554.66	▲ 151.81
निफ्टी	16,280.10	▲ 21.85
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 45,110	▼ ₹176
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹61,765	▼ ₹898
डॉलर	₹74.43	▲ ₹0.17
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 69.75	

एक नजर में

दूरसंचार क्षेत्र को सरकारी समर्थन की जरूरत : मित्तल

नई दिल्ली : भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने उम्मीद जताई है कि सरकार और नियामक दूरसंचार क्षेत्र को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योग को 3+1 (तीन निजी और एक सरकारी कंपनी) के मौजूदा ढांचे को कायम रखने के लिए लंबे समय तक समर्थन की जरूरत है। (प्रेट्र)

जीएसटी के तहत रियल्टी को मिले आइटीसी लाभ

नई दिल्ली : रियल्टी कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने कहा है कि जीएसटी के तहत डेवलपरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ मिलना चाहिए। क्रेडाई का मानना है कि इससे मकान की कीमतों में 10% तक की कमी आ सकती है। (प्रेट्र)

अपने निवेश वादे पर वेदांता ग्रुप अटल : अनिल अग्रवाल

नई दिल्ली : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी अपने विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में 20 अरब डालर तक का निवेश करने को लेकर प्रतिबद्ध है। मंगलवार को कंपनी की 56वीं वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। (प्रेट्र)

जुलाई में 13.2 अरब डालर के 181 सौदे हुए

मुंबई : भारतीय कंपनियों द्वारा विलय और अधिग्रहण सौदों में तीन फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई में 13.2 अरब डालर के 181 सौदे हुए हैं। सलाहकार फर्म ग्रांट थार्नटन द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि जून की तुलना में छह फीसद और सौदों के मूल्य में 33% की वृद्धि हुई है। (प्रेट्र)

बाजार नियामक सेबी ने सात कंपनियों को दिया अर्थ दंड

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने वीडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की खरीद-फरोख्त से जुड़े उल्लंघन के मामले में सात कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने 2017 में अप्रैल से सितंबर के बीच इंडस्ट्री के शेयरों की खरीद-फरोख्त की जांच की थी। जांच से हासिल नतीजों के आधार पर यह कदम उठाया है। (प्रेट्र)

ई-कामर्स पर सख्ती के लिए उठा रहे कदम : पीयूष गोयल

कहा- इन कंपनियों से छोटे कारोबारियों को हो रहा नुकसान

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने देश में बड़ी ई-कामर्स कंपनियों के चलते छोटे व खुदरा कारोबारियों को होने वाले नुकसान की बात स्वीकार की है। सरकार ने कहा है, वह उपभोक्ताओं को लंबे समय तक सस्ती कीमत पर अच्छे उत्पाद मिलना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। सरकार की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें अदालत ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है। दुनियाभर की सरकारें इससे चिंतित हैं और जरूरी कदम उठा रही हैं। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का प्रभार भी संभालने वाले गोयल लंबे समय से घरेलू व्यापारियों का समर्थन करते रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कामर्स) नियम, 2020 में संशोधन से जुड़े सवाल के जवाब में गोयल ने कहा, भारत में करीब छह करोड़ छोटे खुदरा कारोबारी हैं। इनके यहां 12-13 करोड़ लोग काम करते हैं। बड़ी ई-कामर्स कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब उपभोक्ताओं को मजबूर होकर अधिक कीमत पर इनसे सामान खरीदना पड़ेगा। सीसीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मुद्दे को देख रहे हैं। गोयल ने कहा कि कंपनियों ने सीसीआइ द्वारा की जा रही जांच को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुशी है कि सोमवार को भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर उनके सभी प्रयास विफल हो गए। गोयल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद खुदरा दुकानदारों से कहा था कि वे पूरी तरह तैयार होकर सीसीआइ के समक्ष अपना पक्ष रखें, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

मंगलवार को लोस में ई-कामर्स के मामले पर बोलते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ● प्रेट्र

183 नोटिस जारी किए गए: कोई भी उत्पाद किस देश में बना है, इससे संबंधित प्रविधान के उल्लंघन के आरोप में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष के दौरान ई-कामर्स कंपनियों को 183 नोटिस जारी किए हैं। यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में मंगलवार को दी।

महिंद्रा करेगी 29,878 पिक अप वाहन रिकाल

नई दिल्ली, प्रेट्र: घरेलू आटो दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने 29,878 यूनिट पिक अप वाहन रिकाल करेगी। इनकी फ्लूड पाइप में खामी का अंदेशा है। कंपनी ने कहा है कि इन वाहनों की असेंबलिंग ठीक से नहीं हुई हो सकती है। कंपनी ने जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 के बीच बने पिक अप वाहनों की सुरक्षा दृष्टि से जांच की घोषणा की है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि इनमें से कुछ वाहनों की फ्लूड पाइप में खामी हो सकती है। यह खामी 29,878 वाहनों के एक वर्ग तक सीमित है।

बयान में कंपनी ने कहा कि वह संबंधित वाहन मालिकों को व्यक्तिगत रूप से बुलाएगी और खामी मिलने पर उन्हें ठीक कर वाहन लौटा दिया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए कंपनी अपनी तरफ से पूर्व-सक्रियता दिखाते हुए वाहन रिकाल कर रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने कंपनी ने नासिक फैक्ट्री में बने कुछ वाहनों के डीजल इंजन में संभावित खामी को देखते हुए उन्हें रिकाल करने की घोषणा की थी।

एटीएम में नकदी नहीं तो बैंक पर 10,000 रुपये जुर्माना

मुंबई, प्रेट्र : एटीएम में पर्याप्त नकदी नहीं रखना अब बैंकों को भारी पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा है कि अगर नकदी की कमी की वजह से ग्राहक को एटीएम से खाली हाथ लौटना पड़ा तो संबंधित बैंक पर इस वर्ष पहली अक्टूबर से जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआइ ने एक सर्कुलर में कहा है कि किसी भी बैंक के एटीएम में एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक नकदी की कमी स्वीकार्य है। लेकिन अगर उससे ज्यादा देर तक किसी एटीएम में नकदी की कमी पाई गई तो बैंक को प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आरबीआइ का कहना है कि इसका मकसद एटीएम में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कत से ग्राहकों को निजात दिलाना है। आरबीआइ पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी है। वहीं, बैंकों पर देशभर में अपने एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसलिए बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम (वैसी कंपनियां जिन्हें आरबीआइ ने सिर्फ एटीएम परिचालन का लाइसेंस दिया है) आपरेटर्स को अपना तंत्र मजबूत रखना होगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके तहत आने वाले किसी भी एटीएम में नकदी की कभी भी कमी नहीं हो।

आरबीआइ ने कहा है कि किसी भी बैंक के एटीएम में एक माह में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक नकदी की कमी स्वीकार्य है

आरबीआइ ने कहा कि एटीएम में नकदी की कमी को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगेगा। अगर किसी व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी की कमी मिलती है तो जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जिससे उस एटीएम में रकम डालने का करार है।

अब नीरज चोपड़ा कहेंगे, जानकार बनिए सतर्क रहिए

जाब्यू, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का ब्रांड विज्ञापन शुरू हो गया। स्वर्ण पदक विजेता बनने के बाद चोपड़ा का पहला ब्रांड वीडियो आरबीआइ की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में चोपड़ा अमिताभ बच्चन की तरह कहते दिख रहे हैं, 'आरबीआइ कहता है - जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आरबीआइ ने ट्वीट के जरिये चोपड़ा का वीडियो जारी किया जिसमें वह साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। चोपड़ा वीडियो में लोगों से अपने एटीएम के पिन, पासवर्ड जैसी चीजों को किसी के साथ साझा नहीं करने के लिए कह रहे हैं।

विज्ञापन की दुनिया के विशेषज्ञों के मुताबिक ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनने के बाद चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू अभी शीर्ष पर है। जल्द ही बायजूस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी मशहूर कंपनियां उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बना सकती हैं। वैसे, चोपड़ा ने इससे पहले भी जिलेट इंडिया, डिलाइट नेचुरल जैसी कई कंपनियों के लिए विज्ञापन किया है।

टीकाकरण की गति तेज रही तो तीसरी लहर गंभीर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा है कि टीकाकरण की तेज गति जारी रही तो कोरोना की तीसरी लहर गंभीर नहीं होगी। वहीं, मध्य मई के बाद से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और दूसरी लहर का आर्थिक असर कमजोर पड़ने लगा है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने चेताया है कि अभी आर्थिक रिकवरी पूरी तरह से टीकाकरण की प्रगति और कोरोना नियमों के अनुपालन से जुड़ी है। जुलाई में टैक्स संग्रह, ईवे बिल, बिजली और पेट्रोल खपत, निर्यात जैसी कई आर्थिक गतिविधियां कोरोना पूर्व स्तर के पास आ गईं।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर कमजोर होने लगा

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की तरफ से सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 49.8% वयस्क आबादी को पहली डोज और 14.2% को दोनों डोज लग चुकी है। सीरो सर्वे के मुताबिक छह वर्ष से अधिक आयु वाली 67.6 फीसद आबादी में एंटीबाडी विकसित हो चुकी है। वैसे ही, टीके की पहली डोज लेने वाले 81 फीसद और दोनों डोज लेने वाले 89 फीसद लोगों में एंटीबाडी पाई गई। टीके की डोज नहीं लेने वाले 62.3 फीसद लोगों में एंटीबाडी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 45-59 वर्ष से अधिक आयु के 85.1 फीसद लोगों में इम्युनिटी विकसित हो चुकी है, जिस कारण तीसरी लहर के गंभीर असर की आशंका कम है। अब तक इस आयु वर्ग के लोग ही सबसे अधिक गंभीर हो रहे थे।

अगस्त के पहले सप्ताह में निर्यात 50% बढ़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : निर्यात में बढ़ोतरी का रुख जारी है। अगस्त के पहले सप्ताह (सात अगस्त तक) में वस्तुओं का निर्यात पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 50.45 फीसद बढ़ा। वहीं, वर्ष 2019 की समान अवधि के मुकाबले इसमें 27.51 फीसद का इजाफा दर्ज किया गया। हालांकि कंटेनर की किल्लत की वजह से निर्यात लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे निर्यात प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह में 7.41 अरब डालर का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.92 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। वर्ष 2019 की समान अवधि में 5.81 अरब डालर का निर्यात हुआ था।

इस वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में इंजीनियरिंग उत्पाद, जेम्स व ज्वैलरी एवं पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में भारी बढ़ोतरी रही।

कंटेनर की कमी से निर्यात लागत बढ़ना बड़ी चुनौती ● फाइल फोटो

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह मेंवस्तुओं के आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 69.88 फीसद तो वर्ष 2019 की समान अवधि के मुकाबले 30.72 फीसद की बढ़ोतरी रही। इस वर्ष अगस्त के पहले सात दिनों में 10.45 अरब डालर का आयात किया गया।

निर्यात लागत में पांच-आठ फीसद का इजाफा

ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआइ) के मुताबिक कोरोना-पूर्व काल में भारत से अमेरिका माल भेजने के लिए 20 फीट कंटेनर की लागत 1,800 डालर आती थी जो बढ़कर 6,000 डालर के पास पहुंच गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना काल में कंटेनर उन देशों में फंस गए जिनका निर्यात कम है। वहां से कंटेनर वापस नहीं आ पा रहे हैं। टीपीसीआइ का अनुमान है कि कंटेनर में माल भेजने की कीमत बढ़ने से निर्यात लागत में पांच-आठ फीसद तक का इजाफा हुआ है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुएं महंगे दाम पर बिकेंगी। इससे निर्यात प्रभावित होगा। कंटेनर की कमी को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के देश आसपास के देशों को निर्यात आर्डर देने लगे हैं क्योंकि भारत से उनका माल आने में काफी वक्त लग रहा है।

कोरोना-काल में देश में घट गए अरबपति : सीतारमण

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या घटकर 136 रह गई है। उससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 141 था। इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित सकल कुल आय के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में जो आयकर विवरण जमा कराए गए थे, उसमें एक वर्ष के दौरान कुल आय 100 करोड़ रुपये से अधिक बताने वालों की संख्या 77 थी।

वित्त मंत्री के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रत्यक्ष कर के तहत अरबपति शब्द की कोई कानूनी या प्रशासनिक परिभाषा तय नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल, 2016 से वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया गया है और इसके बाद से सीबीडीटी ने व्यक्तिगत करदाताओं की संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करना बंद कर दिया है।

गरीबी से जुड़े आंकड़ों को साझा करते हुए सीतारमण ने कहा कि तेंदुलकर समिति की गणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या 2011-12 में लगभग 27 करोड़ थी। उधर, राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार अवैध लेनदेन में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ब्लाक चेन तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

आसाराम प्रकरण में दवाव डालने का लगाया आरोप

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आसाराम और नारायण साईं प्रकरण के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की एक याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका दाखिल करते हुए महेंद्र चावला ने बताया कि उन पर गवाही से पीछे हटने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और रिश्वत देने का प्रयास भी किया गया। (राब्यू)

एलगार परिषद मामले में आरोप पत्र दाखिल

मुंबई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने वर्ष 2018 के एलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) तथा भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धाराओं के तहत एक विशेष अदालत में सोमवार को आरोप पत्र (ड्राफ्ट) पेश किया। विशेष अदालत 23 अगस्त को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करेगी। (प्रेट्र)

पूर्व सांसद डीपी समेत दो अन्य अभियुक्तों को राहत नहीं

नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गाजियाबाद जिले के विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन के आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मंगलवार को कोर्ट ने पाला उर्फ लक्कड़ पाल व परनीत भाटी के मामले में लगातार तीन घंटे सुनवाई की। अब 17 अगस्त को सीबीआइ की तरफ से बहस की जाएगी। (जासं)

फर्जीवाड़ा मामले में आजम खां व बेटे को मिली जमानत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे मुहम्मद अब्दुल्ला को कथित धोखाधड़ी और दस्तावेज के फर्जीवाड़े मामले में जमानत दी जाए। हालांकि यह दो हफ्ते के अंदर निचली अदालत द्वारा शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने पर निर्भर करेगा। आजम ने अपने बेटे को दूसरा पैन कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज के जरिये जन्म की गलत तारीख प्रदर्शित करने में कथित तौर पर मदद की थी। (प्रेट्र)

पंजाब सीमा पर फिर सुनाई दी ड्रोन की आवाज

जागरण संवाददाता, अमृतसर

पंजाब के सीमावर्ती गांव ढालेके में ड्रोन से फेंके गए आरडीएक्स टिफिन बम के 48 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से फिर नापाक हरकत की गई। सोमवार देर रात को बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर बीओपी मुल्लाकोट पर फिर ड्रोन की आवाज सुनी। जब तक बीएसफ जवान फायरिंग कर पाते तब तक ड्रोन गायब हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन हथियारों का जखीरा फिर भारतीय क्षेत्र में गिराकर गया है।

पाकिस्तानी ड्रोन ने शनिवार रात जहां टिफिन बम गिराए थे, यह स्थान (मुल्लाकोट बीओपी) वहां से मात्र पांच किलोमीटर दूर है। घटना का पता चलते ही एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना, डीएसपी गुरिंदर सिंह नागरा डीएसपी गुरप्रताप सिंह सहोता ने बीएसएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान शुरू कर दिया। शाम तक टीम को कहीं से कोई हथियार या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि मुल्लाकोट, बच्चीविंड, शहूरा और बेलवाड़ गांव में पांच सौ से ज्यादा जवानों के साथ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गांव के लोगों का भी सहयोग लिया गया है। लोपोके, रमदास और अजनाला थाने की पुलिस ने आठ संदिग्ध मजदूरों को पूछताछ के लिए राउंडअप किया है। बताया जा रहा है कि यह श्रमिक अकसर भारत-पाक सीमा के साथ सटे खेतों में काम करते हैं।

अमृतसर जिले के सीमावर्ती गांव ढालेके से बरामद आरडीएक्स टिफिन बम को सोमवार को एनएसजी के कमांडो, एसएसपी देहाती गुलनीत सिंह खुराना, डीएसपी गुरिंदर सिंह नागरा और डीएसपी गुरप्रताप सिंह सहोता ने इस रोबोट के जरिए डिफ्यूज कराया। जागरण

एनएसजी ने रोबोट के साथ डिफ्यूज किया टिफिन बम : उधर, शनिवार रात गांव ढालेके से बरामद तीन किलो बारूद, टिफिन बम और पांच ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए सोमवार को एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) के कमांडो को सीमा पर बुलाया गया। जवानों ने आठ फीट का बड़ा गड्ढा बनाया और सारे विस्फोटक पदार्थ को उसमें डाल दिया। इसके बाद सभी अफसर गड्ढे से दो हजार गज दूर चले गए। दो कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रोबोट को रिमोट से कंट्रोल करने लगे।

सुरक्षा जांचने के लिए उड़ाया गया एयरफोर्स का ड्रोन खेतों में गिरा

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : पंजाब के गुरदासपुर जिले में मंगलवार को एयरफोर्स की ओर से उड़ाया गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (एआरपीए) ड्रोन तकनीकी कारणों से खेतों में गिर गया। एयरफोर्स के जवानों ने डेढ़ घंटे की तलाशी के बाद उसे ढूंढकर अपने कब्जे में लिया। डीएसपी भारत भूषण ने कहा कि एयरफोर्स ने खेतों में गिरे ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी देने से इन्कार कर दिया। कलानौर ब्लाक समिति के वाइस चेयरमैन मनदीप सिंह पन्नू ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे गांव मालोगिल, मुस्तफापुर, खानोवाल क्षेत्र में लगातार डेढ़ घंटे तक एक हेलीकाप्टर उड़ता देखा गया। दहशत का माहौल बन गया था। किसान रछपाल सिंह के खेतों में ड्रोन मिला, जिसे अधिकारियों व जवानों ने अपने कब्जे में लिया।

पढ़ाई को लेकर झगड़े में किशोरी ने कराटे बेल्ट से मां का गला घोंटा

- माता-पिता बेटी को बनाना चाहते थे डाक्टर, लड़की कर रही थी विरोध

ठाणे, प्रेट्र : नवी मुंबई में पढ़ाई को लेकर झगड़े के बाद 15 वर्षीय एक किशोरी ने कराटे की बेल्ट से मां की गला घोंट कर हत्या कर दी। यह घटना 30 जुलाई को नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में हुई। लड़की के माता-पिता चाहते थे कि उनकी बेटी डाक्टर बने और इसके लिए उन्होंने उसे नीट (राष्ट्रीय सह पात्रता प्रवेश परीक्षा) कोचिंग में दाखिल करवा दिया था। लेकिन लड़की मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसकी अपनी 40 वर्षीया मां के साथ झगड़ा होता था।

रबाले थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 27 जुलाई को लड़की के पिता ने मोबाइल फोन से खेलने पर डांटा था जिसके बाद उसने घर छोड़ दिया और अपने चाचा के यहां चली गई। अधिकारी ने कहा कि उसके बाद मां वहां गई और उसे वापस बुलाकर ले आई। लड़की ने कहा कि वह पढ़ाई को लेकर प्रताड़ना से दुखी है और वह थाने जाकर अपने माता-पिता के खिलाफ शिकायत करेगी। इसके बाद महिला बेटी को लेकर थाने पहुंची जहां पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझाया।

30 जुलाई को महिला ने फिर से पढ़ाई को लेकर बेटी को फटकार लगाई। लड़ाई के दौरान महिला ने कथित रूप से चाकू लेकर बेटी को धमकाया। इस बात से डर कर कि मां उसे मारने जा रही है, लड़की ने उसे धक्का दे दिया जिससे महिला गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। अर्ध बेहोशी की हालत में महिला ने समीप पड़े कराटे बेल्ट को पकड़ने की कोशिश की। यह देख लड़की ने बेल्ट पकड़ लिया और उससे मां का गला घोंट दिया। पूछताछ में लड़की ने अपराध स्वीकार कर लिया। किशोरी को सोमवार को हिरासत में लिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

साइबर ठगी के अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़ा छात्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रोहतक

लंबे समय से फरार चल रहे साइबर ठगी के अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े बीएससी के छात्र को रोहतक पुलिस की इकोनामिक सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपने पते बदले, लेकिन आखिरकार मंगलवार को उसे दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से शिकंजे में ले लिया गया। अब आरोपित को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

हरियाणा में रोहतक जिले के कंसाला गांव निवासी युवक के खाते से पैसे निकाले जाने के मामले की जांच रोहतक पुलिस की इकोनामिक सेल के जांच अधिकारी दिनेश कुमार कर रहे हैं। जांच के बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बहादुरपुर गांव निवासी गौरव कुमार मिश्रा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सिमलधार गांव निवासी नवीन चंद्र रावत, कानपुर के रहने वाले जफर मंसूरी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में उप्र के कासगंज जिले के अड्डुपुर गांव निवासी बीएससी का छात्र मोहित भी जांच के दायरे में आया था, जो दिल्ली में रहता था और उसके खाते में चार माह के अंदर करीब 38 लाख रुपये की ट्रांजक्शन हुई थी। जांच अधिकारी दिनेश कुमार ने अपनी टीम के साथ मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में दबिश दी, जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

अलग-अलग दिए थे पते : आरोपित ने दिल्ली के करोल बाग स्थित बैंक में तारा भवन चंद्र विहार मंडावली दिल्ली का पता दे रखा था, लेकिन आरोपित कभी भी वहां पर नहीं रहा। आरोपित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए दिल्ली की राजपुरी कालोनी का भी पता दिया था।

67 वर्ष के बुजुर्ग से सोच समझकर की थी 19 वर्ष की युवती ने शादी

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ : उन्नीस वर्षीय युवती ने सरसठ वर्ष के बुजुर्ग के साथ सोच समझकर निकाह किया है। इसमें न किसी पर दबाव डाला गया है और न ही किसी तरह की साजिश है। पलवल के पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने अपनी रिपोर्ट में मंगलवार को यह स्पष्ट किया है। पुलिस अधीक्षक को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पीठ ने इस निकाह की जांच करने के लिए कहा था।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट में दोनों ने सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर परिवार वालों से खतरा बताया था। दोनों की उम्र में अंतर देख आश्चर्य हुआ, इसलिए पीठ ने पलवल के पुलिस अधीक्षक को जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने युवती को हथीन (पलवल) के एसडीएम के सामने पेश कर बयान दर्ज कराए। उसने कहा कि निकाह अपनी मर्जी से किया है।

...जब बचाव कार्य में जुटे जवान के सामने आ गया मां का शव

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

- दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चार ग्रामीणों की मौत, 19 लोग घायल
- मुख्यमंत्री ने पुलिस जवान कवासी से फोन पर बात कर उन्हें बंधाया ढांढस

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार में सोमवार की शाम विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पोखर में पलट जाने से चार लोगों की मौत हो गई। इस दौरान बचाव कार्य के दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के जवान के साथ जो हुआ, उसने वहां मौजूद सभी के दिल को दहला दिया।

जवान वसूराम कवासी ने ट्राली के नीचे से एक महिला का शव निकालकर जब उसका चेहरा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शव उसकी मां फूके कवासी का था। यह खबर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची तो उन्होंने जवान वासूराम से मंगलवार को टेलीफोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

दरअसल, कटेकल्याण क्षेत्र के हीरानार में एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के बाद वहां मची चीख-पुकार को सुनकर गश्त पर निकले डीआरजी के जवान मौके पर पहुंचे और फौरन बचाव कार्य शुरू कर दिया। एक-एक कर सभी को निकालने लगे। 19 ग्रामीण घायल मिले। जवान वासू ने जब एक महिला का शव निकाला तो वह उसकी मां फूके कवासी का निकला। इससे वह रोने लगा तो साथी जवानों ने उसे संभाला। हादसे में सभी घायलों को डीआरजी के जवानों ने कटेकल्याण के अस्पताल में भर्ती करवाया है।

बची हुई सजा अपने देश की जेल में काटेगा जर्मन बंदी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : चरस तस्करी के आरोप में गोरखपुर की जेल में 10 साल के कारावास की सजा काट रहे जर्मन नागरिक मैनफ्रेंड को मंगलवार की दोपहर दिल्ली भेज दिया गया। यहां साढ़े छह साल की सजा पूरी कर चुका मैनफ्रेंड बची हुई साढ़े तीन साल की सजा जर्मनी की जेल में काटेगा। सशस्त्र सीमा बल ने 31 अक्टूबर, 2014 को जर्मनी के सजसेन स्थित सिरायू लेसिंग स्ट्रीट निवासी मैनफ्रेंड बैरेंड को चार किलोग्राम चरस के साथ महराजगंज के सोनौली बार्डर से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बताया था कि वह भैरहवा से 1.20 लाख रुपये में चरस खरीदकर गोवा ले जा रहा था। मैनफ्रेंड को पहले महराजगंज, फिर एक अक्टूबर, 2015 को गोरखपुर की जेल भेज दिया गया। मैनफ्रेंड की पत्नी जूलिया कैफर ने भारत आकर पैरवी की।

प्रत्येक बुरे अनुभव में भी एक अच्छी सीख छिपी होती है

उच्च सदन में ओछी हरकत

संसद का मानसून सत्र हंगामे के लिए ही अधिक जाना जा रहा है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो, जब संसद में हंगामे के कारण उसकी कार्यवाही बाधित न होती हो। कभी-कभी तो विरोध में विपक्ष सारी हदें पार कर जाता है। दुर्भाग्य से ऐसा राज्यसभा में भी होता है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वहां कहीं अधिक धीर-गंभीर चर्चा होती है। यह देखना दयनीय है कि जब विपक्ष को संसद की गरिमा बनाए रखने के प्रति सचेत रहना चाहिए, तब वह इससे बिल्कुल बेपरवाह दिखता है। इसका प्रमाण गत दिवस तब मिला, जब राज्यसभा में विपक्षी दल के एक सांसद महासचिव की मेज पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने नियम पुस्तिका आसन की ओर फेंकी। यह शर्मनाक कृत्य एक कांग्रेसी सांसद ने किया। इससे भी शर्मनाक यह रहा कि अन्य विपक्षी सांसद अमर्यादित आचरण करने वाले सांसद के समर्थन में तालियां बजा रहे थे। जिस समय राज्यसभा में यह सब हो रहा था, लगभग उसी समय कश्मीर यात्रा पर गए राहुल गांधी यह कह रहे थे कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है।

आखिर संसद में बोलने का यह कौन सा तरीका है कि कुर्सी-मेज पर चढ़ जाया जाए? यह अमर्यादित आचरण इसलिए किया गया, क्योंकि कृषि कानूनों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदल दिया गया। क्या अल्पकालिक चर्चा में विपक्ष अपनी बात नहीं कह सकता था? सवाल यह भी है कि आखिर कृषि कानूनों पर चर्चा के बहाने इन कानूनों को वापस लेने की जिद का क्या औचित्य? इस तरह कृषि कानून वापस ले लेने से तो कोई भी कानून सलामत नहीं बचेगा। क्या विपक्ष यह चाहता है कि संसद की ओर से बनाए गए कानून सड़क पर बैठे लोगों के कहने पर वापस ले लिए जाएं? वास्तव में विपक्ष का उद्देश्य संसद में कोई सार्थक चर्चा करना दिखता ही नहीं। यदि उसकी दिलचस्पी विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात जनता तक पहुंचाने में होती तो वह संसद को इस तरह बाधित नहीं करता। विपक्ष ने संसद को किस तरह बंधक बना लिया है, इसका पता इससे चलता है कि वह उन मुद्दों पर चर्चा करना पसंद कर रहा है जिन पर हंगामा करने से उसे राजनीतिक नुकसान होने का अंदेशा है। इसी कारण गत दिवस उसने लोकसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक पर हंगामा करने के बजाय बहस में भाग लेना ठीक समझा। इस विधेयक पर बहस में शामिल होकर विपक्ष ने यही साबित किया कि वह अन्य मुद्दों को भले ही गंभीर बता रहा हो, लेकिन उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष को यह आभास हो तो बेहतर कि संसद में हंगामा करके वह अपना ही अहित कर रहा है।

भर्तियों में सेंधमारी

उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं पर साल्वर गिरोह किस तरह आंख गड़ाए बैठे होते हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी) इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर टीजीटी और पीजीटी (प्रवक्ता) की परीक्षा कराई है, जिसमें 15 हजार से अधिक पद हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या को देखते हुए ही साल्वर गिरोह ने इस परीक्षा में सेंधमारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। पुलिस ने गिरोह के दस सदस्यों को पकड़ा जरूर है और उनसे पूछताछ में जो जानकारियां मिली हैं, वह गिरोह के अंतरराज्यीय होने और एक पुख्ता नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं। इससे पहले पुलिस ने टीईटी (शिक्षक अर्हता परीक्षा) में भी बड़े साल्वर गिरोह का राजफाश किया था और उसका सरगना जेल में है। टीजीटी की सेंधमारी में शामिल गिरोह के सदस्य उसके भी संपर्क में थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब परीक्षाओं में सेंधमारी के लिए अलग-अलग गिरोह परस्पर समन्वय कर आपरेट कर रहे हैं और उनके निशाने पर दूसरे राज्य की भर्ती परीक्षाएं भी हैं और वे पेपर आउट कराने या साल्वर बैठाकर अभ्यर्थी को पास कराने में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के प्रयोग में भी दक्ष हैं। ऐसे उपकरण गिरोह के सदस्यों के पास बरामद भी हुए हैं। वस्तुतः साल्वर गिरोह के लिए परीक्षाओं में सेंधमारी कमाई का बड़ा जरिया है। पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे की परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई थी कि एक-एक पद के लिए दस से पंद्रह लाख तक में सौदे होते हैं। गिरोह की निगाह उन परीक्षाओं पर ज्यादा होती है, जिनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। टीईटी और टीजीटी में इसीलिए सेंधमारी की कोशिश हुई। आवश्यक है कि ऐसे गिरोहों को पूरी तरह समाप्त किया जाए और परीक्षा व्यवस्था को इतनी मजबूती दी जाए कि उसमें सेंध न लग सके। जब तक साल्वर गिरोहों की जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं की जातीं, परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़े होते रहेंगे।

> जब तक भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले साल्वर गिरोहों की जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं की जातीं, परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़े होते रहेंगे

अधर में अटकी विपक्षी एकता

संदीप घोष

> विपक्ष ने उत्साह तो खूब दिखाया है, लेकिन उसमें गंभीरता का अभाव और शोर-शराबा अधिक है

अवधेश राजपूत

अगले लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय शेष है, परंतु भाजपा विरोधी ताकतें एकजुट होना शुरू हो गई हैं। यह अनपेक्षित भी नहीं है। चूंकि कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है तो यही सहमति बन रही है कि सभी विपक्षी दलों द्वारा मिल-जुलकर ही भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। पिछले आम चुनाव से पहले भी ऐसी कवायदें हुई थीं, लेकिन कांग्रेस के कारण परवान नहीं चढ़ सकीं। दरअसल कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस को अपने दम पर सत्ता में वापसी की संभावनाएं दिखने लगीं और उसने भाजपा विरोधी एकजुटता से कन्नी काट ली। इस बार ऐसी एकजुटता में हैरानी की बात यही है कि यह चुनाव से करीब तीन साल पहले ही शुरू हो गई है। बंगाल में भाजपा को लगे झटके ने विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी है। इसी कड़ी में तृणमूल को राष्ट्रीय स्तर पर गुंजाइश दिखने लगी है। एक वर्ग द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने अपनी भारी राजनीतिक पूंजी गंवा दी है और इस महामारी के कारण होने वाले आर्थिक आघात से सरकार को और नुकसान पहुंच सकता है।

नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे अभियान से भी विपक्ष को बड़ी उम्मीद है, जिसकी आंच खरीफ सीजन के दौरान और तेज की जा सकती है। इससे भी बढ़कर उनकी उम्मीदें अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत विरोधी भावनाओं के उबाल पर टिकी हैं। विशेषकर अमेरिका में बाइडन प्रशासन के सत्तारूढ़ होने के बाद उनकी उम्मीदों को नए पंख लगे हैं, जिसकी दृष्टि में मोदी सरकार की छवि दक्षिणपंथी हिंदू सरकार की है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचा सकती है। इन पहलुओं को मिलाकर यही लगता है कि मोदी सरकार को उसके शेष कार्यकाल के दौरान रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर विपक्ष को नई संजीवनी दी जा सकती है।

यदि किसी को लगा हो कि भाजपा इस सबसे बौखला जाएगी तो उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। सरकार कोरोना की दूसरी लहर के सबसे बदतर दौर से पार पा चुकी है। देश में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। राजनीतिक रूप से मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया। उन्होंने कई नए चेहरों को जगह दी। इससे शासन-प्रशासन में नई ताजगी आई। बदलाव की बयार स्पष्ट दिख रही है। विशेषकर स्वास्थ्य जैसे महकमे में, जिस पर तात्कालिक रूप से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों को लेकर निर्णायक फैसले किए गए, जहां चुनाव दस्तक देने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर से जुड़ी सर्वदलीय बैठक भी एक बड़ी पहल रही। मानसून सत्र को बाधित करने की विपक्षी कोशिशों से बेपरवाह सरकार अपने महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी है। पेगासस जासूसी मामले पर हंगामे से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा।

अफगानिस्तान से लेकर चीन के मोर्चे पर विदेश नीति में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हालिया दौरे और लद्दाख सीमा पर चीनी सेना के पीछे हटने से यह प्रत्यक्ष दिखा। जुलाई में अर्थव्यवस्था ने भी दूसरी लहर से उबरने के शुरुआती संकेत दिए। वहीं ओलिंपिक में भारत के बढ़िया प्रदर्शन ने भी देश का मिजाज बेहतर बना दिया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने सब कुछ नियंत्रण में होने का ही आभास कराया है।

विपक्ष ने उत्साह तो खूब दिखाया, लेकिन उसमें गंभीरता एवं गहराई का अभाव और शोर-शराबा अधिक रहा। उसने मानसून सत्र में मिला अवसर भी गंवा दिया। सार्थक मुद्दों पर बहस के जरिये सरकार को घेरने के बजाय वह सदन के भीतर और बाहर हंगामे में लगा रहा। इससे कोई हित पूरा न हुआ। विपक्ष की अगंभीर और नकारात्मक छवि से सरकार को ही लाभ पहुंचा।

भाजपा के राष्ट्रीय विकल्प को आकार देने के लिए नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी एक हाई-प्रोफाइल बैठक की, जिसमें विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। चूंकि कांग्रेस इस सबसे बहुत असहज थी और वह नहीं चाहती थी कि किसी को पहली चाल चलने का फायदा मिले, इसलिए उसने जल्दबाजी में एक चाय पार्टी का आयोजन किया, ताकि भाजपा विरोधी ध्रुव में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। निचली पांत के उसके कई नेता यह कहते दिखे कि कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका के बिना विपक्षी एकता का कोई प्रयास फलीभूत नहीं हो सकता। ऐसे आयोजन में बसपा जैसे दलों की अनुपस्थिति से कुछ संदेह उपजे। वहीं इसमें शामिल हुई सपा फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रही। इस प्रकार देखा जाए तो मंच सजने से पहले ही विरोधाभास सतह पर उभरने लगे हैं। फिलहाल विपक्षी एकता के भविष्य की धुरी प्रशांत किशोर पर टिकी है, लेकिन कोई चुनावी सलाहकार किसी करिश्माई और विजनरी नेता का विकल्प नहीं बन सकता। वैसे भी वह कोई जयप्रकाश नारायण या लोहिया तो हैं नहीं।

ऐसे में क्या भाजपा को आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए? मोदी-शाह के नेतृत्व वाली भाजपा किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेती। वे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का रण बहुत टेढ़ी खीर है और कई लोग इसे अगले आम चुनाव का सेमीफाइनल भी बता रहे हैं। वे विपक्ष के बीच भ्रम की इस स्थिति के दौरान अपनी जीत सुनिश्चित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले वाराणसी दौरे में इसका बिगुल पहले ही बज चुका है। आने वाले दौर में पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी बड़ी परियोजनाओं से इस अभियान को और गति मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिले घाव भी अब भरने लगे हैं। ऐसे में अगर कोई अप्रत्याशित त्रासदी न घटित हो तो कुछ फिसली सियासी जमीन 2022 से पहले फिर वापिस हासिल हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में किसी महागठबंधन होने के आसार कम हैं। बसपा और सपा दोनों कांग्रेस को बहुत ज्यादा भाव नहीं देंगी। प्रियंका वाड्रा को लेकर हो रहे अतिरेकपूर्ण दावों के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन फीका ही रहने का अनुमान है। बहरहाल विपक्षी खेमे में तृणमूल भले ही 'खेला होबे' की हुंकार भर रही हो, लेकिन वह शायद मोदी की उस प्रतिभा से परिचित नहीं जो खेल से पहले ही उसकी काया पलटने की कूवत रखते हैं। ऐसे में उन्हें कमतर आंकना भारी भूल होगी।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

पाकिस्तान-बांग्लादेश के अभागे हिंदू

राजीव सचान

> पता करें कि हाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले की घटनाओं की किस दल ने निंदा की?

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि अफगानिस्तान में बचे-खुचे सिखों-हिंदुओं को जल्द भारत लाया जाए। उन्होंने विदेश मंत्री को लिखे पत्र में यह तो लिखा है कि अफगानिस्तान में रह रहे करीब सात सौ सिखों और हिंदुओं को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें भारत लाकर नागरिकता दी जाए या नहीं? वह शायद इसलिए संकोच कर गए, क्योंकि कांग्रेस उन दलों में अव्वल थी, जिसने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का जी भरकर विरोध किया था। जब यह कानून विधेयक के रूप में था, तब खुद शेरगिल ने उसकी व्याख्या कम्युनल एटम बम के रूप में की थी। शायद इसी कारण वह ऐसा कुछ नहीं कह सके कि अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं को भारत लाकर उन्हें देश की नागरिकता दी जाए। पिछली सदी के आखिरी दशक में अफगानिस्तान में दो लाख से अधिक हिंदू और सिख थे, लेकिन अब करीब 650 सिख और 50 हिंदू ही वहां बचे हैं। यदि इन बचे-खुचे सिखों और हिंदुओं को भारत लाया जाता है तो अफगानिस्तान इन दोनों समुदायों से रिक्त हो जाएगा-शायद हमेशा के लिए। कुछ दशकों बाद यही स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बन सकती है, क्योंकि इन दोनों ही देशों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं को सताने का सिलसिला कायम है।

पिछले दिनों पाकिस्तान में एक मंदिर पर हमला कर वहां प्रतिमाओं को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। चूंकि इस खौफनाक घटना के वीडियो सामने आ गए इसलिए पाकिस्तान सरकार भी सक्रिय हो गई और वहां के मुट्ठी भर मानवाधिकारवादी भी। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की ओर से यह कहा गया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मंदिर को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, लेकिन ऐसी बातों से किसी को उत्साहित नहीं होना चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि जिस इलाके में मंदिर को निशाना बनाया गया, वहां के कुछ हिंदुओं के पलायन करने की भी खबरें हैं। एक हकीकत यह भी है कि इस तरह की घटनाओं के बाद जो त्वरित कार्रवाई होती दिखती है, वह अक्सर दिखावटी और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के इरादे से होती है। पिछले साल पाकिस्तान में जब एक मंदिर को जलाने के बाद तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया गया था, तब भी पाकिस्तान

पाकिस्तान में क्षतिग्रस्त मंदिर। फाइल

सरकार ने सक्रियता दिखाई थी और कई लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वहां के हिंदुओं ने मंदिर जलाने-तोड़ने वालों को कथित तौर पर माफ कर दिया है। यह खबर सरकार के हवाले से आई, जिस पर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, लेकिन सरकार तो यही साबित करने पर आमादा थी कि हिंदुओं ने दंगाइयों को माफ कर दिया है। इस कारण आगे की कार्रवाई इसी हिसाब से हुई।

पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले की घटनाएं आम हैं। हर चाह-छह माह बाद किसी न किसी मंदिर पर हमला करने या फिर उसे अपवित्र करने की खबर आती ही रहती है। पाकिस्तान में जैसे मंदिरों पर हमले आम हैं, वैसे ही वहां के हिंदुओं और सिखों की लड़कियों को जबरन उठाकर उनसे निकाह करने की खबरें भी। शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जाता हो जब पाकिस्तान में किसी हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका निकाह किसी मुस्लिम से कराने की खबर न आती हो। इस काम में पुलिस, प्रशासन और अदालतें उन्हीं की मदद करती हैं, जो लड़की का अपहरण करते हैं। यही कारण है कि वहां के हिंदुओं को जब भी मौका मिलता है, किसी बहाने भारत आ जाते हैं और फिर लौटने से इन्कार करते हैं।

भारत विभाजन के समय पाकिस्तान में 21 प्रतिशत हिंदू थे। अब उनकी संख्या महज डेढ़ प्रतिशत रह गई है। पाकिस्तानी इस पर हैरान नहीं होते। वे यह बहाना गढ़ते हैं कि दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश बना तो हिंदुओं की बड़ी संख्या वहीं रह गई। सच्चाई यह है कि 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 14 प्रतिशत थी। अब उनकी संख्या आठ प्रतिशत रह गई है। स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू या तो भारत भाग आए या फिर जबरन मुस्लिम बना दिए गए। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने 2016 में कहा था कि 1930 तक बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। कहना कठिन है कि 1930 तक पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या होगा, लेकिन कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वहां के अन्य अल्पसंख्यकों की तरह हिंदुओं का भविष्य भी अंधकारमय है।

बांग्लादेश में भले ही पाकिस्तान जितना धार्मिक अतिवाद न दिखता हो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के लिए हालात अच्छे नहीं। इसका प्रमाण बीते दिनों खुलना जिले में चार मंदिरों पर हमला है। इस हमले के दौरान मंदिरों के आसपास रहने वाले हिंदुओं को भी निशाना बना गया। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान-यहां के हिंदू, सिख सताए जाने की स्थिति में भारत की ओर ही निहारते हैं, लेकिन भारत के लोग और खासकर यहां के विपक्षी दल उनके बारे में एक शब्द भी बोलना पसंद नहीं करते। पता करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले की घटनाओं की किस दल ने निंदा की? सच तो यह है कि इन दलों का बस चले तो वे नागरिकता संशोधन कानून पर अमल भी न होने दें। आज जब जरूरत इस कानून में ऐसे संशोधन करने की है कि उक्त तीनों देशों के हिंदुओं और सिखों को कहीं आसानी से भारत की नागरिकता दी जा सके, तब दुर्भाग्य से कोई भी विपक्षी दल या फिर लिबरल बुद्धिजीवी इसकी पैरवी करने वाला नहीं दिखता। उनकी भी खामोशी देखें, जो रोहिंग्या को शरण देने के लिए बेचैन थे।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

सिंहावलोकन

हमें अपने किये गए कार्यों का लेखा-जोखा सदैव स्मरण रहना चाहिए। जीवन में बीते हुए दिनों को मुड़कर देखने पर हमें बहुत अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगे कार्य करें तो निश्चित ही सफलता की ओर उन्मुख होते जाएंगे। जंगल के राजा शेर से हम एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। वह है पीछे मुड़कर देखना, फिर आगे बढ़ जाना। इसे दूसरे शब्दों में सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन शेर को विशिष्ट बनाता है। उसे आत्मविश्वास से भर देता है। उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ा देता है। इसी गुण के कारण वह गलतियां बहुत कम करता है। इसीलिए उसे जंगल के राजा की उपाधि प्राप्त है। यदि हम भी शेर की भांति उसके सिंहावलोकन के गुण को आत्मसात कर लें तो अपने कार्यक्षेत्र के राजा कहला सकते हैं। इससे हमारे भीतर क्षमताओं का विकास होगा। यदि हम पीछे मुड़कर देखने, फिर आगे बढ़ने का गुण विकसित कर लें तो निश्चित ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह गुण हमारे किए गए कार्यों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है।

सिंहावलोकन करने वाला व्यक्ति आत्मविकास के मार्ग पर एक कदम आगे होता है। उसके निर्णय सटीक होते हैं। उसकी गलती करने की प्रायिकता अत्यंत न्यून हो जाती है। सिंहावलोकन का अभिप्राय आत्मावलोकन से भी है। वास्तव में शेर पीछे मुड़कर आत्मावलोकन ही तो करता है। वह अपने किए गए कार्य अथवा तय किए गए मार्ग को देखता है। यही हमें भी करना है। जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की तय की गई यात्रा का अवलोकन, उस पर मंथन अवश्य करना है। इसी मंथन से हम यात्रा के मार्ग की सफलता अथवा सार्थकता का निर्णय ले सकते हैं। सिंहावलोकन निश्चित ही हमारी जीवन यात्रा की सफलता का बड़ा कारक बन सकता है। बस हमें इसे जीवन में प्रवर्तित कर कार्यक्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने की आवश्यकता है।

ललित शौर्य

स्कूली शिक्षा की बदलती तस्वीर

सुधीर कुमार

> गत वर्षों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना और उसके विभिन्न घटकों में महत्वपूर्ण सुधार दिखे हैं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में समग्र शिक्षा अभियान-2 को मंजूरी दी है। यह प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का कार्यक्रम है, जो 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 12 तक उन्नयन, बालिका छात्रावासों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था तथा स्कूलों को ज्ञान के साथ कौशल प्रदान करने के केंद्र के रूप में परिणत किया जाना है।

देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना और स्कूली शिक्षा के विभिन्न घटकों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं। दरअसल 2012-13 में जहां देश के 54 फीसद स्कूलों तक ही बिजली पहुंची थी, वहीं अब 83.4 फीसद स्कूलों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। सात साल पहले केवल 36 फीसद स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा थी, जो अब 90 फीसद स्कूलों में उपलब्ध है। बालिकाओं को स्कूलों के प्रति आकृष्ट करने तथा स्वच्छता के लिए 97 फीसद स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाए गए हैं। सरकार ने छात्रों को पढ़ाई का माहौल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि देश के 84 फीसद स्कूलों में पुस्तकालय या स्वाध्याय के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था है। देश के 82 फीसद स्कूलों में विद्यार्थियों की साल में एक बार स्वास्थ्य जांच भी होती है। सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी खयाल रख रही है। देश में पहली बार स्कूली शिक्षा में पुरुष शिक्षकों के मुकाबले महिला शिक्षकों की सहभागिता बढ़ी है। दरअसल 2019-20 में कुल शिक्षकों में पुरुष शिक्षकों की संख्या 47.7 लाख, जबकि महिला शिक्षकों की संख्या 49.2 लाख दर्ज की गई है, जबकि 2012-13 में महिला शिक्षकों के मुकाबले पुरुष शिक्षकों की संख्या साढ़े छह लाख अधिक थी। इसके विपरीत अब महिला शिक्षकों की संख्या पुरुषों से डेढ़ लाख अधिक है। प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो वर्तमान में 15.8 लाख पुरुष शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि महिला शिक्षकों की संख्या 19.7 लाख है। यही नहीं, देश के 14 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुषों से अधिक है। शिक्षण के प्रति महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी निश्चय ही स्कूली शिक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। इस उपलब्धि का बहुत बड़ा श्रेय बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है।

एक समृद्ध राष्ट्र की नींव शिक्षित समाज ही रख सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि हर बच्चे की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित की जाए। महामारी के दौर में स्कूली शिक्षा से वंचित छात्रों को पुनः स्कूलों से जोड़ने की कवायद ईमानदारी से करनी होगी, तभी बच्चे स्कूली शिक्षा से लाभान्वित हो पाएंगे।

(लेखक बीएचयू में शोध अध्येता हैं)

हिंदुओं की वापसी के हों ठोस प्रयास

'कब होगी कश्मीरी पंडितों की वापसी' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में बलबीर पुंज ने कश्मीर से अत्यंत विषम परिस्थितियों में निर्वासित वहां के हिंदू परिवारों की वापसी के बहाने जम्मू-कश्मीर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों और साजिशों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। हालांकि इन हिंदू परिवारों को किस तरह वापस घाटी में बसाया जाए, इस बारे में विस्तार से बात नहीं की गई है। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं, जिन्हें मैं साझा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम इन परिवारों के कब्जाए गए घरों को मुक्त कराया जाए। उन्हें सरकारी नियंत्रण में रखा जाए और उसी अनुपात में उनके लिए एक विस्तृत भूखंड पर (जो सुरक्षा के लिहाज से भी उचित हो) अधिवास की व्यवस्था की जाए। पुनः वापसी करने वाले सभी परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार शस्त्र लाइसेंस की लचीली व्यवस्था की जाए। उन्हें स्थानीय नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाए। सुरक्षा बल और राज्य पुलिस में इन परिवारों से कम से कम एक युवा सदस्य को अवश्य शामिल किया जाए। अच्छा हो कि केंद्र सरकार इन हिंदू परिवारों की घर वापसी की योजना को एक समयबद्ध सशक्त अभियान का रूप दे। निर्वासित हिंदू परिवार को वापस कश्मीर में बसाने में अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवार कोई गंभीर पहल करेगा अथवा केंद्र सरकार का सहयोग करेगा, ऐसा सोचना भी बेमानी होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि 19 जनवरी, 1990 की रात से जब वहां के हिंदू परिवारों का भारी पैमाने पर पलायन होना शुरू हो गया, तबसे अब तक अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवार का इस त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम पर कैसा रुख रहा है, वह किसी से छिपा नही है। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के अब तक के फैसलों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सरकार में साहस और सामर्थ्य की कमी नही। अतः उसे इस दिशा में निःसंकोच कदम आगे बढ़ाने चाहिए। साथ ही लेखक से एक आग्रह यह भी है कि वह 'कश्मीरी हिंदुओं' को 'कश्मीरी पंडित' लिखना छोड़ दें, क्योंकि पलायन करने वाले सभी जाति के थे। कश्मीरी पंडित वामपंथी नैरेटिव है, जो हिंदू समाज में फूट डालने के लिए रचा गया था।

चंदन कर्ण, झारखंड

मेलबाक्स

छलावा है किसानों का साथ

देश की आजादी के बाद हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। कोई भी सरकार किसानों की हमदर्द नहीं बनी। कांग्रेस ने किसानों के बूते देश में शासन किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हमदर्द बन रही है। वह पहले अपने गिरेबां में झांककर देखें। राहुल को गांधी परिवार की विरासत मिली है। किसान और किसानों का दर्द क्या होता है। जो धूप, बारिश और ठंड में खेतों में सिंचाई कर अनाज पैदा करता है, वही उसकी पीड़ा बयां कर सकता है। किसानों ने बैंकों से कर्ज लेकर खेती की थी। बैंकों का कर्ज और सरकार के समर्थन मूल्य की कमी से किसानों की फसलें औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती थी। किसानों का कर्ज बढ़ता जाता था। आज सरकार बदल गई है। अब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से आय में बढ़ोतरी हुई है। किसान कर्ज मुक्त होता जा रहा है। किसान देश का अन्नदाता है। देश इनका आदर करता है, लेकिन आठ महीने से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। कांग्रेस जिन किसानों के हितों की रक्षा करने की कसम खा रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वही कांग्रेस अपने घोषणापत्र में ऐसे कानूनों का वादा करती है। बेहतर है कि उसे किसानों को उकसाना बंद कर देना चाहिए। करोड़ों रुपये के समर्थन मूल्य पर सरकार ने किसानों से अनाज खरीदा है। कभी कोई किसान की शिकायत नहीं आई है। लिहाजा, विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पास विरोध का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस की नजर में फिलहाल पेगासस का मुद्दा छाया हुआ है। पेगासस को लेकर कांग्रेस ने मानसून सत्र नहीं चलने दिया। कांग्रेस हमेशा देश के लिए शुभ-शुभ सोचे। कांगेस सबसे पुरानी पार्टी है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के साथ पूरा न्याय करना चाहिए।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

1931 में पहली बार अंग्रेजों ने हमारे देश में जातीय जनगणना कराई थी। इस आंकड़े को आधार बनाकर ही मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

आजकल

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

जातीय जनगणना की मांग और राजनीति

कुछ राजनीतिक दल और नेता आजकल देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आगामी जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी निश्चित रूप से होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश का अहित होगा। कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो लगता है जैसे जातीय जनगणना ही सर्वप्रमुख एजेंडा हो। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना नहीं होगी। ऐसे में जातीय जनगणना से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमें गौर करना चाहिए

भारत जातियों के मामले में विविधताओं वाला देश है। ऐसे में यहां जातीय जनगणना का काम आसान नहीं होगा। फाइल

कई राजनीतिक दलों की ओर से जातीय जनगणना कराने की मांग को फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद से कुछ नेता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में तो खास तौर पर इस मामले पर सक्रियता बढ़ गई है। बिहार में राजद ने इसे हाथों-हाथ लिया तथा जातीय जनगणना की मांग कर दी। नीतीश कुमार क्यों पीछे रहते। उन्होंने न केवल जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया, बल्कि प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया। इसकी आग बढ़ती हुई दूसरे राज्यों तक पहुंची और उत्तर प्रदेश में भाजपा को छोड़कर हर दल इसकी मांग करने लगा। इस समय यह देश की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

दरअसल जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने की मांग वर्षों से हो रही है, पर इसके पक्ष में अगर लोग खड़े होते हैं तो विपक्ष में भी उतना ही सशक्त तर्क दिया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि आगामी जनगणना में वह पिछड़ी जातियों की गणना कराएगी। यह जानना रोचक होगा कि जो पार्टियां, नेता और एक्टिविस्ट इस समय जाति की गणना कराने की मांग कर रहे हैं, वे तब कई किंतु-परंतु के साथ इसका विरोध करने लगे थे। वे मांग करने लगे कि नए सिरे से जातीय जनगणना कराने के बजाय यूपीए सरकार ने जातियों की जो गणना कराई थी, मोदी सरकार पहले उसे जारी करे। दरअसल इन पार्टियों और नेताओं का भय भाजपा के पिछड़ा वर्ग से संबंधित कार्यों को लेकर था। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कानून संसद से पारित करा दिया था। पूर्व की सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की सोची भी नहीं और मोदी ने कैसे कर दिया? यह प्रश्न इन सब नेताओं के दिमाग को मथ रहा था। उनको लग रहा था कि मोदी सरकार ने यदि पिछड़ी जातियों की जनगणना करा दी तो वे लोग इसके सियासी लाभ से वंचित हो जाएंगे।

यह भी तय है कि जब आप पिछड़ी जातियों की जनगणना की मांग करेंगे तो दूसरी जातियां भी खड़ी होंगी। नरेंद्र मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद एक बड़े वर्ग ने यह मांग की कि जब गणना करानी है तो केवल पिछड़ी जातियों की क्यों होनी चाहिए? दूसरी जातियों की भी हो जाए। पिछड़ी जातियों की जनगणना के पीछे मुख्य तर्क यही रहा है कि चूंकि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, इसलिए एक बार जातियों का आंकड़ा आ जाए तो उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और अन्य योजनाओं में उनकी सही भागीदारी पर निर्णय करना आसान हो जाएगा। आज हमारे पास जातियों की संख्या को लेकर कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। जो है वह 1931 का है जिसे अंग्रेजों ने अंजाम दिया था। वर्ष 1931 के इस आंकड़े को आधार बनाकर ही मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की और उसे स्वीकार कर लिया गया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब पिछड़ी जातियों की गणना की मांग तीव्र हुई तो उस समय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट को जारी किया गया था। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी कुल आबादी की 41 प्रतिशत बताई गई थी। मंडलवादी या पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेताओं को यह गवारा नहीं हुआ और उन्होंने दबाव बनाया कि नए सिरे से गणना कराई जाए। इनमें से ज्यादातर यूपीए के भाग थे या बाहर से समर्थन दे रहे थे, इसलिए उस पर दबाव कायम हुआ।

उस समय के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में तत्काल एक मंत्री समूह गठित हुआ। उस समूह ने सभी दलों से अलग-अलग राय लेने के बाद जाति आधारित जनगणना कराने की अनुशंसा कर दी। किंतु यह गणना जनगणना कानून के तहत नहीं होकर अलग से की गई। इसलिए इसका नाम भी जनगणना नहीं रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना (एसईसीसी) रखा गया। यह राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक के नेतृत्व में नहीं, बल्कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुई। इसमें समय लगा और यह 2013 में पूरा हुआ। चाहे समय के अभाव में या अन्य कारणों से, तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे जारी नहीं किया, पर मोदी सरकार में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में घोषणा की थी कि गणना में आई अलग-अलग जातियों की संख्या प्रकाशित कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि इसे प्रकाशित करना आसान नहीं था। दरअसल उसमें कई लाख जातियां, उपजातियां, वंश, गोत्र आदि सामने आए थे। यह सिर चकराने वाली स्थिति थी।

तब नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित हुई। उसके व्यापक कसरत के बावजूद गणना की रिपोर्ट को प्रकाशित करना संभव नहीं हुआ। मांग करना आसान है, लेकिन भारत जातियों के मामले में विविधताओं वाला एकमात्र देश है। सच यही है कि यहां संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप में ऐसी गणना और उसे प्रकाशित करने योग्य बना पाना संभव नहीं है। अंग्रेज कैसे जातीय जनगणना कराते थे, इसका अध्ययन करने वाले भी बताते हैं कि वह भी संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ नहीं था। वैसे भी भारतीय समाज व्यवस्था की जटिलताओं का सही अध्ययन अंग्रेजों के द्वारा संभव ही नहीं था। फिर अंग्रेज भारतीय समाज को बांटे रखने के लिए ऐसा करते थे और उस आंकड़े का आजादी के बाद कोई अर्थ नहीं रह गया था।

जातीय जनगणना की मांग करने वाले तथा उसका समर्थन करने वाले यह ध्यान रखें कि आजादी के बाद की पहली सरकार ने ही यह निर्णय किया कि अब देश में जाति जनगणना नहीं होगी। इसके लिए जो तर्क दिए गए थे उनमें सर्वप्रमुख यही था कि भारत अब ऐसे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन प्रणाली में आ गया है, जहां प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है और सभी वयस्क को मताधिकार मिल गया है। आजादी के बाद जिस भारत का सपना देखा गया था उसमें धीरे-धीरे जातिभेद खत्म होने की कल्पना थी और शासन को उसी दिशा में बढ़ना था। हालांकि यह तय हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना की जाएगी, क्योंकि संविधान में इनके उत्थान के लिए विशेष प्रविधान की बात थी। 1951 से 2011 की जनगणना तक उनकी गिनती होती रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों की जनगणना के विषय को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया।

आसान नहीं सामाजिक विसंगतियों का खात्मा

जातीय जनगणना का मामला पुनर्जीवित तभी हुआ जब मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण लागू हुआ। तभी से यह मांग उठ रही है कि अनुसूचित जाति-जनजातियों की तरह पिछड़ी जातियों की भी गणना की जाए। मंडल आयोग ने कहा था कि अगली जनगणना जब भी हो इनकी संख्या पता कर ली जाए। जब आयोग की सिफारिश लागू हुई, उसके बाद की जनगणना 1991 में होनी थी, किंतु उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लिहाजा 2001 की प्रतीक्षा की गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अंजाम नहीं दिया। वास्तव में जब भी इस पर विचार-विमर्श हुआ यही लगा कि भारत में जातीय-सामाजिक जटिलताओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं है। मुख्य बात तो यही है कि सभी पिछड़ी जातियों की पहचान कैसे होगी? एक राज्य में जो जाति अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल है, वही दूसरे राज्य में उस श्रेणी में नहीं है और केंद्रीय सूची में भी नहीं है। यही स्थिति अनुसूचित जाति-जनजाति के मामले में भी है। इसलिए इनकी गणना आसान नहीं है। यही स्थिति अगड़ी जातियों के संदर्भ में भी है।

वास्तव में इसे भारतीय राजनीति की विडंबना कहेंगे कि विचारधाराओं से निकले जो नेता जातियों की आलोचना करते हुए-जातिवाद खत्म करो-का नारा लगाते थे, उसके लिए अभियान चलाते थे वे मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद धीरे-धीरे जाति व्यवस्था के घोर समर्थक बन चुके हैं। जाति तोड़ो का सपना अब दफन हो चुका है। उनकी पूरी राजनीति और सामाजिक न्याय की कल्पना आरक्षण और जातियों के इर्द-गिर्द सिमट चुकी है। इनका तर्क होता है कि हम जितनी संख्या में हैं, उतना आरक्षण हमें मिले और यह तभी होगा जब पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या सामने आ जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि जातिगत आरक्षण को इन्होंने भारत का स्थाई अंग बनाए रखने का मन बना लिया है। ये यह भी भूल रहे हैं कि स्वयं मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों की आबादी को 52 प्रतिशत बताते हुए भी उनके लिए 27 प्रतिशत की ही सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति-जनजाति का विषय अलग है, लेकिन पिछड़ी जातियां मंडल आयोग की कल्पना में भी उस अवस्था में नहीं कि इनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाए।

कहने का तात्पर्य यह कि जातीय जनगणना की मांग भारतीय समाज के व्यापक हित या सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा रही है, बल्कि इसके पीछे केवल राजनीति है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें भारतीय समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए अनेक कदम उठाने हैं। काफी कदम उठाए गए हैं, आरक्षण उनमें से केवल एक है, लेकिन जब राजनीति दिशाहीन या दिशाभ्रम का शिकार हो जाती है तो फिर ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर आप नए सिरे से जातीय जनगणना करा कर फिर उसके आधार पर आरक्षण के लिए जोर डालेंगे तो समाज में तनाव बढ़ेगा, सामाजिक एकता भंग होगी और सामाजिक न्याय के अन्य कदमों के सकारात्मक परिणामों पर अत्यंत घातक असर होगा। इस बात को देश के सभी राजनेता, बुद्धिजीवी आदि समझें तथा ऐसी मांग नहीं करें जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो। उन्हें समझना चाहिए कि आखिर यूपीए सरकार ने 2006 में नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया? इसी तरह जो मोदी सरकार स्वयं पिछड़े वर्गों का समर्थन पाने के लिए इनकी जनगणना की घोषणा कर चुकी थी, वह पीछे क्यों हट गई? इस प्रश्न का उत्तर भी तलाशना चाहिए।

खरी-खरी

मौसम-मौसम, उनका मौसम

डा. प्रदीप उपाध्याय

बहुत सोचा-विचारा कि क्या वास्तव में मौसम बेईमान होता है या फिर आशिकाना होता है! मौसम आशिकाना बने रहने की जगह बिगड़ भी सकता है। यानी मौसम का ही मिजाज बिगड़ सकता है या फिर जो उन्हें याद फरमा रहे हैं, उनका ही मूड बिगड़ सकता है। लोकतंत्र के चार स्तंभों जैसे चार मौसम, पर पांचवां मौसम प्यार का जोड़ने में भी किसी को लाज नहीं आई। अब क्या प्यार का भी कोई एक अलग मौसम होता है! जैसे रिश्ते-नातों का एक निर्धारित दिवस। मौसम बनता-बिगड़ता है तो लोगों का मूड भी बनने-बिगड़ने लगता है। यह क्या बात हुई!

मौसम का अपना मिजाज है तो फिर ये दो पैरों वाला सामाजिक प्राणी क्यों नहीं अपने मिजाज पर कायम रहता है। मौसम भी किसी के लिए खुशनुमा हो जाता है तो किसी के लिए खुशगवार, लेकिन सोचने में यह भी आता है कि सब बातें मौसम पर ही आकर क्यों ठहर जाती है! मौसम क्यों बेईमान होता है! क्यों मौसम कुछ क्षणों के लिए आशिकाना होता है! क्यों मौसम कुछ समय के लिए प्यार का मौसम होकर नदी में आई बाढ़ के बाद की तबाही की तरह खामोश सा हो जाता है! कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मौसम के कंधे का सहारा लेकर बंदूकें चला रहे हों। मौसम का अपना क्रम है, अपना मिजाज है तब फिर क्यों उसके नाम का सहारा लेकर इंसान बहकता है! क्या वास्तव में मौसम का मानव मन पर इतना प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है! इसके हिसाब से मानव मन गतिमान होता है, चलायमान होता है या फिर मानव मन के हिसाब से मौसम परिवर्तित होता रहता है। अभी तो इंसान ने ही मौसम को बहकने के बहुतेरे अवसर दिए हैं। दरअसल इंसान ने अपने अधिक बुद्धिजीवी होने का फायदा उठाते हुए मौसम को हर तरह से लाभ उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा।

कभी तो इंसानी फितरत कहती है कि मौसम बेईमान है और कभी कहती है कि दिल ही बेईमान हो गया था। ऐसा तो नहीं कि मौसम तो चुस्त-दुरुस्त है और इंसान की नीयत में खोट हो। यदि इंसान मौसम को बेईमान बताता है तो मौसम का गीत यही होगा कि आज इंसान बेईमान है बड़ा बेईमान है।

ट्वीट-ट्वीट

भविष्य के कुछ रुझानों पर गौर कर लीजिए। कोविड से ज्यादा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा होगी। आवाजाही के लिए साइकिल सबसे अहम वाहन बनकर उभरेगी। इलेक्ट्रानिक्स के उपभोग में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी होगी। वहीं कैजुअल कपड़े ज्यादा खरीदे जाएंगे।
हर्ष गोयनका@hvgoenka

टोक्यो ओलिंपिक समापन के साथ ही अब पूरा ध्यान विंटर ओलिंपिक पर केंद्रित हो गया है, जिसमें छह महीने से भी कम का समय शेष है। चूंकि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार पर्दा डाला है, उसे देखते हुए क्या बीजिंग को विंटर ओलिंपिक की मेजबानी करने दी जानी चाहिए?
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

पश्चिमी देश पहले भी ओलिंपिक खेलों का बहिष्कार कर चुके हैं। ऐसे में विंटर ओलिंपिक का न केवल इस आधार पर बहिष्कार किया जाए कि वायरस की उत्पत्ति की जांच में अवरोध पैदा किए गए, बल्कि इसकी मांग करने वालों को भी निशाना बनाया गया। इसमें शिरकत करने वाले चीन की आक्रामक नीतियों पर ही मुहर लगाएंगे। उद्दंड शी को इसकी तपिश महसूस होनी ही चाहिए। कंवल सिब्बल@KanwalSibal

लियोन मेसी बार्सिलोना से अपनी विदाई पर रो रहे हैं। समर्थक भी विलाप कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा। आखिर मामला पैसों पर ही तो फंसा हुआ था। सुधीर मिश्रा@IAmSudhirMishra

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार मिलना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या विपक्षी दलों की एकता आकार लेती हुई दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

माटी गांव-गिरांव की मत समझो बेकार,
यही दे रही आजकल ओलंपिक स्टार।
ओलंपिक स्टार राष्ट्रधुन हैं बजवाते,
सोना-चांदी जीत देश का मान बढ़ाते।
देख-देख उपलबधि हो रही चौड़ी छाती,
क्योंकी उगले स्वर्ण देश की अपने माटी।
- ओमप्रकाश तिवारी

अनुराग अग्रवाल
स्टेट ब्यूरो चीफ, हरियाणा

हरियाणा डायरी

आंदोलनकारियों पर भारी तिरंगा यात्रा

हरियाणा में किसान संगठन पिछले आठ माह से तीन कृषि कानूनों को रद कराने की अनावश्यक जिद पर अड़े हैं। इन आठ माह में खूब उपद्रव हुए। अराजक एवं हिसंक घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन भाजपा ने तिरंगा यात्राएं निकालकर न केवल आंदोलनकारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि पूरे प्रदेश में देशप्रेम की लौ जगा दी है। दरअसल केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध करते-करते आंदोलनकारी इतने अराजक हो चुके थे कि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा (जननायक जनता पार्टी) गठबंधन के नेताओं का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले का घेराव, उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने-प्रदर्शन और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गाड़ी पर पथराव इन आंदोलनकारियों के हिंसक होने के प्रमाण हैं। किसान संगठनों के आंदोलन स्थलों पर आए दिन होने वाले अपराध आंदोलनकारियों के अराजक होने की कहानी कह रहे हैं। इन सबके बीच हरियाणा के सत्तारूढ़ दल भाजपा ने पूरे प्रदेश में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का ऐसा खाका खींचा कि आंदोलनकारी तो निरुत्तर हुए ही, साथ ही जनता भी देशप्रेम के रंग में रंगी नजर आने लगी।

हरियाणा में इस समय सभी विधानसभा क्षेत्रों में शहीद सम्मान तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ की जोड़ी ने आजादी का जश्न मनाने तथा शहीदों को सम्मान देने के लिए ये तिरंगा यात्राएं शुरू की है, जो 15 अगस्त तक चलेंगी। भाजपा सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी इन तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह से किसान संगठनों ने अपने आंदोलन में ट्रैक्टरों को शामिल किया,

भाजपा ने तिरंगा यात्राएं निकालकर न केवल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बल्कि पूरे प्रदेश में देशप्रेम की लौ भी जगा दी है। फाइल

उसी का जवाब देते हुए भाजपा की तिरंगा यात्राओं में अनगिनत ट्रैक्टर शामिल किए गए हैं। किसान संगठनों के आंदोलन में खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे झंडे-बैनर थे तो भाजपा की तिरंगा यात्राओं में भारत माता की जय लिखे नारे हैं।

हरियाणा सरकार यदि चाहती तो इन किसान संगठनों के अराजक मंसूबों पर समय रहते शिकंजा कस सकती थी, लेकिन प्रदेश सरकार उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई कर उन्हें पनपने का मौका नहीं देना चाहती थी। सरकार की इस नरमी को किसान संगठनों ने कमजोरी मान लिया। बावजूद इसके प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को घेरकर उनके प्रति गलत रवैया अपनाने का किसान संगठनों का सिलसिला नहीं थमा। अब भाजपा ने तिरंगा यात्रा के जरिये न केवल प्रदेश भर के लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पूरी सक्रियता के साथ फील्ड में उतार दिया है।

हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। भाजपा अभी तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाल चुकी है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया, धर्मवीर सिंह, नायब सिंह सैनी, रमेश कौशिक, सुनीता दुग्गल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, मंत्री अनिल विज, पंडित मूलचंद शर्मा, संदीप सिंह, कमलेश ढांडा, कंवरपाल गुर्जर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा और कविता जैन के नेतृत्व में निकली इन तिरंगा यात्राओं से ऐसा माहौल बना कि आंदोलनकारी बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल में भी तिरंगा यात्रा निकल चुकी है। भाजपा सांसदों, मंत्रियों और विधायकों द्वारा निकाली जा रही इन यात्राओं का सकारात्मक असर उसके सहयोगी दल जजपा पर भी पड़ा है।

भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सहभागी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लंबे समय से आंदोलनकारियों के निशाने पर चल रहे थे, लेकिन जब से राज्य में तिरंगा यात्राएं निकली हैं और पूरा प्रदेश देशप्रेम के रंग में ओतप्रोत हो गया है, तब से भाजपा की सहयोगी जजपा के विधायकों को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में गर्व के साथ सिर उठाकर चलने का मौका मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ का कहना है कि किसान संगठनों का आंदोलन अपनी जगह है और तिरंगा यात्राओं का अपना अलग सम्मान है। इसके बावजूद यदि किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर केंद्र से वार्ता करने को तैयार होते हैं तो हम इसके लिए मध्यस्थता करने के लिए आगे आएंगे।

पंजाब डायरी

'मिशन किसानी' से लेकर 'मिशन पंजाब' का सच

अमित शर्मा
स्थानीय संपादक, पंजाब

तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों द्वारा पिछले आठ महीने से किए जा रहे आंदोलन को लेकर गत दो सप्ताह में तीन बड़े घटनाक्रम हुए। पहला था अदाणी ग्रुप द्वारा 2017 में लुधियाना के किला रायपुर गांव में 80 एकड़ में स्थापित मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क को अचानक बंद किए जाने की आधिकारिक घोषणा और फिर इस फैसले पर किसान संगठनों समेत राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस एवं तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा चुप्पी साध लेना। इसी क्रम में दूसरी घटना है संसद भवन परिसर की, जहां शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू के बीच हुई तीखी नोकझोंक चर्चा का एक मुख्य विषय बना। तीसरी घटना रही हरियाणा से आंदोलन में अब तक अग्रणी भूमिका निभा रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होने का एलान। इन तीनों प्रसंगों में सबसे अहम यदि कुछ रहा तो वह था किसान हितों की आड़ में प्रतिदिन प्रबल होती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का इस तरह सरेराह पटाक्षेप होना। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि अब किसान हित से जुड़े मसलों पर राजनीतिक दांवपेच हर तरह से भारी पड़ रहे हैं। अब चाहे किसान मोर्चे के नेता हों या फिर सत्ताधारी और विपक्षी दलों से जुड़े लोग, सबका एजेंडा मिशन किसानी से बदलकर मिशन पंजाब या मिशन यूपी में पूर्णतः तब्दील हो गया है।

पंजाब जैसे लैंड-लाक स्टेट में उद्योगों को आयात और निर्यात के लिए रेल और सड़क मार्ग से कार्गो उपलब्ध करवाने वाले लाजिस्टिक पार्क का बंद होना अच्छा सूचक नहीं है। दो दशकों से राज्य में लगातार निवेश के लिए लाबिंग के बाद शुरू हुई इतनी बड़ी परियोजना बंद होने पर जहां किसान नेताओं ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं मौजूदा कैप्टन

लुधियाना के किला रायपुर गांव स्थित अदाणी लाजिस्टिक्स पार्क का बंद होना पंजाब में उद्योग जगत के लिए शुभ संकेत नहीं है। फाइल

सरकार या अकाली दल के नेताओं ने भी आपराधिक चुप्पी साध रखी है। विडंबना देखिए कि जिस दिन लाजिस्टिक्स पार्क बंद होने की घोषणा को अधिकतर पंजाबवासी किसान नेताओं के अड़ियल रवैये से जोड़ कर देख रहे थे, उसी दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने निवास पर बुलाई पंजाब नेतृत्व की एक बैठक में उन्हें इस आंदोलन को पंजाब और उत्तर प्रदेश में हरसंभव समर्थन देकर और अधिक मजबूत करने का निर्देश दे रहे थे।

यह सही है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा राजनीतिक तबका इस मसले पर कुछ भी बोलकर आंदोलनरत किसानों की संभावित नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि उनकी यह चुप्पी प्रदेश के हित में कतई नहीं है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए तो यह किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे नेताओं पर पार्टी से अधिक सूबे के हितों की नुमाइंदगी करने का जिम्मा है। उनका यह फर्ज है कि वे केवल एक वर्ग को न देखकर पूरे प्रदेश की चिंता करें। हर स्तर पर इस मौन का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि सूबे में रिलायंस द्वारा संचालित अनेकों उपक्रम (जो पिछले आठ महीने से बंद पड़े हैं) समेत कई बड़े कारपोरेट घराने भी अब अपने निवेश को बिल्कुल सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। ऐसी भावनाओं से प्रदेश को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके प्रभाव दूरगामी होंगे।

जहां तक पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल और कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू के बीच हुए 'वाक् युद्ध' की बात है तो उस नोकझोंक की शैली ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया कि इनके लिए किसानी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके बीच लगी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की दौड़। लगभग वही दौड़ अब संयुक्त किसान मोर्चे के शीर्ष नेताओं में भी सरेआम देखने को मिल रही है। तीन दिन पहले चढ़ूनी द्वारा अपनी फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश के माध्यम से यह सार्वजनिक हुई है। पूरे प्रकरण में किसानी से ज्यादा फोकस में रहा चढ़ूनी के मिशन पंजाब और टिकैत के मिशन यूपी को अंजाम तक ले जाने का मसला। इसे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता कि जिस रात दिल्ली बार्डर पर चढ़ूनी पंजाब के पांच अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक कर मोर्चे से बाहर निकलने का फैसला ले रहे थे, उसी समय भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के बलबीर सिंह राजेवाल के गृहक्षेत्र खन्ना में सड़कों और गलियों की दीवारों पर असंख्य पोस्टर उकेरे जा रहे थे। पंजाबी में लिखे इन पोस्टरों पर राजेवाल की फोटो लगाकर लिखा गया था कि क्या आप चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री बनें बलबीर सिंह राजेवाल? मजेदार बात तो यह है कि इन पोस्टरों को लेकर चढ़ूनी द्वारा प्रचारित मिशन पंजाब का खुलकर विरोध कर रहे संयुक्त मोर्चे के किसी भी किसान नेता का कोई बयान नहीं आया।

अब जब किसान आंदोलन पर राजनीतिक जकड़न साफ दिख रही है, आंदोलन से जुड़े तमाम किसान नेता या राजनीतिक चेहरे खुलकर सियासत करने लगे हैं तो जाहिर है आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और दशा भी बदलेगी। बस जरूरत है आंदोलन को सत्य की कसौटी पर परखने की।

65 फीसद क्षय रोग (टीबी) के मामले 15-45 वर्ष के लोगों में है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। टीबी के 58 फीसद मामले ग्रामीण इलाकों में हैं।

उत्तराखंड

सुधार गृहों की दुर्दशा चिंताजनक

उत्तराखंड में सुधार गृहों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इनमें से कुछ सुधार गृह सरकारी हैं अथवा सरकारी मदद से संचालित किए जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन्हें गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं। राजधानी देहरादून में नारी निकेतन का मामला तो सुर्खियां में रहा ही, अब ताजा मामला नशा मुक्ति केंद्र का है। यहां भर्ती युवती ने केंद्र के संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। प्रताड़ित युवतियां कुछ दिन पहले केंद्र से भाग गईं, पकड़ में आने पर उन्होंने पुलिस से अपना दर्द बयां किया। युवतियों ने बताया कि केंद्र में उन्हें नारकीय यातना दी जाती थीं। प्रदेश में नशा मुक्ति के नाम पर सैकड़ों केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इन केंद्रों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वे हालात की गंभीरता को दर्शाते हुए सिस्टम की सजगता पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर क्या ये नशा मुक्ति केंद्र मानकों का पालन कर रहे हैं। ताजा मामले में पता चला कि नशा मुक्ति केंद्र में न चिकित्सक की व्यवस्था थी और न ही काउंसलर की।

सुधार गृहों की दुर्दशा नि:संदेह चिंता का विषय है। सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कदम उठाने होंगे। सिस्टम को सजग बनाना होगा ताकि इन गृहों को खोलने का मकसद पूरा हो सके

सवाल यह भी है कि इन केंद्रों की निगरानी के लिए क्या इंतजाम हैं। किस एजेंसी के पास इसकी जिम्मेदारी है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब कभी ऐसा मामला सामने आता है तो प्रशासन और पुलिस सजग नजर आते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ सबकुछ लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज में चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र वक्त की जरूरत बन चुके हैं। यह अभिभावकों की बेबसी है कि उन्हें अपने बच्चों को इन केंद्रों में भर्ती कराना पड़ता है। इसके लिए उनसे फीस के नाम पर भारी-भरकम धनराशि भी वसूली जा रही है। बावजूद इसके हालात ये हैं कि वहां उनके नौनिहालों की उचित देखभाल तक नहीं हो पा रही, यहां तक कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि नशीले पदार्थों की बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हर रोज मादक पदार्थों की तस्करी में कोई न कोई गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये सब छुटभैये हैं। असल मुजरिम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। अब वक्त आ गया है कि पुलिस तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए। नशे की जकड़न में फंस रही युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सरकार के साथ ही सामाजिक संगठनों को भी गंभीरता के साथ पहल करनी होगी।

बिहार

उद्योगों की बात

किसी भी समस्या का समाधान बातचीत, चर्चा और संवाद से हो सकता है। संयोग से बिहार में काफी वर्षों बाद औद्योगिक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में आक्सीजन की कमी सार्वजनिक होने के बाद इसका उत्पादन करने वाली इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के साथ नए प्लांट लग रहे हैं तो यह सर्वे भी चल रहा कि किस जिले के मिजाज से कौन सा उद्योग लगाया जाए। बड़ी बात है कि सरकार ने यह महसूस किया है कि कृषि के बाद उद्योग के माध्यम से ही रोजगार सृजन किया जा सकता है। दरअसल किसी भी राज्य की प्रगति उद्योगों के बिना संभव नहीं है। बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश उद्योगों के बल पर ही विकास का दम भर रहे हैं। विकास के मोर्चे पर प्रयत्नशील बिहार सरकार के एजेंडे में भी उद्योगों की चर्चा ऊपरी पायदान पर आ गई है। औद्योगिक संभावनाओं की नजर से देखें तो राज्य ने कृषि उत्पादन में काफी तरक्की की है। मक्का, धान और सब्जियों के ममाले में तो बिहार दूसरे राज्यों को सबक दे रहा है। ऐसे में इनपर आधारित उद्योगों की स्थापना की भरपूर गुंजाइश है। फलों में लीची, आम, अमरूद,

किसी भी राज्य की प्रगति उद्योगों के बिना संभव नहीं है। फाइल

कोरोना संक्रमण से उबर रहे बिहार में उद्योगों की स्थापना का प्रयास युवाओं को रोजगाररूपी ऊर्जा देगा। सुखद है कि नीतीश कुमार की सरकार इस पर गंभीर है

केला आदि के उत्पादन में किसान व्यावसायिक तरीके से लगे हैं। हस्तकला, शिल्पकला, मधुबनी पेंटिंग में अग्रणी होने के साथ बिहार खादी एवं सिल्क कपड़ों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, परंतु किसान, कलाकार, बुनकर, कारोबारी और उद्यमी देश-विदेश स्तर पर ब्रांड बनने में पीछे हैं।

बहरहाल इस दिशा में राज्य सरकार काफी गंभीर है। प्रदेश के उद्योग मंत्री उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां स्थानीय स्तर पर कच्चा माल आधारित उद्योग लगाकर रोजगार सृजित किया जा सकता है। बिहार का गया ऐसा जिला है जो पर्यटन की दृष्टि से देश-विदेश में विख्यात है। इसे उद्योगों का हब बनाने की कोशिश दक्षिण बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में मदद कर सकती है। रविवार को उद्योग मंत्री ने गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने पहले पानी, सड़क, बिजली पर काम किया और अब उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि नवयुवकों को रोजगार मुहैया हो सके। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि उनके प्रयास सफल हों।

झारखंड

चिंता और चुनौती

झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है। इस समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बिहार का विभाजन कर इस अलग राज्य का निर्माण किया गया था। जब अलग राज्य की मांग की जा रही थी तब पहले वृहद झारखंड की कल्पना की गई थी, जिसमें झारखंड के पड़ोसी राज्यों के जनजातीय बहुल जिले भी शुमार थे। तकनीकी जटिलता के कारण यह संभव नहीं हो पाया। आरंभ से ही जनजातीय समुदाय कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करता रहा। रोजगार के लिए पलायन, कुपोषण, अशिक्षा समेत अन्य चुनौतियां आज भी इस समुदाय के समक्ष हैं। हालांकि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से धीरे-धीरे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन अन्य समुदायों की अपेक्षा अभी भी जनजातीय समुदाय पीछे है। आदिवासियों के उत्थान के लिए अभी बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। जनजातीय समुदाय की कम होती आबादी चिंताजनक है। 1951 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों

झारखंड में आदिवासियों की आबादी में गिरावट पर सरकार समेत हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है

आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। फाइल

पर गौर करें तो जनजातीय समुदाय की आबादी में 10 प्रतिशत की कमी इंगित की गई है। जानकार इसकी कई वजहें गिनाते हैं। इनमें रोजगार के लिए पलायन भी एक बड़ा मसला है। हालांकि राज्य सरकार की रोजगारपरक योजनाओं से इसमें कमी आई है। कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के पारंपरिक उपायों के तहत प्रयोग किए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए जाने वालों का निबंधन अनिवार्य किया गया है। इससे आंकड़े सहेजने में सहूलियत होगी। झारखंड सरकार ने अब उन संस्थाओं के साथ श्रम समझौते की भी पहल शुरू की है, जो यहां से श्रमिकों को लेकर बाहर जाते हैं। ऐसे प्रयास उनका जीवन स्तर बेहतर करने में मददगार होंगे। जनजातीय समुदाय को केंद्र में रखकर शैक्षिक योजनाएं भी आरंभ की गई हैं। इसका भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। खेल समेत कई क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय की प्रतिभाओं ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। जनजातीय समुदाय की आबादी का कम होना चिंताजनक है। खासकर तब और, जब आदिम जनजातीय समूह की ज्यादातर जनजातियां विलुप्तप्राय जातियों की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। इनके संरक्षण की चिंता सबको होनी चाहिए।

बंगाल

माकपा को तिरंगे को लेकर आई सद्बुद्धि

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद तत्कालीन कम्युनिस्टों ने नारा दिया था 'यह आजादी झूठी है।' हालांकि बाद में अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआइ) ने गलती को स्वीकार ली थी। परंतु इन वाम नेताओं का तर्क था कि जब आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर यह कैसी आजादी है! पर जब वक्त का पहिया घूमा तो भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति वाम नेतृत्व की आस्था भी बढ़ी थी। बाद में 1964 में सीपीआइ विभाजित हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) बनी। इसके बाद माकपाइयों ने जनप्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में तो हिस्सा लिया, लेकिन कभी भी अपने पार्टी दफ्तरों में स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। स्वतंत्रता के 75वें साल में आकर माकपाइयों को तिरंगे को लेकर सद्बुद्धि आई है।

स्वतंत्रता के 75वें साल में आकर माकपाइयों को तिरंगे को लेकर सद्बुद्धि आई है। माकपा की केंद्रीय कमेटी ने इस बार 15 अगस्त को पार्टी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है

दरअसल भाजपा के राष्ट्रवाद से टक्कर लेने के लिए माकपा की केंद्रीय कमेटी ने इस बार 15 अगस्त को देशभर के पार्टी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। अब तक माकपा मानव श्रृंखला सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित कर गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस मानती थी, पर पार्टी कार्यालयों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। वहां कम्युनिस्टों का लाल झंडा लहराता था। यही वजह थी कि पार्टी के अंदर बार-बार सवाल उठाया जाता था कि क्या अभी तक माकपा के लिए यह आजादी झूठी है? अजादी के 75वें साल सीताराम येचुरी की पार्टी ने सोच और मानसिकता बदली है। कन्नूर में होने वाली आगामी पार्टी कांग्रेस से पहले माकपा केंद्रीय समिति की बैठक में इस बार अभूतपूर्व प्रस्ताव पारित कर माकपा के सभी कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस मनाने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया। यह माकपा ही नहीं वामपंथियों के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। आखिर माकपा में यह परिवर्तन इतने वर्षों के बाद क्यों आया है? इस पर कामरेडों के तर्क तो अलग-अलग हैं, लेकिन उनके सार को समझें तो उनका मानना है कि जिस तरह से भाजपा ने राष्ट्रवाद के जरिये देशवासियों को प्रभावित किया है, उससे मुकाबले के लिए रणनीति में परिवर्तन जरूरी है और इसी नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है। सवाल है कि माकपा के विचार व नीति बदलने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि 34 वर्षों तक बंगाल पर राज करने वाली माकपा आज यहां अस्तित्व संकट से जूझ रही है। राष्ट्रवाद को लेकर माकपा नेता और क्या-क्या करते हैं और इसका उन्हें कितना फायदा मिला, यह वक्त बताएगा।

श्रद्धा का महासावन

शिव का मतलब कल्याण

भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास अतिप्रिय है। सावन में शिवजी की आराधना विशेष फल देने में समर्थ है। सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोरथ की सिद्धि होती है। महादेव की कृपा प्राप्त होती है। बाधाएं खत्म होती हैं और शत्रुओं का दमन होता है। शिव, भगवान का स्वरूपक प्रधान नाम है। इसी तरह शंकर, स्वभावक प्रधान नाम है और प्रलयंकर, प्रभावक प्रधान नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याणस्वरूपम।

जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती
पीठाधीश, पुरी गोवर्द्धन पीठ

शंकर का अर्थ कृपा और कल्याण की वर्षा करने वाले व प्रलयंकर का अर्थ है -दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों तथा बुराइयों को नष्ट करने वाले। धर्म और अध्यात्म का गहरा चिंतन ईश्वर के एकाकार स्वरूप को मान्यता देता है। भगवान के सभी रूप महादेव में समाहित हैं। एक ही भगवान ब्रह्मा होकर सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु होकर संरक्षण या पालन करते हैं और शिव होकर संहार करते हैं। जलाभिषेक के पीछे यह भावना है कि भगवान शंकर की कृपा से सब प्रमुदित रहें। जहां शिव हैं वहां कल्याण है, आनंद है, धर्म है, साधना है, त्याग है, नीति है, कृपा है और शक्ति है। सावन शब्द श्रवण से बना है। पूजा के साथ भगवान की महिमा का श्रवण होना चाहिए। सावन के सोमवार को शिव का अभिषेक करने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। कोरोना संकट काल में घर में आप ज्यादा विधि-विधान और श्रद्धा से पार्थिव शिव लिंग की पूजा कर सकते हैं। शिव सप्तनाम का पाठ कर सकते हैं। जलाभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने सबके कल्याण के लिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम... लिखा है, इस स्तुति का पाठ कर सकते हैं।

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

मप्र में मिलावटी शराब पर फांसी का कानून बनाने का विधेयक पारित

नईदुनिया, भोपाल

- बार-बार अपराध करने वाले पर कम से कम 20 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा

मिलावटी शराब से बढ़ रही मौत की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर फांसी की सजा का प्रविधान जोड़ा है। मंगलवार को विधानसभा में आबकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक हंगामे के बीच पारित हो गया। राज्यपाल की सहमति के बाद अब यह कानून भी बन जाएगा। इसमें मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु के मामले में आरोपित के विरुद्ध बार-बार दोषसिद्ध होता है तो उसे मृत्युदंड (फांसी) की सजा और कम से कम 20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मध्य प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया। सदन में हंगामे के कारण इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। शोरगुल के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यवाही पूरी कराई और विधेयक पारित हो गया। अब इसे राज्यपाल को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। उनकी अनुमति मिलते ही राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इसके प्रविधानों को लागू कर दिया जाएगा।

अब यह प्रविधान : संशोधन के अनुसार

वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने विस में मध्य प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया।

मादक द्रव्य में मिलावट करने पर जुर्माना न्यूनतम तीन सौ रुपये के स्थान पर 30 हजार और अधिकतम दो हजार की जगह दो लाख रुपये होगा। जांच में बाधा पहुंचाने या हमला करने पर दो की जगह अब तीन साल का कारावास होगा। इससे यह अपराध गैर जमानती हो जाएगा। मिलावटी शराब मिलने संबंधी पहली बार के अपराध में कारावास दो माह की जगह न्यूनतम छह माह और जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।

मिलावटी शराब से शारीरिक क्षति (जैसे आंखों की रोशनी जाना) होने पर न्यूनतम चार माह की जगह दो वर्ष और अधिकतम आठ वर्ष के कारावास के साथ न्यूनतम दो लाख रुपये का जुर्माना होगा। मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु होने पर न्यूनतम दो वर्ष की जगह 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास व न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। बार-बार मिलावटी शराब मिलने पर न्यूनतम छह से लेकर अधिकतम दस वर्ष का कारावास और कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। बार-बार शारीरिक क्षति पर न्यूनतम दस वर्ष, अधिकतम 14 साल का कारावास और न्यूनतम दस लाख रुपये जुर्माना लगेगा। बार-बार मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु के मामले आने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड के प्रविधान के सहित न्यूनतम 20 लाख रुपये तक का जुर्माने का दंड मिलेगा।

उप्र ने सबसे पहले बनाया था फांसी का कानून : देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मिलावटी शराब से मौत होने की स्थिति में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रविधान किया था। इसी तरह पंजाब में भी इसी साल मई में नकली या अवैध शराब पीने से किसी व्यक्ति की मौत होने या हालत गंभीर होने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा का प्रविधान किया गया है।

रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे कोविन्द

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

- पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1983 में की थी रामनगरी की यात्रा
- राममजन्मभूमि परिसर न जाकर कनक भवन में किया था दर्शन पूजन

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अयोध्या यात्रा ऐतिहासिक होगी। रामलला का दर्शन करने वाले वह पहले राष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले देश के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह वर्ष 1983 में अयोध्या आए थे, लेकिन उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए थे। उन्होंने कनक भवन जाकर दर्शन-पूजन किया था। उनकी अयोध्या यात्रा में कांग्रेस के पूर्व सांसद डा. निर्मल खत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नगर पालिका अयोध्या के पूर्व अध्यक्ष वयोवृद्ध महेंद्र सिंह को आज भी वह पल याद है। वह बताते हैं कि कनक भवन में काफी भीड़ थी। वह भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रपति के आगमन पर मंदिर के अंदर, जो गिने चुने लोग मौजूद थे उसमें महेंद्र सिंह भी शामिल थे। पूर्व पालिकाध्यक्ष कहते हैं कि एक लंबा समय बीत चुका है। उस वक्त की स्मृतियां कमजोर पड़ चुकी हैं, लेकिन कनक भवन में उनके आगमन के वह चश्मदीद हैं।

महेंद्र सिंह की मानें तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रामजन्मभूमि परिसर नहीं गए थे। कांग्रेस नेता हरजीत सलूजा भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की यात्रा के गवाह हैं। उन्हें गुरुनानकपुरा ले जाने में हरजीत का प्रयास शामिल था। 38 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द 29 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। जागरण आकाईव

अयोध्या को राष्ट्रपति के स्वागत का मौका मिल रहा है। देश के 14वें राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द रामलला के दर्शन करेंगे। वह कनक भवन, हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के अलावा सरयू आरती भी कर सकते हैं।

29 अगस्त को आ रहे राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के आगमन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा एवं एसएसपी शैलेश पांडेय ने अयोध्या जंक्शन का जायजा लिया। वहीं राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। अधिकारियों ने स्टेशन परिसर का भ्रमण कर राष्ट्रपति के निकास एवं प्रवेश की व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने रामजन्मभूमि परिसर का भी जायजा लिया।

नोएडा में स्थापित होगा भारतीय विरासत संस्थान

नई दिल्ली, एएनआइ : संस्कृति मंत्रालय ने नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान (आइआइएच) की स्थापना का फैसला किया है। यह देश का विशिष्ट संस्थान होगा। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'इससे भारतीय विरासत व उसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा व शोध को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय विरासत संस्थान में कला इतिहास, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, पुरालेख, मुद्राशास्त्र व पांडुलिपि विज्ञान आदि में स्नातकोत्तर व पीएचडी कोर्स का संचालन किया जाएगा। वहां काम करने वालों और छात्रों को संरक्षण प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी।'

भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना पुरातत्व संस्थान (पं. दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान), राष्ट्रीय अभिलेखागार (नई दिल्ली) के अंतर्गत अभिलेखीय अध्ययन स्कूल, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एनआरएलसी) लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान-कला इतिहास, संरक्षण व संग्रहालय विज्ञान (एनएमआइसीएचएम) व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आइजीएनसीए) की प्रशासनिक इकाई को एकीकृत करके किया जा रहा है। ये इकाइयां संस्थान के विभिन्न स्कूल के रूप में काम करेंगी। संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोस में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

टिहरी झील में जल विमान उतरने का रास्ता हुआ साफ

राज्य ब्यूरो, देहरादून

योजना

- एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने देश के 17 वाटर एयरोड्रोम में टिहरी झील को भी किया शामिल

उत्तराखंड स्थित टिहरी झील में जल विमान उतारने का सपना अब जल्द साकार होता नजर आ रहा है। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने देश के 17 वाटर एयरोड्रोम में टिहरी झील को भी शामिल किया है। इसके साथ ही इसे क्षेत्रीय संपर्क योजना में भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही यहां वाटर एयरोड्रोम बनाने के साथ ही हवाई सेवा शुरू करने के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए जाएंगे।

उत्तराखंड की झीलों और नदियों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। टिहरी झील को पर्यटन के एक बड़े गंतव्य के रूप में प्रचारित किया गया है। प्रदेश सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लंबे समय से यहां जल विमान उतारने की योजना बना रही है। वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथारिटी के बीच यहां वाटर एयरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। इस कड़ी में अब एयरपोर्ट अथारिटी ने इसे वाटर एयरोड्रोम के रूप में चिह्नित कर लिया है। इससे यहां जल विमान उतरने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि, इसमें अभी कुछ समय लगेगा।

वाटर एयरोड्रोम के निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय व एएआइ सहयोग करेंगे। इसके सुरक्षा मानकों के लिए इनलैंड वाटर वेसल पालिसी भी बनाई जानी है, जिस पर अब जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल, केंद्र में पहले से ही इनलैंड वाटर वेसल पालिसी लागू है और राज्य सरकारों को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, इसके लिए अपनी नीति बनाने की व्यवस्था भी इसमें है। इसका मुख्य मकसद यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है।

क्या होता है जल विमान

जल विमान एक विशेष प्रकार का हवाई जहाज है, जिसे उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पानी से टेक आफ और लैंडिंग कर सकता है। इसका उपयोग पर्यटन गतिविधियों के अलावा रेसक्यू आपरेशन के दौरान सबसे अधिक किया जाता है।

निर्भया कोष का अन्य योजनाओं में उपयोग पर जताया आश्चर्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय से संबंधी संसद की स्थायी समिति ने महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों में दोषसिद्धि दर काफी कम होने पर चिंता जताई। समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि निर्भया कोष का लगातार अन्य योजनाओं में उपयोग किया जाता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 'समिति महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों में असामान्य रूप से कम सजा दर पर गौर करने के लिए मजबूर है, जो अपनाए गए उपायों और उनके कार्यान्वयन के बीच गंभीर बेमेल को जाहिर करता है।' रिपोर्ट के अनुसार, 'समिति ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम-2018 के अनुरूप कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौन अपराधों के लिए आनलाइन जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आइटीएसएसओ) नामक एक टूल प्रदान किया गया है, जिसका काम यौन अपराधों की जांच की निगरानी करना है। समिति सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय को सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आइटीएसएसओ के सख्त कार्यान्वयन के लिए मामला उठाना चाहिए।'

बिहारी श्रमिक खूब उठा रहे वन नेशन-वन राशन कार्ड का लाभ

राज्य ब्यूरो, पटना

- दिल्ली में 2773, हरियाणा में 1838, पंजाब में 128, महाराष्ट्र में 3073, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव में 1,577 और गुजरात में 1428 प्रवासी श्रमिकों ने राशन का किया उठाव

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना उन प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजी-रोटी कमाने गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी लोग बिहार के कोटे से अपने हिस्से के अनाज का उठाव कर रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक हर महीने 15,857 प्रवासी परिवार दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पिछले साल दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लेने वाले प्रवासी बिहारियों की संख्या 1765 थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस वर्ष पूरे देश में सर्वाधिक बिहार के प्रवासी लोगों ने इसका लाभ लिया है। दिल्ली में 2773, हरियाणा में 1838, पंजाब में 128, महाराष्ट्र में 3073, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव में 1577 और गुजरात में 1428 बिहारी मजदूरों ने राशन का उठाव किया।

खाद्य सचिव विनय कुमार के मुताबिक इस योजना का लाभ उठाने वाले प्रवासी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस साल अप्रैल में राशन का उठाव करने वाले बिहारी मजदूरों की संख्या 3249 थी, जो

फाइल फोटो/इंटरनेट मीडिया

जुलाई में करीब दोगुनी यानी 6419 रही। स्पष्ट है कि राज्य से बाहर जा रहे बिहार के मजदूर योजना का लाभ उठाने के प्रति जागरूक हैं।

खाद्य सचिव ने मंगलवार को बताया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से प्रदेश के 55.34 लाख राशन कार्डधारक लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लाभार्थी अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। वे ऐसा कर भी रहे। कौन लाभार्थी, कितने बजे और किस डीलर से कितना अनाज लेता है, इसका पूरा अपडेट विभाग को सर्वर सिस्टम से मिल जाता है।

राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया देख सकेंगे श्रद्धालु

जासं, अयोध्या : अब श्रद्धालु राम मंदिर निर्माण का कार्य आसानी से देख सकेंगे। इसके लिए रामलला के दर्शन पथ पर मंदिर के निर्माण स्थल (पश्चिम दिशा) की ओर की दीवार को तोड़कर बड़ा झरोखा खोला गया है। इसमें ग्रिल लगाई जा रही है। फिलहाल यह झरोखा लगभग दस फीट लंबा व पांच फीट ऊंचा है। जल्दी ही इसे बढ़ाकर 30 फीट लंबा किया जाना है। सोमवार को श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए पूरे मंदिर निर्माण के दर्शन किए। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपतराय ने इसकी जानकारी इंटरनेट मीडिया के जरिये लोगों से साझा की है। उन्होंने सूचित किया है कि अस्थायी मंदिर के दर्शन मार्ग पर यह व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने भी झरोखे से निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

1.10 करोड़ आबादी है चीन के वुहान शहर की। यहां तीन अगस्त से कोरोना जांच शुरू हुई थी और छह दिन में पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट कर लिया गया है।

तालिबान ने मजार-ए-शरीफ को चारों ओर से घेरा

अफगान संकट ▶ सेना और आतंकियों के बीच चल रहा भीषण संघर्ष

अमेरिका ने तालिबान पर बढ़ाया दबाव, हवाई हमले जारी रखने की कही बात

काबुल, एएनआइः अफगानिस्तान का बड़ा शहर मजार-ए-शरीफ भी तालिबान के कब्जे में आ सकता है। इस शहर को तालिबान आतंकियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और भीषण संघर्ष चल रहा है। तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान में एबक शहर पर कब्जे के बाद ताजिकिस्तान की सीमा से लगे मजार-ए-शरीफ को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस बड़े शहर पर हमले के साथ ही उसने बगलान के पुल ए खुमरी, बदख्शान प्रांत के फैजाबाद और फरह पर भी कब्जे के लिए अंतिम लड़ाई छेड़ दी है। लश्कर गाह, हेरात और कंधार शहर में पिछले कई दिनों से भीषण संघर्ष चल रहा है।

आइएएनएस के अनुसार, अमेरिका तालिबान पर हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। इस संबंध में वार्ता के लिए अमेरिका के अफगानिस्तान में विशेष दूत जालिमे खलीलजाद तीन दिन के लिए दोहा पहुंच गए हैं। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे के दौरान कई हवाई हमले किए। उसके बी-52 लड़ाकू विमान के हमले में 12 तालिबान आतंकी मारे गए। इनमें दो पाकिस्तानी भी हैं। एपी के अनुसार, अमेरिका ने कहा है कि अफगान सेना के समर्थन में उसके हवाई हमले जारी रहेंगे। हवाई हमलों की नीति में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जान किर्बी ने कहा है कि यह उनका देश है और उनका संघर्ष है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने माना है कि हालात बिगड़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह भी माना है कि जमीन पर चल रही लड़ाई सही दिशा में नहीं जा रही है।

अफगानिस्तान में तालिबानी आंतकियों का देश के कई प्रांतों में कब्जा होने के बाद उनके खौफ से बचने के लिए हजारों अफगान परिवारों ने राजधानी काबुल की ओर पलायन शुरू कर दिया है। उन्हें पार्कों और सड़कों के किनारे रहने को मजबूर होना पड़ा रहा। मंगलवार को एक पार्क में भोजन के इंतजार में अन्य प्रांतों से आए नागरिक। एपी

भारत ने अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई : अमेरिका

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में पिछले कई वर्षों से भारत की रचनात्मक भूमिका रही है जो सराहनीय है। भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास और स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जान किर्बी ने मंगलवार को कहा कि भारत की अफगानिस्तान के विकास में भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भारत ने यहां के विकास कार्यों में पूरा योगदान देने के साथ ही कई परियोजनाओं को सफलता से पूरा कर बेहतर अफगानिस्तान बनाने में योगदान दिया है। यहां उसने अफगान लोगों को ट्रेनिंग देने के भी कई कार्यक्रम चलाए हैं।

महिलाओं पर बर्बर अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

प्रेट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर जुल्म और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए हैं। 2009 से यहां पर चालीस हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब यहां महिलाओं पर बर्बरता चिंतित करने वाली है। युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए।

तालिबान ने 65 फीसद क्षेत्र पर कब्जा किया

रायटर के अनुसार, यूरोपीय यूनियन के एक शीर्ष अधिकारी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि यहां 65 फीसद हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो गया है। 11 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान भीषण लड़ाई लड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन के अधिकारी ने कहा है कि तालिबान ने समझौते का पालन नहीं किया।

अमेरिका की पाक को चेतावनी, बंद करे आतंकियों के घुसने के रास्ते

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह अपनी सीमा से आतंकवादियों को अफगानिस्तान में प्रवेश कराना बंद करे। अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने क्षेत्र में आतंकवादियों के अभ्यारण्यों को भी तुरंत समाप्त कर दे।

इस संबंध में अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन की पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर वार्ता हुई।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जान किर्बी ने बताया कि पाक से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वह अपनी जमीन को आतंकवादियों को इस्तेमाल न करने दे। उन्होंने पाक से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अफगानिस्तान की सेना की निरंतर मदद करता रहेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को तालिबान की सहायता देने वाली स्थितियों से बचना होगा।

ज्ञात हो, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सीमा से घुसे दस हजार विदेशी आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगान सेना से युद्ध कर रहे हैं। पाक ही सभी आतंकवादियों को शरण दिए हुए है।

अफगान हिंसा से चिंतित चीन का रूस के साथ युद्धाभ्यास

बीजिंग, एपी : अफगानिस्तान में अस्थिरता और बढ़ती हिंसा के बीच चीन और रूस की सेनाओं का शिनजियांग प्रांत की सीमा से लगे निंगशिया में युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। सेना का यह अभ्यास शुक्रवार तक चलेगा। इसमें दोनों ही देशों की थल और वायु सेना शामिल हैं। निंगशिया में दोनों देशों का युद्धाभ्यास इसलिये महत्वपूर्ण है कि यह शिनजियांग से लगा क्षेत्र है। जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और राजधानी बीजिंग से जुड़ी हुई हैं। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के यातना केंद्र बने हुए हैं। चीन और रूस दोनों ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर दोनों ही देश स्थिरता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह युद्धाभ्यास आतंकवाद के खिलाफ चल रहे उनके अभियान को मजबूती देगा। इससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी और समन्वय बढ़ाने में मदद मिलेगी। युद्धाभ्यास की शुरूआत सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य ली जुओचेंग ने की। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ने के साथ ही चीन अपने मुस्लिम क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर चिंतित है। उसे आशंका है कि उइगर मुस्लिमों के संगठन अफगानिस्तान से उसके क्षेत्र में घुस सकते हैं।

नीरव मोदी से जुड़े फैसले की समीक्षा कर रहे भारत व ब्रिटेन

लंदन, प्रेट्रः ब्रिटेन की क्राउन प्रासिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने वह मंगलवार को कहा कि प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी को अपील की अनुमति देने संबंधी लंदन हाई कोर्ट के फैसले की भारत के साथ समीक्षा कर रही है। उच्च न्यायालय के एक जज ने सोमवार को भगोड़े हीरा कारोबारी को मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने फैसले में उसे भारत प्रत्यर्पित करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। ताकि वहां जाकर भारतीय कोर्ट में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर सके। इसी फैसले के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक प्रवक्ता ने कहा, 'मोदी को दो आधारों पर भारत में अपने प्रत्यर्पण की अपील करने की अनुमति दी गई है। सीपीएस, भारत सरकार के साथ आगे की कार्रवाई के बारे में समीक्षा कर रहा है।' न्यायाधीश मार्टिन चेंबरलेन ने सोमवार को मोदी को अपील करने की अनुमति देते हुए कहा था कि नीरव के वकीलों द्वारा उसके गंभीर अवसाद और खुदकुशी के खतरे के संबंध में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, वह सुनवाई योग्य हैं। जज ने यह भी कहा था कि प्रत्यर्पण के बाद नीरव को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है। ऐसे में इन मुद्दों पर भी सुनवाई करने की आवश्यकता है कि क्या वहां खुदकुशी को रोकने के पर्याप्त उपाय हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने अन्य सभी आधारों पर अपील की अनुमति को अस्वीकार कर दिया था।

न्यूज गैलरी

प्रिंस एंड्रयू पर यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा

न्यूयार्क : अमेरिका के मैनहट्टन की जिला अदालत में वर्जीनिया गुफरे नामक महिला ने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि दो दशक पहले जब वह सिर्फ 17 साल की थी, तब उसका यौन उत्पीड़न किया गया था और इस बात से वह दो दशकों से परेशान रही है। गुफरे का आरोप है कि दिवंगत फाइनेंसर ने यौन उत्पीड़न के लिए उसकी तस्करी की थी। इस सिलसिले में महिला ने अब प्रिंस एंड्रयू पर केस किया है जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दूसरे बेटे हैं। (रायटर)

यूनिसेफ इथियोपिया में 100 से अधिक बच्चों की हत्या से चिंतित

अडिस अबाबा : संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की संस्था यूनिसेफ ने इथियोपिया में 100 बच्चों समेत 200 से अधिक लोगों की हत्या किए जाने की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है। देश में जारी गृह युद्ध में अब तक चार लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसमें भी कम से कम 1.60 लाख बच्चे अनाथों सा जीवन बिता रहे हैं। गत पांच अगस्त को ऐसे बच्चों के आश्रय स्थल व स्कूलों पर भी हमला हुआ था। यूनिसेफ ने कहा है कि इन बच्चों में जानलेवा कुपोषण बीस गुना अधिक होगा। (आइएएनएस)

ब्रिटेन के कई नागरिकों के प्रवेश पर रूस ने लगाई रोक

मास्को : रूस की सरकार ने घोषणा की है कि उसने ब्रिटेन के लगाए प्रतिबंधों के जवाब में कई ब्रिटिश नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। ब्रिटेन ने कुछ रूसी नागरिकों पर मानवाधिकार उल्लंघन व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह प्रतिबंध लगाए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बिना नाम बताए ही प्रतिबंधित ब्रिटिश नागरिकों की संख्या बता दी है। (आइएएनएस)

सिंगापुर में ठगी के आरोप में भारतीय मूल की महिला को जेल

सिंगापुर : भारतीय मूल की 55 वर्षीय महिला को सिंगापुर में धोखाधड़ी करने के लिए 20 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है। उस पर ग्राहकों से भारत से दुबई के टूर पैकेज के नाम पर 35 हजार एसजीडी झटकने का आरोप है। टुडे अखबार के मुताबिक एस.लीलावडी एक स्वतंत्र ट्रैवेल एजेंट है और उसने आठ पीड़ितों से भारत और दुबई के लिए 19 फर्जी ट्रिपों का बहाना करके मोटी रकम वसूल की है। (प्रेट्र)

किम जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को फिर दी धमकी

▶ युद्धाभ्यास से उत्तर कोरिया के साथ बढ़ा तनाव

▶ किम की बहन बोलीं, अमेरिका पहले सेना वापसी करे, तब होगी वार्ता

सियोल, एपी : अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश पिछले कुछ माह से उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में शुरू होने जा रहे दोनों देशों के युद्धाभ्यास से फिर तनाव हो गया है। उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को युद्धाभ्यास करने पर सीधे धमकाया है। साथ ही कहा है कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया अपनी सामरिक ताकत को तेजी से बढ़ाएगा। अच्छे संबंधों के लिए वार्ता भी तभी होगी, जब अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपने हथियार और सैनिकों को वापस ले जाएगा।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की शक्तिशाली बहिन किम यो जोंग ने अमेरिका और उत्तर कोरिया के लिए धमकी भरा बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें यह कड़ा संदेश देने के लिए उनके भाई ने अधिकृत किया है।

उन्होंने अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन की भी आलोचना करते हुए कहा कि वह अच्छे संबंध रखने का पाखंड कर रहा है।

ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया के उत्तर कोरिया से अच्छे संबंधों की शुरूआत हुई है। वर्षों से बंद पड़ी दोनों देशों के बीच हाटलाइन सेवा भी शुरू हो गई है। उत्तर कोरिया की धमकी से लगता है कि अब दूरियां फिर बढ़ेंगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया 16 से 26 अगस्त तक युद्धाभ्यास की प्रारंभिक तैयारी शुरू कर रहे हैं।

उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग (फाइल फोटो) रायटर

रायटर के अनुसार किम यो जोंग के बयान पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों ने ही कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके साथ ही बताया गया है कि युद्धाभ्यास जारी रहेगा।

ताइवान को लेकर चीन ने लिथुआनिया से वापस बुलाया अपना राजदूत

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने लिथुआनिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। उसकी नाराजगी की वजह लिथुआनिया का ताइवान को अपने यहां एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति देना है। लेकिन चीन के राजदूत वापस बुलाने के फैसले से यूरोपीय संघ से संबंध खराब हो सकते हैं।

ताइवान द्वीप वर्ष 1950 से स्वतंत्र है, लेकिन चीन उसे बागी क्षेत्र मानते हुए उस पर अपना हक जताता है। और चाहता है कि मुख्य चीन से उसे फिर से जोड़ दिया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान को अपने देश में एक प्रतिनिधि कार्यालय उसी के नाम से खोलने की अनुमति देकर लिथुआनिया ने कूटनीतिक रिश्तों का उल्लंघन किया है। चीन सरकार लिथुआनिया के इस कदम का कड़ा विरोध करती है। साथ ही विरोध स्वरूप उसने अपना राजदूत वहां से बुलाने का फैसला किया है। चीन ने लिथुआनिया सरकार से कहा है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। इस संपूर्ण चीन की केवल एक सरकार है।

पाकिस्तान में बहुत गहरी हैं हिंदू विरोध की जड़ें

रिपोर्ट

▶ जबरन मतांतरण से लेकर पूजा स्थलों को अपवित्र करने तक की घटनाएं होती हैं

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को इस्लामी उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। जबरन मतांतरण से लेकर पूजा स्थलों को अपवित्र करने तक की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हालांकि, दक्षिण एशियाई देश की हिंदू विरोधी कट्टरता विशिष्ट रूप से संस्थागत बनी हुई है।

पिछले हफ्ते पंजाब प्रांत के भोंग गांव में उन्मादी भीड़ ने नारेबाजी करते हुए एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और वहां रखी मूर्तियों को अपवित्र किया। मंदिर पर हमले की व्यापक निंदा के बावजूद पाक की कई पार्टियों के सदस्यों और यहां तक कि इमरान खान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने भी 'ईशनिंदा करने वालों' के लिए दंड के समर्थन में हिंदू विरोधी कट्टरता व्यक्त की या उसके समर्थन में रैली तक कर डाली।

द डिप्लोमैट के लिए लिखते हुए कुंवर खुलदुने शाहिद ने कहा, भोंग में भीड़ की हिंसा ने पाक में हिंदू विरोधी भावना की गहरी वैचारिक जड़ों को प्रदर्शित किया है। पहले ईशनिंदा कानून के जरिये दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। हजारों पीड़ितों को कैद, घायल या निष्कासित कर दिया गया। कानून इस्लामवादी भीड़ को आहत इस्लामी भावनाओं को स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करता है।

पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं को प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

शाहिद ने लिखा है कि हिंसक इस्लामी सर्वोच्चता इस्लामवादियों या अवसरवादी राजनेताओं द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा स्वीकृत है। फर भी शासन विरोधाभासी रूप से पाक को एक लोकतांत्रिक गणराज्य जताने की कोशिश करता है। उनका यह सिद्धांत सऊदी अरब या ईरान जैसे निर्विवाद धर्मतंत्र के विपरीत दिखाने की कोशिश के बावजूद उसका चलन उनके जैसा ही है। इस्लामी भीड़ को मनमाने फैसले सुनाने का जिम्मा सौंपता है और उन्हें हर जगह ईशनिंदा या इस्लाम विरोध पर नजर रखते हुए उन्हें सजा देने के लिए उकसाता रहता है।

थिंक टैंक सेंटर ऑफ पालिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स (सीपीएफए) के अनुसार, इस्लाम के प्रभुत्व वाले पाकिस्तान में सुन्नी संप्रदाय से संबंधित एक बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण है। मारियो डी गैस्पेरी ने अपनी सीपीएफए रिपोर्ट में तर्क दिया कि पाकिस्तान अपने संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद अपने नेताओं द्वारा किए गए राजनीतिक निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से धार्मिक असहिष्णुता की अपनी वर्तमान स्थिति में उतर गया है।

हिंदू समुदाय के अलावा पाक में ईसाई समुदाय के खिलाफ भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। सीपीएफए की रिपोर्ट के अनुसार, ईशनिंदा कानून अल्पसंख्यकों के लिए पीड़ा का स्रोत बना हुआ है। एक झूठा आरोप अपने आप में सजा हो सकता है, क्योंकि कई मामलों ने आरोपित व उनके परिवारों के खिलाफ क्रूर भीड़ की हिंसा को उकसाया है। थिंक टैंक ने आगे कहा, पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी अधिकारी अल्पसंख्यकों को आस्था आधारित हिंसा से बचाने में नाकाम रहे हैं।

पाकिस्तान में लोकतंत्र और संविधान बस नाम का : हामिद मीर

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के लिए शायद ही कोई जगह बची है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान केवल नाम के रह गए हैं।

पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार टीवी शो कैपिटल टॉक के होस्ट रह चुके हामिद मीर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में लोकतंत्र है, इसके बावजूद यहां कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में संविधान भी है, पर वहां कोई संविधान नहीं है। जून में मीर पर दो बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। उनका अपहरण भी हो चुका है। एक अन्य पत्रकार पर हुए हमले के बाद सेना के खिलाफ बोलने पर मीर को शो से निकला भी जा चुका है। बीबीसी के होस्ट स्टीफन सकर से बातचीत के दौरान मीर ने कहा, पत्रकार चाहते हैं कि पाक में कानून-व्यवस्था स्थापित हो। अगर को पत्रकार कोई सवाल करता है तो उसकी आवाज बंद नहीं की जानी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या पत्रकारों पर हमलों में खुफिया एजेंसियों का हाथ है तो उन्होंने कहा कि इसके दस्तावेजी सुबूत हैं। सरकारी एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां पत्रकारों पर हमले कराती हैं या उनका अपहरण कर लेती हैं।

पंजाब प्रांत में तोड़े गए मंदिर को बनाने में लगेंगे दो महीने

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में उन्मादी भीड़ के हमले में क्षतिग्रस्त हुए मंदिर को दोबारा बनाने का काम तेज हो गया है। मूर्तियों को बनाने के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। इसमें दो माह का समय लग सकता है। मंदिर हिंदू समुदाय को सौंप दिया गया है।

जिले के उपायुक्त खुर्रम शहजाद ने 60 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहसिन इम्तियाज व अन्य अफसरों के साथ भोंग के गणेश मंदिर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से कहा, मंदिर को ठीक कर दिया गया है। प्रतिमा स्थापित करने का काम चल रहा है। साथ ही मंदिर के चारों ओर चारदीवारी बनाई जा रही है। पुलिस ने मंदिर और हिंदुओं की सुरक्षा का प्लान भी बना लिया है। मंदिर की मूर्तियों के जीर्णोद्धार में दो माह का समय लगेगा। उन्होंने कहा, मंदिर पर हमले के मामले में अब तक सौ लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता और सीनेटर दानेश कुमार ने कहा, मंदिर पर हमला अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ी साजिश है।

सऊदी अरब ने उमरा के लिए पाकिस्तान समेत नौ देशों को दिखाया रेड सिग्नल

इस्लामाबाद, एएनआइ : सऊदी अरब ने उमरा के लिए पाकिस्तान समेत नौ देशों के यात्रियों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री नूर उल हक कादरी ने यह जानकारी दी है। इधर, पाकिस्तान की केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटिश सरकार के उनके देश को कोविड के चलते यात्रा के लिए प्रतिबंधित देशों की सूची में रखने के फैसले पर रोष जताया है।

बाखबर सवेरा अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के मंत्री नूर उल हक कादरी ने स्वीकारा कि पाक अभी भी उन नौ देशों में शामिल है, जिनके नागरिकों को सऊदी अरब में प्रवेश की इजाजत नहीं है। ध्यान रहे कि सऊदी अरब ने कुछ शर्तों के साथ उमरा के लिए उन यात्रियों को इजाजत दे दी है कि जिनको कोविड के दो टीके लग चुके हैं। जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सीनोफार्म समेत एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड, फाइजर, माडर्ना या जानसन एंड जानसन की वैक्सीन लगाई है, वही लोग सऊदी अरब में प्रवेश पा सकेंगे।

ब्रिटेन के पाक यात्रियों को रेड लिस्ट में डालने से उखड़ा पाकिस्तान

इस बीच, पाक के जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार को मानवाधिकार मंत्री शीरीन मजारी ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा के लिए ब्रिटेन ने कभी भी पाकिस्तान से कोविड-19 के हालात संबंधी डाटा नहीं मांगा है। मंत्री उस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थीं जिसमें कहा गया है कि पाक को रेड लिस्ट में डाला गया है क्योंकि उसने ब्रिटिश प्रशासन को टीकाकरण व कोविड परीक्षण से संबंधित आंकड़े मुहैया नहीं कराए हैं।

मजारी ने ट्वीट करके इसे बकवास बताते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरे विश्व को पता है कि भारत कोविड को बहुत ही लापरवाही से ले रहा है। इसके बावजूद ब्रिटेन ने उसे रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। जबकि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है। उसके बाद बचकाना आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कोविड संबंधी आंकड़े ही नहीं दिए हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने कोविड के हालात में यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी जो चर्चिल के छह अगस्त के लिखे पत्र के अनुसार पाकिस्तान को खतरे वाले देशों की सूची में रखने की वजह स्पष्ट की गई है।

कोरोना का कहर

अमेरिका में तेजी से बढ़ने लगे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज

डेल्टा वैरिएंट से गंभीर मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि, चीन में जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज

न्यूयार्क, रायटर : अमेरिका में डेल्टा वैरिएंट का कहर कम नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या पिछले छह माह में सबसे ज्यादा हो गई है।

अमेरिका में औसतन हर रोज एक लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। डेल्टा वैरिएंट के कारण गंभीर मरीजों की संख्या में 40 फीसद की वृद्धि हो गई है। इसके साथ ही अब कई स्थानों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी निरस्त किए जा रहे हैं। दक्षिण डकोटा की मोटरसाइकिल रैली इस वर्ष भी रद कर दी गई। फ्लोरिडा में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या पिछले आठ दिनों में तेजी से बढ़ी है। यहां स्कूलों के खुलने के बाद सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजरायल, फ्रांस और थाईलैंड की यात्रा टालने के लिए कहा है।

प्रेट्र के अनुसार, चीन में मंगलवार को कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। इनमें से अधिकांश मामले ऐसे हैं, जो स्थानीय संक्रमण के हैं। चीन में कोरोना की नई लहर से देश में चिंता है। यहां कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। राजधानी बीजिंग को संक्रमण से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर कई उड़ानों को रद कर दिया गया है। जिन स्थानों पर संक्रमण की गति तेज है, उन स्थानों से बीजिंग आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1702 है, इनमें 54 गंभीर किस्म के मरीज हैं।

सतर्कता है जरूरी...: वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अमेरिका सहित तमाम अन्य देशों में जहां सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के लोग घूमते-फिरते देखे जा रहे हैं, वहीं जापान में काफी सतर्कता दिख रही है। टोक्यो के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को मास्क लगाकर आवागमन करते लोग। एएफपी

पाक में अक्टूबर से वैक्सीन लगे यात्री ही कर सकेंगे ट्रेन यात्रा : प्रेट्र के अनुसार, पाकिस्तान में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि अक्टूबर माह से वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी। पाक ने स्थानीय उड़ानों में पहले से ही यह नियम लागू कर रखा है।

कनाडा ने भारत से सीधी उड़ान पर 21 सितंबर तक बढ़ाई रोक: एएनआइ के अनुसार, कनाडा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत से सीधी उड़ान पर रोक को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

बांग्लादेश : यहां पर अब रोहिंग्या शरणार्थियों को भी टीके लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।

छह साल बाद हटा उड़ान से प्रतिबंध

दुखद विमान हादसे के करीब छह साल बाद रोसिया एयरलाइंस की उड़ानों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। मिस्र के शर्म अल-शेख एयरपोर्ट पर मंगलवार को एयरलाइंस की पहली उड़ान के लिए तैयार विमान को वाटर सैल्यूट देकर विदाई दी गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में शर्म अल शेख से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ने वाला रूसी विमान चंद मिनटों बाद सिनाई क्षेत्र में क्रैश हो गया था। इस हादसे में सवार सभी 224 यात्री एवं क्रू मेंबर्स मारे गए थे। हादसे के बाद मिस्र और ब्रिटेन सहित कई देशों ने सुरक्षा कारणों से सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। रायटर

अभी भी सर्वश्रेष्ठ की तलाश कर रहे हैं भारतीय सितारे

टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय पुरुष हाकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने टीम को कांस्य पदक जिताया। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने एतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया तो पहलवान रवि दहिया ने भी अपने पहले ओलिंपिक में कमाल करते हुए रजत पदक हासिल किया। हालांकि इन खिलाड़ियों का मानना है कि उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। मनप्रीत ने कहा कि पेरिस 2024 ओलिंपिक में वह पदक का रंग बदलना चाहेंगे तो नीरज ने कहा कि उनका सपना 90 मीटर का थ्रो फेंकना है। जबकि रवि दहिया भी आगामी ओलिंपिक में स्वर्ण पदक के साथ संतुष्ट होना चाहते हैं।

टीम में जादुई ताकत : मनप्रीत

मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हाकी टीम ने 41 साल बाद ओलिंपिक में पदक जीतकर अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त किया। जिसके पीछे मनप्रीत ने आस्ट्रेलियाई मूल के भारतीय कोच ग्राहम रीड का आभार व्यक्त किया। मनप्रीत का मानना है कि उनके आने से टीम में जादू की तरह बदलाव आया है। जिससे हम पदक जीतने में कामयाब रहे। टोक्यो से पदक जीतकर लौटे **मनप्रीत सिंह** से **शुभम पांडेय** ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :

● मनप्रीत आपने बतौर कप्तान देश को 41 साल बाद हाकी में कांस्य पदक जिताया। इसे कैसे देखते हैं?

-बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि पिछला पदक (1980 मास्को ओलिंपिक स्वर्ण पदक) 41 साल पहले आया था और तब मैं जन्मा भी नहीं था। तो उस खुशी के पल के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन हां, अभी पदक हासिल करके सभी बहुत खुश हैं। यह मेरा तीसरा ओलिंपिक था, लंदन 2012 एक तरह से काफी खराब रहा क्योंकि हमने सबसे निचला स्थान हासिल किया था। उस समय से निकल कर 2016 रियो ओलिंपिक में क्वार्टर फाइनल में हारे। जिसके बाद तीसरे ओलिंपिक में पदक लाने से काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है।

● 2012 के समय को भारतीय हाकी का काला समय भी कहा जाता है। उसके बाद आपके सामने ही पिछले आठ वर्षों में भारतीय हाकी पूरी तरह से बदलती चली गई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?

- 2012 का समय वाकई काफी खराब रहा था और हार के बाद जितना खराब एक एथलीट को लगता है। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी को लगता होगा। क्योंकि वह पूरी मेहनत करता है और जब ऐसा प्रदर्शन होता है तो काफी मनोबल भी टूट जाता है। जिसके बाद हमने ठान लिया कि अब हमें आगे अच्छा करना है। इसकी शुरुआत 2014 एशियन गेम्स से शुरू हुई क्योंकि उसमें हमने स्वर्ण पदक हासिल किया फिर राष्ट्रमंडल खेलों में हमने रजत पदक जीता। इसके बाद 2016 में हमने चैंपियनशिप ट्राफी में भी रजत पदक जीता। इन टूर्नामेंट से टीम का आत्मविश्वास लौटा और हमारी टीम में कई सुधार भी हुए।

● 2018 विश्व कप में हमें नीदरलैंड्स से हार मिली, उसके बाद ओलिंपिक के सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार मिली। इस तरह की उच्च टीमों के खिलाफ क्या अभी हमारी टीम कमजोर है?

- अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जब सभी पूरी तरह से जश्न मनाने के बाद वापस अभ्यास शिविर में लौटेंगे तो हम वीडियो विश्लेषण के जरिये पता लगाएंगे कि कहां पर हमसे गलतियां हुई तो अभी हमें यही नहीं रुकना है। हमारी रणनीति बस यही है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और टीम की कमजोरियों को दूर करके आगामी ओलिंपिक में पदक का रंग बदलना है।

● ओलिंपिक के ग्रुप मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से हराया। उसके बाद आपने टीम को कोच के साथ मिलकर कैसे संभाला?

- जब हम बुरी तरह हारे थे तो उस समय पूरी टीम निराश थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह नाकआउट मैच नहीं था। हमने अपने खिलाड़ियों को समझाया कि अगर अब भी हम अपने आगामी तीन मैचों को जीत लेते हैं तो ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहेंगे। हमने आस्ट्रेलिया वाले मैच का विश्लेषण किया तो पता चला कि इतना भी बुरा नहीं खेले थे। वह दिन आस्ट्रेलिया का था और गोल दागते चले जा रहे थे। हमारी यही मानसिकता थी कि हमने अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ हाकी नहीं खेली है।

● साल 2018 में टीम के कोच हरेंद्र सिंह थे, लेकिन उसके बाद ग्राहम रीड को कोच बनाया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?

- ग्राहम सर का यही मानना था कि भारतीय हाकी के पास कई जादुई खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके होने से भी टीम को नतीजा नहीं मिल पा रहा है। हम कई बार विरोधियों के खेमे में जा रहे थे, लेकिन वहां से गोल नहीं कर पा रहे थे। इसमें काफी सुधार हुआ। ओलिंपिक में भले ही हम कम मौकों पर विरोधियों के खेमे में आक्रमण के लिए गए हो, लेकिन हमने अधिक से अधिक मौकों को भुनाया है। यह एक तरह का जादू उनके आने से हमारे अंदर आया है। उन्होंने टीम को बदलकर रख दिया है।

90 मीटर के करीब हूं : नीरज चोपड़ा

भारतीय एथलेटिक्स को 100 साल से भी अधिक समय बाद पहला पदक स्वर्ण के रूप में दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का मानना है कि वह इस समय क्यों न देश के बड़े सितारों की फेहरिस्त में शामिल हो गए हों लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खेलों पर ही रहने वाला है। अब स्वर्ण पदक (87.65 मीटर के थ्रो) जीतने के बाद मेरा सपना 90 मीटर से अधिक का थ्रो फेंकना है। टोक्यो से ओलिंपिक चैंपियन बनकर लौटे **नीरज** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :

● नीरज आपने एथलेटिक्स में भारत का खाता स्वर्ण पदक से खोला। क्या आपको ओलिंपिक में पहले यकीन था कि आप ऐसा करने वाले हैं?

-हर एथलीट का ओलिंपिक में पदक जीतने का सपना होता है और स्वर्ण जीतने से बेहतर कोई भावना नहीं होती है। जब मैंने इसे जीता तो यह सपने जैसा लगा। इस बात पर यकीन पाने के लिए फिर मैं अपना स्वर्ण पदक देखता था तो खुद से कहता था यह तो मेरे पास है ही। अब हमारा लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप का पदक है, जो हमारे लिए, एथलेटिक्स में अंजू बाबी जार्ज ने जीता है। एक पदक जीतने के बाद रुकना नहीं चाहिए। अब और पदक जीतने की कोशिश करूंगा। स्वदेश वापस लौटने पर जिस तरह का सम्मान मिला उसने मुझे अहसास दिलाया कि मैंने क्या उपलब्धि हासिल की है।

● अब आप एक सुपरस्टार बन गए हैं और बहुत से लोगों को देखा है कि सफलता की ऊंचाईयों पर खुद को संभाल नहीं पाते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं?

-मैं इस बारे में तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है कि प्रशंसकों से इतना प्यार मिल रहा है लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान अगले साल होने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के अलावा आने वाले टूर्नामेंट और पेरिस ओलिंपिक खेलों पर है। बस अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करूंगा और उसी पर ज्यादा ध्यान रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है वही चीज बहुत जरूरी है। खेलों में ऐसी सोच आना थोड़ा खतरनाक हो जाता है।

● 90 मीटर दूरी का थ्रो हमें नीरज से कब देखने को मिलेगा?

90 मीटर थ्रो फेंकने की तैयारी तो इस बार ही थी। भाला फेंक थोड़ा तकनीक पर आधारित खेल है। मैं इसके आस-पास था। इस बार सोच रहा था कर दूंगा। 90 मीटर थ्रो फेंकना मेरा सपना है जिसे मैं जल्द ही जरूर पूरा करूंगा।

● आप ओलिंपिक में अपने अंतिम थ्रो से पहले ही स्वर्ण पदक जीत चुके थे तो उस समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था?

-देखिए शुरुआत में मेरे दो थ्रो बहुत अच्छे गए। फिर बीच में कई थ्रो खराब गए। अंतिम वाले थ्रो से पहले मुझे पता था कि मैं स्वर्ण जीत चुका हूं। ऐसे में थ्रो फेंकते समय बहुत शांत रहता हूं लेकिन उस थ्रो से पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खो सा गया था और बस मैंने थ्रो फेंक दिया लेकिन वह भी अच्छा गया।

● ओलिंपिक में कई बार डोप टेस्ट होता है तो क्या एक एथलीट पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है?

–जी हां, डोप टेस्ट तो होता ही है। जब स्वीडन से टोक्यो गए तो लगातार सुबह तीन दिन जल्दी डोप टेस्ट लिया तो उससे थोड़ा परेशानी हुई। हालांकि बाद में लंबी नींद लेकर खुद को तरोताजा किया।

● आपने कोच उवे हान के साथ भाला फेंक का अभ्यास किया और फिर दूसरे कोच क्लाउस बर्तोनित्ज के साथ अभ्यास शुरू किया। इस तरह दोनों से सिखाने की तकनीक में क्या अंतर देखते हैं?

-कोच हान के साथ जितना काम किया उनका मैं आदर करता हूं। हालांकि उनकी तकनीक से बेहतर मुझे कोच क्लाउस की तकनीक लग रही थी इसलिए मैंने भारतीय एथलेटिक्स संघ से निवेदन किया और उन्होंने मान लिया। क्लाउस के साथ अभ्यास करने का फैसला मेरा था। वह बहुत अनुभवी हैं जिसका मुझे फायदा मिला। हान सर ने मेरी क्षमता पर काम किया लेकिन तकनीक के मामले में क्लाउस सर का मैं आभारी हूं।

● टोक्यो ओलिंपिक 2020 की जगह 2021 में होने से क्या आपको फायदा मिला?

-जनवरी 2020 में जब मैंने क्वालिफाई किया तो मैं टोक्यो ओलिंपिक के लिए फिट और तैयार था। 2019 थोड़ा कठिन था लेकिन 2020 में मैं पूरी तरह से फिट था। हालांकि मैंने ओलिंपिक के स्थगन को सकारात्मक रूप से लिया क्योंकि मुझे लगा कि प्रशिक्षण के लिए एक और साल मिल गया है। उस एक साल में, मैंने अपनी कमजोरियों जैसे कि तकनीक और ताकत में सुधार किया और इसका फायदा भी मिला।

● आपको अपने करियर के दौरान कब लगने लगा था कि ओलिंपिक तक जा सकता हूं और पदक जीत सकता हूं?

राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद जब मुझे नेशनल कैंप में चुना गया तो उसका फायदा मुझे मिला क्योंकि पहले हम खुद खाना बनाते थे। कैंप में सब कुछ बेहतर मिलने लगा। उसके बाद सब कुछ बदलता चला गया। अच्छी सुविधाएं मिलीं और मैंने अपनी तैयारी में जोर लगाना शुरू कर दिया।

पेरिस में स्वर्ण जीतूंगा : रवि

एक पहलवान चोट के कारण तीन साल अखाड़े से दूर रहता है तो उसकी वापसी मुश्किल होती है। ऐसे बहुत कम पहलवान देखने को मिलते हैं जिन्होंने ऐसे में वापसी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया हो। चोट से उबरने के बाद मात्र दो साल की तैयारी में ओलिंपिक में रजत पदक जीतकर रवि दहिया ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। **रवि दहिया** से **अनिल भारद्वाज** ने खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

● आप किसान के बेटे हैं। आपने रजत जीत लिया है तो क्या अब स्वर्ण की आस कर सकते हैं?

- मैं पेरिस में वह भी दूंगा। तीन साल बाद पेरिस में स्वर्ण पदक अपने नाम करूंगा।

● टोक्यो में आपने हर मुकाबले में आक्रामक रुख दिखाया, लेकिन फाइनल में वह रुख नहीं दिखा।

- रूस के पहलवान अच्छे होते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे मुकाबले उन्हें अधिक अनुभव है। फाइनल में मेरा 100 प्रतिशत देने का लक्ष्य था, लेकिन वह मेरे से अच्छा खेला और चैंपियन बना। यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि भविष्य में मुकाबले होते रहेंगे। रूस के पहलवान को अब मेरे से मुकाबला करना मुश्किल साबित होगा।

● कजाख पहलवान आपके हाथ को दांतों से काटता रहा, लेकिन आपने उसे छोड़ा नहीं?

- ऐसा कोई नहीं होगा जिसे दर्द न हो, लेकिन मेरा लक्ष्य उसे हराना ही था। मुकाबले का समय खत्म होने वाला था। अगर मैं दर्द के लिए उसे छोड़ देता तो वह जीत जाता। जीत का मौका मैं किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहता था। उसी दांव पर जीत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी जुनून में मैं दर्द भूल गया।

● इस बार ओलिंपिक पर खेलप्रेमियों व प्रधानमंत्री की खास नजर थी, क्या इसका दबाव था?

-खिलाड़ी पर खेलप्रेमियों व प्रधानमंत्री की आशाओं पर खड़ा उतरने का जुनून था। हर खिलाड़ी इस बात को लेकर उत्साहित था कि उनके खेल को देश का प्रधानमंत्री देख रहा है। इसी बात से हमें जीतने का हौंसला मिल रहा था। मैं स्वयं कह सकता हूं कि टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन इसी कारण कर पाया हूं।

● आपने सिर्फ दो वर्ष प्रशिक्षण किया और ओलिंपिक में पदक जीत लिया। इसके पीछे राज क्या है?

- राज कुछ नहीं है। कुश्ती के प्रति अपने को समर्पित करना। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का पहलवानों के साथ सहयोग बहुत होता है। किसी भी पहलवान को सुविधा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मुकाबले मिलना उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत है। जब मैंने चोट से ठीक होकर 2018 में वापसी की तो मेरे सामने टोक्यो का लक्ष्य था, लेकिन यह आसान नहीं था। मैंने यही सोचकर प्रशिक्षण शुरू किया कि मेहनत करनी है, इसके बाद देखा जाएगा। इसी वर्ष 2018 में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप हुई और मैं यहां रजत पदक जीत कर लाया। इसके बाद मुझे अपने पर विश्वास हो गया था कि मैं टोक्यो का टिकट हासिल कर सकता हूं। चोट ने मुझे कई वर्ष दूर रखा तो भाग्य ने बाद में साथ भी दिया। वर्ष 2019 में सीनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं सही राह पर हूं और टोक्यो का सपना पूरा कर सकता हूं।

> मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। मेरे गांव के बहुत पहलवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं और गांव में कुश्ती को बहुत अच्छा माहौल है। सरकार द्वारा जो सेंटर बनाया जाएगा उससे मेरे गांव व आसपास के गांवों के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा।

● वर्ष 2015 में चोट लगने के बाद आपको अपनी वापसी का विश्वास था?

- जब चोटिल हुआ तो तीन साल अखाड़े से दूर रहा। एक बार लगा था कि कुश्ती दोबारा नहीं हो पाएगी, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। तब मन दुखी होता था कि मेरे साथ क्या हुआ। बस एक ही विश्वास था कि अगर ठीक हो गया, तो मेहनत बहुत करनी है।

● जब आप छोटे थे तो बहुत कमजोर थे और परिवार के लोग कहते थे कि ये क्या पहलवान बनेगा?

- हंसते हुए, हर परिवार अपने बच्चे पर दया करता है। उन्हें लगता था कि मैं कमजोर हूं तो दूसरे पहलवान मुकाबले में दबा लेंगे, लेकिन मेरा कुश्ती करने का जुनून था। मेरे फैसले को परिवार का साथ मिला और विश्वास किया। जब-जब मैं अपने वजन के मुकाबलों में उतरता था तो जीत दर्ज करता था।

● हरियाणा सरकार ने क्लास वन की नौकरी देने की घोषणा की है। क्या आप रेलवे को छोड़ दोगे?

कुछ नहीं बता सकता। सच यह है कि इस पर अभी कुछ नहीं सोचा है। जब कोई निर्णय लिया जाएगा, तो सभी को बताया जाएगा।

एक नजर में

क्रिस केर्न्स की हालत नाजुक

मेलबर्न : न्यूजीलैंड के पूर्व आलराउंडर क्रिस केर्न्स को अचानक बेहोश होने के बाद कैनबरा में वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले हफ्ते कैनबरा में उन्हें गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति ओरटिक डिसेक्सन का सामना करना पड़ा। ओरटिक डिसेक्सन एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर की मुख्य धमनी की भीतरी परत को नुकसान पहुंचता है। अस्पताल में उनके कई आपरेशन हुए, लेकिन उनका शरीर उपचार पर उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। (प्रेट्र)

द्रविड़ कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली : बीसीसीआइ ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में क्रिकेट प्रमुख के लिए पद के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके मौजूदा प्रमुख और भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ फिर से आवेदन कर सकते हैं। (प्रेट्र)

आइपीएल में कीवी क्रिकेटर

आकलैंड : न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की आइपीएल में भागीदारी को मंगलवार को उसके क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड ने टी-20 विश्व कप और उसके बाद भारत के लिए टीमें चुनी हैं। आइसीसी टी-20 विश्व कप और भारत के खिलाफ टी-20 के लिए टीम : केन विलियमसन (कप्तान), टाड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कोनवे, लाकी फर्ग्युसन, मार्टिन गुप्टिल, काइल जेमिसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, टिम साउथी, एडम मिल्ने (किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर)। (प्रेट्र)

यूएस ओपन खेलेंगे नोवाक

सिनसिनाटी : विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गए हैं जिसका मतलब है कि अब वह यूएस ओपन के दौरान ही कोर्ट पर दिखेंगे जहां वह करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जोकोविक ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि उन्हें आस्ट्रेलिया से लेकर टोक्यो तक के व्यस्त कार्यक्रम के बाद तरोताजा होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। (एपी)

अंडर -18 तीरंदाजों ने तोड़े दो विश्व रिकार्ड

रौक्लाव, प्रेट्र : तीरंदाजी में भारत की कंपाउंड वर्ग की लड़कियों और मिक्स्ड टीम ने मंगलवार को विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रैंकिंग दौर में दो अंडर-18 विश्व रिकार्ड तोड़े। प्रिया गुर्जर, परनीत कौर और रिद्धु सेंथिल कुमार की टीम ने 2067 अंक के साथ पिछले रिकार्ड में 22 अंक का सुधार किया। इससे पहले 2017 में अमेरिका की तिकड़ी (कीन सेंचिको, ब्रीना थियोडोर और सवाना वेंडरवियर) तीरंदाजों के नाम 2045 अंकों के साथ विश्व रिकार्ड दर्ज था। इसके बाद प्रिया ने कुशाल दलाल (705) के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में भी 1401 अंक के साथ विश्व रिकार्ड बनाया। जो कि पहले डेनमार्क की नताशा और मथियास की जोड़ी ने 2019 में मैड्रिड विश्व युवा चैंपियनशिप में 1387 अंक जुटाकर विश्व रिकार्ड बनाया था।

अनुशासनहीन विनेश को किया गया निलंबित

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

ओलिंपिक में स्वर्ण पदक की दावेदार के रूप में गईं विनेश फोगाट अपने खराब प्रदर्शन से ना तो कोई पदक जीत पाईं, बल्कि टोक्यो में अपने खराब व्यवहार के कारण अब प्रतिबंध भी झेलना पड़ गया। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) ने मंगलवार को कहा कि उन्हें टोक्यो में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया। वहीं, एक अन्य पहलवान सोनम मलिक को भी दुर्व्यवहार के लिए नोटिस जारी किया गया। विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है।

विनेश फोगाट ● फाइल फोटो, ट्विटर

हरियाणा की विनेश पर अनुशासनहीनता के तीन आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने खेल गांव में रहने और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की पोशाक नहीं पहली बल्कि अपने मैचों के दौरान नाइकी की पोशाक पहनी थी। डब्ल्यूएफआइ के एक सूत्र ने बताया कि विनेश सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित रहेंगी। जवाब नहीं देने तक वह किसी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा पेश नहीं कर पाएंगी। सूत्र ने बताया कि विनेश को जब सोनम, अंशु मलिक और सीमा बिसला के करीब कमरा आवंटित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह कोरोना से संक्रमित हो सकती हैं क्योंकि ये पहलवान भारत से टोक्यो आई हैं। विनेश ने उनके साथ ट्रेनिंग भी नहीं की। विनेश हंगरी से टोक्यो पहुंची थीं। वहीं, टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले सोनम या उनके परिवार को डब्ल्यूएफआइ के कार्यालय से पासपोर्ट लेना था। लेकिन उन्होंने साई अधिकारियों को उसके लिए पासपोर्ट लाने का आदेश दिया। जब यह बात महासंघ को पता चली तो उन्होंने नोटिस जारी किया।

जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे से मिले सूबेदार नीरज

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को ओलिंपिक में पहले एथलेटिक्स स्वर्ण पदक हासिल करने पर भारतीय सेना में पदोन्नति मिलने की संभावना है। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सूबेदार नीरज चोपड़ा की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी, जिसने देश को गौरवान्वित किया। सेना में संबंधित विषय के जानकारों ने कहा कि चोपड़ा को उनके शानदार प्रदर्शन के चलते निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत पदोन्नति मिलेगी। रक्षा मंत्री एवं सशस्त्र बलों ने भी उन्हें सच्चा सैनिक बताया। मालूम हो कि नीरज 15 मई 2016 को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के तौर पर चार राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए थे।

राधाकृष्ण बोले, इस बार चार तिरंगे लेकर गया था टोक्यो : एएफआइ के कोच राधाकृष्ण नायर ने कहा कि ये मेरा कोच के तौर पर दूसरा ओलिंपिक था। इस बार लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि पहले एथलीटों को काफी तवज्जो दी जा रही थी। सरकारें कार्यक्रम कर रही थीं। सकारात्मक माहौल था। ओलिंपिक में मैं तिरंगे लेकर नहीं जाता था लेकिन क्योंकि पता था एथलेटिक्स में पदक आना नहीं है लेकिन इस बार मैं चार झंडे लेकर गया। जैसे ही नीरज ने पदक जीता, वैसे ही मैंने उन्हें तिरंगा दिया और उन्होंने उसके साथ दौड़ लगाई।

भारतीय ओलिंपिक दल की मेजबानी करेंगे राष्ट्रपति कोविन्द

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द शनिवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय ओलिंपिक दल की चाय पर मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करके यह जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन के अनुसार, 'भारत के राष्ट्रपति 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चाय पर टोक्यो ओलिंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे।'

अब सात अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस

नई दिल्ली : नीरज चोपड़ा ने सात अगस्त को टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगा। 23 साल के चोपड़ा टोक्यो में शनिवार को 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर ओलिंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। एएफआइ के चेयरमैन ललित भनोट ने कहा, 'पूरे भारत में भाला फेंक को बढ़ावा देने के लिए हम सात अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे व अगले साल से इस दिन अपने अपने राज्यों में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगी। इसके बाद अंतर जिला प्रतियोगिताएं होंगी व इसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता बनाएंगे।'

एक तिहाई रकम में पीएसजी से जुड़े मेसी

करार को लेकर पेरिस पहुंचे बार्सिलोना के पूर्व स्ट्राइकर लियोन मेसी

पेरिस, एपी : सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी एक तिहाई रकम में पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) की ओर से खेलते दिखाई देंगे। मेसी पीएसजी के साथ दो साल का करार करेंगे और वह इस करार से सहमत हैं। बार्सिलोना के पूर्व स्ट्राइकर मेसी करार को लेकर अन्य चीजों पर बात करने के लिए पेरिस पहुंच गए जहां उनका समर्थकों ने शानदार तरीके से स्वागत किया। वहीं, बार्सिलोना को छोड़ने के बाद मेसी के कैंप नाउ में जगह-जगह से पोस्टर उतारे गए।

साल 2017 में बार्सिलोना क्लब ने मेसी के साथ 550 मिलियन यूरो (करीब 48 अरब रुपये) का करार किया था, जो इस साल 30 जून को समाप्त हो गया। अब पीएसजी के साथ उनका करार दो साल का है जिसमें उन्हें प्रत्येक वर्ष लगभग 35 मिलियन यूरो (लगभग चार अरब रुपये) मिलेंगे। अब फिर से मेसी और नेमार की जोड़ी मैदान पर दिखेगी। यह जोड़ी पहले बार्सिलोना के लिए एक साथ खेलती थी। 34 वर्षीय मेसी के करार को लेकर पेरिस में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है जबकि

कैंप नाउ में मंगलवार को लियोन मेसी का पोस्टर उतारता एक कर्मचारी ● एएफपी

पेरिस पहुंचने के बाद प्रशंसकों का अभिवादन करते लियोन मेसी ● एपी

क्लब की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मेसी पेरिस में मेडिकल टेस्ट भी कराने आए हैं। बार्सिलोना का अनुबंध समाप्त होने के बाद मेसी फुटबाल इतिहास में किसी क्लब के लिए उपलब्ध होने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। पीएसजी के कोच मौरिसियो पोचेटिनो बार्सिलोना से अलग होने के बाद मेसी के संपर्क में थे।

ला लीगा 17 सत्र के बाद मेसी के बिना शुरू होगी : स्पेनिश लीग ला लीगा का 14 अगस्त से जब नया सत्र शुरू होगा तो पिछले 17 वर्षों में पहली बार मेसी इसका हिस्सा नहीं होंगे। मेसी ला लीगा में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। 2004 के बाद बार्सिलोना पहली बार मेसी के बिना खेलेगा क्योंकि वित्तीय संकट के कारण टीम अर्जेंटीना के खिलाड़ी से नया अनुबंध नहीं कर पाई। मेसी के पदार्पण से पहले दशक में बार्सिलोना की टीम सिर्फ दो बार लीग खिताब जीत पाई। 17 सत्र में बार्सिलोना की टीम 10 बार चैंपियन बनी। मेसी रिकार्ड आठ बार लीग में सर्वाधिक गोल करने का कारनामा किया।

कोहली व पुजारा की नजरें लाड्र्स में शतक लगाने पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर कभी लाड्र्स में टेस्ट सैकड़ा नहीं लगा पाए, लेकिन विराट कोहली इन दोनों दिग्गजों के इस क्लब में शामिल होने से बचना चाहेंगे और इस ऐतिहासिक मैदान पर तिहरे अंक में पहुंचकर शतक का लंबा इंतजार खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोहली पिछले नौ टेस्ट मैचों की 15 पारियों में शतक लगाने में असफल रहे हैं। उनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 27 शतक दर्ज हैं, लेकिन नवंबर 2019 के बाद से वह तिहरे अंक में पहुंचने के लिए तरस रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो 15 पारियां खेली हैं उनमें 345 रन बनाए हैं और उनका औसत 23.00 है।

अभ्यास के दौरान जमीन पर गिर पड़े विराट कोहली ● एएफपी

भारत को गुरुवार से दूसरे टेस्ट मैच में लाड्र्स के उस मैदान पर इंग्लैंड का सामना करना है जिसमें भारतीय दिग्गज रन बनाने के लिए जूझते रहे। गावस्कर ने इस मैदान पर 10 पारियों में 340 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं जबकि तेंदुलकर ने यहां जो नौ टेस्ट पारियां खेली हैं उनमें वह कभी 50 रन तक भी नहीं पहुंचे। कोहली ऐसे किसी रिकार्ड से बचना चाहेंगे। भारतीय कप्तान ने लाड्र्स में अब तक चार पारियां खेली हैं जिनमें उन्होंने 65 रन बनाए तथा उनका उच्चतम स्कोर 25 रन है। कोहली नाटिंघम में पहले टेस्ट मैच की एकमात्र पारी में पहली गेंद पर आउट हो गए थे और लाड्र्स में वह भारत को तीसरी जीत दिलाने के लिए बड़ा स्कोर बनाने को बेताब होंगे।

भारत के एक अन्य भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की कहानी भी कोहली जैसी ही है। पुजारा ने पिछली 32 पारियों से टेस्ट शतक नहीं लगाया है। इस बीच, उन्होंने 27.64 की औसत से 857 रन बनाए हैं। लाड्र्स में उन्होंने भी दो मैच खेले हैं जिनकी चार पारियों में वह केवल 89 रन बना पाए और उनका उच्चतम स्कोर 43 रन है। असल में भारत की वर्तमान टीम में अजिंक्य रहाणे को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज लाड्र्स में टेस्ट मैचों में शतक नहीं लगा पाया है।

मोईन की टीम में वापसी : इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट से पहले आलराउंडर मोईन अली को टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, स्पिन गेंदबाजी करने वाला यह आलराउंडर टीम के साथ अभ्यास करेगा। कप्तान जो रूट को छोड़कर इंग्लैंड का शीर्ष क्रम पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहा है।

ओलिंपिक में शामिल हो सकता है क्रिकेट

दुबई, प्रेट्र : आइसीसी ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह लास एंजिलिस में 2028 में होने वाले ओलिंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अपनी तरफ से दावा पेश करेगा।\ आइसीसी पिछले कुछ समय से क्रिकेट को ओलिंपिक में शामिल करने की कोशिश कर रहा है तथा उसके इस दावे को दुनिया के सबसे धनी बोर्ड बीसीसीआइ का भी समर्थन हासिल है। बीसीसीआइ के सचिव जय शाह ने हाल में इस पर अपनी राय स्पष्ट की थी। आइसीसी ने ओलिंपिक कार्य समूह भी गठित किया है जोकि क्रिकेट को 2028 से ओलिंपिक खेलों का हिस्सा बनाने की दिशा में काम करेगा। आइसीसी के चेयरमैन ग्रेग बारक्ले ने कहा, 'हम सब एक इस दावे को लेकर एकमत हैं और हम ओलिंपिक को क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखते हैं।'

पहले खुलें प्राथमिक स्कूल

स्कूल खोलने के लिए सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सभी स्कूल या कक्षाओं को एक साथ नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक स्कूल खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चे जितने छोटे होते हैं, कोरोना का प्रभाव उतना ही कम होता है। यही वजह है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना का असर बहुत कम देखा गया है। इसकी तुलना में 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर कोरोना का असर थोड़ा अधिक होता है। कोरोना की पहली लहर कमजोर होने पर कई जगह पर बड़े बच्चों के स्कूल खोले गए थे। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल के बाद माध्यमिक स्कूल और फिर हाईस्कूल व इंटर कालेज खोलना चाहिए।

स्कूल खोलने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को टीका लग जाए। जरूरी यह है कि स्कूल खुलने से पहले बच्चों के आसपास का पूरा परिवेश टीके की प्रतिरोधक क्षमता के कवच से लैस हो साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित हो कि वे संक्रमण फैलाने से पूरी तरह बचे रहें...

डा. नरेंद्र कुमार अरोड़ा

टीके का कवच स्कूल में देगा बच्चों को सुरक्षा

कोरोना को हराना है

वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के कारण पिछले करीब डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं। संचार की अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से आनलाइन पढ़ाई जारी है, लेकिन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह यह सुविधा एक समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी गरीब परिवार के बच्चों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे आनलाइन पढ़ाई कर सकें। इसलिए कोरोना ने बच्चों के बौद्धिक विकास पर भी आघात किया है। अब जल्द बच्चों का टीकाकरण शुरू करने की बात कही जा रही है। यह सही है कि टीका लगने पर बच्चे कोरोना से सुरक्षित होंगे, लेकिन टीकाकरण वैज्ञानिक साक्ष्यों व उपलब्ध संसाधन के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि बच्चों के माता-पिता, शिक्षक सहित सभी कर्मचारी टीका ले चुके होंगे तो ज्यादातर बच्चे कोरोना से सुरक्षित रहेंगे।

बहुत कम बच्चे हुए प्रभावित: कोरोना की पहली व दूसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव बहुत कम रहा। इस वजह से मृत्यु दर न के बराबर रही। देश में कोरोना से बीमार होने वालों में बच्चों की संख्या करीब 12 फीसद है। इसमें भी छोटे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरी लहर में डेल्टा वायरस का संक्रमण अधिक होने के बावजूद कोरोना से बीमार होने वालों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या महज 3.33 फीसद रही। वहीं 11 से 20 साल की उम्र के किशोरों व नवयुवकों की संख्या 8.35 फीसद रही है। दुनिया के अन्य देशों में भी बच्चों पर कोरोना का अधिक प्रभाव नहीं देखा गया है। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में तीसरी लहर में काफी संख्या में बच्चों के प्रभावित होने की बात सामने आई थी। यह तथ्य सही नहीं है। सिर्फ बच्चों के अस्पताल के डाटा के आधार पर गलत तथ्य दुनियाभर में फैला दिया गया। ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने से बचना होगा। बच्चों को कोरोना से अधिक खतरा नहीं है। ज्यादातर बच्चों में कोरोना का असर बहुत हल्का होता है। इसलिए अभी बच्चों को टीका लगाने का सही समय नहीं है।

मिलकर तैयार करना होगा स्कूल खोलने का कार्यक्रम: यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना ज्यादा घातक है। इसलिए पहले 18 साल से अधिक उम्र के वयस्क लोगों को टीका लगाना ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे पास इतने टीके उपलब्ध नहीं हैं कि बच्चों को टीका देना शुरू कर दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो बच्चे तो बच जाएंगे, लेकिन यदि तीसरी लहर आई तो बहुत से बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी बड़ी आबादी टीके से वंचित है। दूसरी लहर में बहुत से बच्चों ने यह दर्द झेला है और परिवार के लोगों को खोते हुए देखा है। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। इसलिए स्कूल जल्द खोलने के लिए बच्चों के टीकाकरण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी लहर के बाद बच्चों के मन में कोरोना को लेकर खौफ हो सकता है। इसका निवारण भी जरूरी है। इसलिए डाक्टर, महामारी विद, शिक्षाविद, शिक्षक व अभिभावक संघ से सलाह लेकर राज्य सरकारों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

बच्चों से फैल सकता है संक्रमण: बच्चे कोरोना के संक्रमण से भले ही बीमार नहीं होते, लेकिन वे संक्रमण फैला सकते हैं। सीरो सर्वे में भी यह बात सामने आ चुकी है कि करीब वयस्क लोगों के बराबर ही बच्चे एंटीबाडी पाजिटिव हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों में संक्रमण तो होता है, लेकिन ज्यादातर को बीमारी नहीं होती। ऐसे में बच्चों से दूसरे लोगों में संक्रमण फैल सकता है। इसलिए स्कूल खोलने से पहले सभी शिक्षक, आया, बस व कैब चालक सहित सौ फीसद कर्मचारियों को टीका लग जाना चाहिए ताकि बच्चों से दूसरे लोगों में संक्रमण न फैलने पाए, क्योंकि स्कूलों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन आसान नहीं होगा साथ ही बच्चों को आपस में मिलने से रोकना चुनौतीपूर्ण होगा। यदि स्कूल के सभी कर्मचारियों व बच्चों के परिवार में सभी को टीका लगा रहेगा तो बच्चे यदि आपस में मिलेंगे तब भी संक्रमण खास नहीं फैल पाएगा।

कक्षा में शारीरिक दूरी के साथ बैठने का नियम हो: कक्षा में एक डेस्क पर दो या डेस्क छोटी हो तो एक बच्चे के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है साथ ही कोरोना से बचाव के नियमों का अधिक से अधिक पालन होना चाहिए। छुट्टी होने के बाद भीड़ नियंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अगले साल के आरंभ से बच्चों का टीकाकरण: देश में अभी तक करीब 50 करोड़ 68 लाख डोज टीका लगा है। इसके तहत करीब 39.53 लाख लोगों को टीके की पहली डोज व 11.15 लाख लोगों को दोनों डोज लग सकी हैं। अभी टीके की उपलब्धता बढ़ी है। अगले तीन माह में तीन नए टीके और आ जाएंगे। मौजूदा समय में जिस गति से टीकाकरण हो रहा है उससे दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के करीब सभी लोगों को टीका लग जाएगा। देश में करीब 40 करोड़ बच्चे हैं। अगले साल के आरंभ से बच्चों को भी कोरोना का टीका लगने लगेगा। दो से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जायडस कैडिला द्वारा विकसित टीके के ट्रायल में भी 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। कोवैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर 77.8 फीसद असरदार है। यह बच्चों पर कितना प्रभावी होगा यह ट्रायल का परिणाम सामने आने के बाद पता चलेगा। उम्मीद है कि बच्चों पर भी यह टीका कारगर होगा।

(चिकित्सक कोरोना पर गठित एनटागी (नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप आन इम्यूनाइजेशन) की कार्य समिति के चेयरमैन हैं)

प्रस्तुति: रणविजय सिंह

माइग्रेन के बारे में जरूरी है जागरूकता

डा. तुषार राउत, कंसलटेंट न्यूरोलाजिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हास्पिटल, मुंबई

असहनीय होता है माइग्रेन का दर्द और इसका स्थायी उपचार भी नहीं है, लेकिन जीवनशैली में बदलाव लाकर इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है...

माइग्रेन में बहुत तेज दर्द होता है और इसके साथ कई बार मिचली, उल्टी और प्रकाश की सेंसिटिविटी भी होती है। यह कई घंटों से लेकर तीन दिन तक रह सकता है। माइग्रेन युवाओं से लेकर अधेड़ उम्र वालों में सामान्य है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह ज्यादा देखने को मिलता है। यह वंशानुगत होने के साथ-साथ जीवनशैली कारकों के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। सामान्य तौर पर यह सिर के आधे हिस्से को प्रभावित करता है, जिसके चलते इसे आधासीसी या अधकपारी भी कहा जाता है, लेकिन यह अक्सर पूरे सिर को भी प्रभावित कर सकता है।

माइग्रेन व अन्य सिरदर्द में अंतर: माइग्रेन का सिरदर्द गंभीर प्राथमिक सिरदर्द होता है जो आमतौर पर एक खास समय की अवधि में होता है, जबकि अन्य सिरदर्द विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, जैसे मेनिन्जाइटिस, ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज। वे कुछ न्यूरोलाजिकल समस्याओं जैसे दृश्य हानि, स्मृतिलोप, असंतुलन या अंगों की कमजोरी के साथ तीव्र या पुराने हो सकते हैं। इसके अन्य कारणों का पता लगाने के लिए ब्रेन स्कैन जैसी जांच की आवश्यकता होती है।

उपचार: माइग्रेन का समय पर इलाज न किए जाने पर यह गंभीर समस्या बन जाता है। इसलिए यदि समय से न्यूरोलाजिस्ट को दिखाया जाए और इसका मूल्यांकन किया जाता रहे एवं उपयुक्त दवाओं का सेवन किया जाए तो लक्षणों की गंभीरता को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अब ऐसी प्रभावी और सुरक्षित दवाएं उपलब्ध हैं जो शुरुआत में ही माइग्रेन के दर्द को रोक सकती हैं। इसके अलावा दर्द की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए तीन से छह महीने की अवधि में विभिन्न प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, जिसे माइग्रेन प्रोफायलैक्सिस कहा जाता है। एपिसोडिक और क्रोनिक माइग्रेन के इलाज के लिए विशिष्ट दवाओं का उपयोग किया जाता है। माइग्रेन के उपचार में भी नई प्रगति हुई है, जैसे कि सिर की त्वचा के विभिन्न बिंदुओं पर इंजेक्शन का उपयोग माइग्रेन की आवृत्ति को कम करने में मदद करता है।

माइग्रेन का कोई स्थायी इलाज नहीं है और यह आमतौर पर एक निश्चित उम्र के बाद अपने आप दूर भी हो जाता है। माइग्रेन से परेशान लोग स्वयं से तरह-तरह की दर्द निवारक दवाओं का सेवन करते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। कारण, दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन किडनी समेत शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। इसलिए चिकित्सकों द्वारा माइग्रेन के लिए बार-बार दर्द निवारक दवाएं लेने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे समय के साथ सिरदर्द की हालत बिगड़ सकती है। माइग्रेन के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जीवनशैली में बदलाव। माइग्रेन मुक्त जीवन जीने के लिए नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, वजन नियंत्रित रखना, प्रतिदिन समय पर भोजन, प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर नींद लेना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और इंटरनेट मीडिया से ब्रेक लेना फायदेमंद रहता है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच व खुश रहना भी अनिवार्य है।

कारक

माइग्रेन से पीड़ित लोगों में इसके कारकों के बीच अंतर हो सकता है और इसमें पर्यावरणीय परिवर्तन से लेकर विशिष्ट खाद्य पदार्थों व अन्य चीजों के अलावा कुछ भी शामिल हो सकता है। उपवास, गर्मी, तेज धूप और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नट्स, चाकलेट, पनीर और प्रोसेस्ड फूड्स आदि सामान्य कारक हैं। नींद की गड़बड़ी और महिलाओं में मासिक धर्म चक्र की गड़बड़ी से भी माइग्रेन हो सकता है।

डा. अरुण प्रसाद
बैरियाट्रिक सर्जन
अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली

कई समस्याओं से बचाएगी बैरियाट्रिक सर्जरी

गतिहीन जीवनशैली ने कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दी हैं। इनमें मोटापा प्रमुख है। अत्यधिक समस्या होने पर विशेषज्ञ देते हैं वजन कम करने वाली बैरियाट्रिक सर्जरी कराने की सलाह...

बीते करीब डेढ़ साल से वर्क फ्राम होम के बढ़ते चलन व बाहर आने-जाने में आई कमी के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है व्यक्तियों का वजन। भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने सभी भारतीय राज्यों में मोटापे में वृद्धि दर्ज की है। बढ़ते वजन के साथ पहले से ही परेशान लोग लाकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद हुए जिम आदि से वजन बढ़ने की समस्या से भी घिर गए हैं। ऐसे में अब बहुत ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज करके वजन कम करने का फैसला लेने का प्रभाव जोड़ों और रीढ़ में दर्द के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में डाक्टर बैरियाट्रिक सर्जरी कराने की सलाह देते हैं।

दुनियाभर के हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि यदि मरीज में गंभीर समस्या के संकेत दिखें और सर्जरी बहुत जरूरी हो जाए तो वजन कम करने वाली बैरियाट्रिक सर्जरी कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। सर्जरी में देरी करने से वजन बढ़ने और इससे संबंधित बीमारियों से हालत बिगड़ने से जीवन की गुणवत्ता खराब होती है और रिकवरी दर भी धीमी हो जाती है। मोटापे के मामले में वृद्धि मुख्य रूप से इसलिए हुई है, क्योंकि लोगों की जीवनशैली और खानपान का पैटर्न बदला है। इससे उनके शरीर में मेटाबालिज्म और इंसुलिन रजिस्टेंस में गड़बड़ी पैदा हो रही है। चूंकि सरकार ने अब वैकल्पिक सर्जरी पर से लगी रोक हटा दी है। इसलिए बैरियाट्रिक सर्जरी कराने का यह उपयुक्त समय है।

बैरियाट्रिक सर्जरी की प्रक्रिया: अगर किसी का बीएमआई 32.5 है और उसमें टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप एप्निया या हाई ब्लडप्रेशर की समस्या है तो वह बैरियाट्रिक सर्जरी करा सकता है। बीएमआई और मरीज की जरूरतों के आधार पर, एंडोस्कोपिक /लेप्रोस्कोपिक / रोबोटिक सर्जरी आफर की जाती है। जब थोड़ा वजन कम करने की बात आती है तो एंडोस्कोपिक सर्जरी को प्राथमिकता दी जाती है और अगर केस गंभीर हुआ तो रोबोटिक सर्जरी की जाती है।

इस क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी एक नई तकनीक है। इस तरह की सर्जरी में सर्जन एक मास्टर कंसोल के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। पारंपरिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में इस प्रक्रिया के कई लाभ हैं, क्योंकि इसकी 3डी विजन और सटीक सहज ज्ञान युक्त मल्टी रेंज उपकरण मरीजों को ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। पोस्ट आपरेटिव दर्द और रिकवरी समय भी इसमें कम लगता है। बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद पोषक तत्वों की कमी की समस्या हो सकती है। हालांकि हास्पिटल की टीम के साथ संपर्क में रहने और डाइट स्पेशलिस्ट द्वारा सुझाए गए डाइट प्लान से पोषक तत्वों की कमी संबंधित समस्या को दूर किया जा सकता है।

मिल गए नए विकल्प

यह सर्जरी तब की जाती है जब वजन कम करने में एक्सरसाइज और डाइट काम नहीं आती हैं या जब किसी को वजन के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो इस तरह की सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। रोबोटिक सर्जरी और एंडोस्कोपिक बैरियाट्रिक इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे नई तकनीक ने हमें मोटापे की समस्या से निपटने में ढेरों विकल्प दिए हैं। इसके अलावा अब बेहतर स्टेपलिंग और टांके लगाने के उपकरण भी आ गए हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं कि जिन लोगों ने कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले बैरियाट्रिक सर्जरी कराने का फैसला किया था, उन्हें स्वास्थ्य पर किसी और प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए इसे बाद में करवाने के बजाय जल्द से जल्द करवाने पर विचार करना चाहिए।

बदलते मौसम में बीमार न हो जाएं बच्चे

चाइल्ड केयर

डा. सुमित गुप्ता
बालरोग विशेषज्ञ,
गाजियाबाद

उमस भरी गर्मी के साथ बारिश का मौसम है। ऐसे में एहतियात बरतेंगे तो बच्चों को कोरोना के अलावा सुरक्षित रख सकेंगे इस मौसम के अन्य संक्रमणों से ...

कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ, नियंत्रण में जरूर है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी आशंका जता रहे हैं। इसके साथ ही मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तेज गर्मी और उमस के साथ बारिश भी हो रही है। ऐसे में शिशुओं, बच्चों व किशोरों में कोरोना संक्रमण के साथ ही निमोनिया और एलर्जी का खतरा भी मंडरा रहा है। डायरिया और कालरा की बीमारी भी इसी मौसम में बच्चों को संक्रमित करती है। फिलहाल हर उम्र के लोगों में इस तरह के संक्रमण का खतरा अभी कम होने की संभावना है, क्योंकि बीते दिनों हमने स्वच्छता, पौष्टिक आहार और संक्रमण से बचाव के लिए बहुत कुछ सीखा और अपनाया है। फिर भी सुरक्षा ही हर तरह के संक्रमण का एकमात्र बचाव है।

इन दिनों शिशुओं व बच्चों में निमोनिया का खतरा अधिक रहता है। कुछ बच्चों में आनुवांशिक कारणों या वायरसजनित संक्रमण की समस्या हो जाती है। अगर आप कोरोना संक्रमण से बचने के सारे उपाय आजमा रहे हैं तो खुद के साथ ही बच्चों को भी इस मौसम की बीमारियों से सुरक्षित रखने में सफल रहेंगे।

निमोनिया से संक्रमित बच्चों को जुकाम, बुखार, खांसी और शरीर में आक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। कई बार समय से उपचार न मिलने पर बच्चा बेहोश भी हो सकता है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में तेज सांस व खांसी के कारण फेफड़ों में सूजन व इनमें पस पड़ने की समस्या हो सकती है। खांसी, जुकाम व बुखार के कारण बच्चे कुछ भी खाना बंद कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें जो पसंद हों वे चीजें खाने को दें। निमोनिया से संक्रमित बच्चे को यदि समय रहते उपचार मिल गया तो अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन संक्रमण बढ़ जाने पर ऐसा जरूरी हो जाता है।

ये जरूर करें

- बच्चों को बाहर का खाना देने से बचें।
- घर के बने पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें।
- बारिश में न भीगने दें। भीगने पर बच्चों के कपड़े बदल दें और कुछ समय के लिए एसी व पंखे से दूर रखें।
- किसी तरह का संक्रमण होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।

देश के लिए 18 साल की उम्र में शहीद हो गए थे खुदीराम बोस

1908 में आज ही 18 साल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी थी। उन्हें 30 अप्रैल, 1908 को जज की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी फांसी के विरोध में लोगों ने कई दिनों तक स्कूल-कालेज बंद रखे थे।

भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ दादर एवं नगर हवेली

1961 में आज ही दादर एवं नगर हवेली भारत का हिस्सा बना। दो अगस्त, 1954 को पुर्तगाली शासकों से आजादी के बाद 1961 तक वहां जनता ने ही शासन चलाया था। 2020 में दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

श्रुति वीणा के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं पंडित लालमणि मिश्र

संगीत की 22 श्रुतियों को वीणा पर प्रस्तुत कर श्रुति वीणा का आविष्कार करने वाले पंडित लालमणि मिश्र का जन्म 1924 में आज ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। सात वर्ष की उम्र में हारमोनियम पर 15 अलंकारों की प्रस्तुति दी थी। फिल्मों में संगीत दिया। वैदिक संगीत पर शोध करते हुए सामिक स्वर का रहस्य सुलझाया। 1958 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर का पद स्वीकारा और 20 साल तक गायन-वादन की नई-नई विधाएं रचीं। 1979 में वाराणसी में निधन हो गया।

थोड़े में भी मिलती है ज्यादा खुशी

हाल में खेलों का महाकुंभ ओलिंपिक संपन्न हुआ है। अलग-अलग प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार पदक पाते समय कांस्य विजेता के चेहरे पर रजत पाने वाले से ज्यादा खुशी होती है। अक्सर हम इसे अपने मन का वहम मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि वास्तव में कांस्य पाने वाला ज्यादा खुश होता है। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण जिम्मेदार होते हैं।

कम भी लगता है ज्यादा

1995 में न्यूयार्क की कार्नेल यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञानी विक्टोरिया मेडवेक व थामस गिलोविच और यूनिवर्सिटी आफ टोलेडो के स्काट एफ मेडे ने पदक विजेताओं की मनोदशा पर रिसर्च पेपर छापा था। उन्होंने एक हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर यह दिखाया कि पदक जीतने के तुरंत बाद भी और आगे के जीवन में भी कांस्य पदक विजेता रजत जीतने वालों से ज्यादा खुश रहते हैं। कांस्य विजेता के मन में बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए कुछ हासिल कर लेने की खुशी होती है, जबकि रजत विजेता के मन में कुछ बहुत बड़ा चूक जाने का दुख रहता है।

बस जरा सी चूक से बड़ा सपना टूट जाने का दर्द चुभता है

शोधकर्ताओं ने पाया कि रजत विजेता के मन में कई तरह के भाव चल रहे होते हैं। यह बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है कि बस जरा सा अतिरिक्त प्रयास उसे स्वर्ण दिला सकता था। उसे स्वर्ण और रजत के बीच का वह फर्क महसूस हो रहा होता है, जिसका सामना उसे निजी और सामाजिक स्तर पर पूरी उम्र करना पड़ सकता है। 1912 के स्टाकहोम ओलिंपिक में रजत जीतने वाले मिड डिस्टेंस अमेरिकन रनर ऐबेल किविएट ने 71 साल बाद एक साक्षात्कार में रजत पदक जीतने के उस पल को जीवन का सबसे बुरा सपना कहा था। ग्रेट ब्रिटेन के अर्नाल्ड जैकसन 0.1 सेकेंड के अंतर से स्वर्ण जीते थे। उस पल को याद करते हुए किविएट ने कहा था, 'मेरे लिए बहुत निराशाजनक दिन था। अक्सर रातों को मेरी नींद टूट जाती है और मैं सोचने लगता हूं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था?'

इस तरह किया गया अध्ययन

अध्ययन के पहले चरण में नतीजों के तुरंत बाद 41 एथलीटों के चेहरे के भाव कुछ छात्रों को दिखाए गए। उन छात्रों को यह ज्ञात नहीं था कि किस एथलीट ने क्या जीता है। छात्रों से हर चेहरे के भाव के आधार पर यह आंकने को कहा गया कि कौन कितना खुश या दुखी दिख रहा है। इस आधार पर उन्हें एक से 10 तक अंक देने को कहा गया था। पदक जीतने के तुरंत बाद रजत विजेताओं के चेहरे के भाव के आधार उन्हें औसतन 4.8 अंक मिला। वहीं, कांस्य विजेता इस मामले में खुशी के पैमाने पर 7.1 तक पहुंच गए। मेडल स्टैंड पर पदक पाते समय भी कांस्य विजेताओं की खुशी 5.7 और रजत विजेताओं की खुशी 4.3 पाई गई।

बचा रह जाता है दुख

पदक जीतने के बाद टेलीविजन पर दिए गए साक्षात्कार के अध्ययन में भी लगभग ऐसा ही नतीजा मिला। शोधकर्ताओं ने 22 पदक विजेताओं के साक्षात्कार के वीडियो का अध्ययन किया था। इसमें भी कांस्य विजेताओं की औसत खुशी 5.7 अंक तक रही, जबकि रजत वालों की खुशी 4.4 रही। 'काश थोड़ा और...' की भावना रजत विजेताओं के मन में हमेशा बनी रह जाती है।

जागरण रिसर्च

इधर-उधर की

घर की सीलिंग में छिपा बैठा था विशाल अजगर

इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में अजगर सीलिंग तोड़कर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेट मीडिया

फ्लोरिडा, एजेंसी : दीवार पर अचानक बड़ी छिपकली भी दिख जाए तो सिहरन हो जाती है। ऐसे में यह बात रोंगटे खड़ी करने वाली है कि घर की सीलिंग में कई फीट लंबा अजगर बैठा था। हाल में इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें सीलिंग में छिपे बैठे अजगर को पकड़ते देखा जा सकता है। पकड़ने आए रेस्क्यू टीम के सदस्य पर अजगर हमला करने की कोशिश भी करता है। वायरलहाग नामक यूट्यूब यूजर ने इस घटना के वीडियो को साझा किया है। मिस्ट्री गेस्ट नामक यूजर ने इस घटना को साउथ फ्लोरिडा का बताया है।

चोट से उबारने को खास पट्टी की तैयार

आविष्कार ▸ आइआइटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की पारदर्शी फिल्म

किफायती होने के साथ-साथ प्रकृति के लिए भी हानिकारक नहीं है यह पट्टी

नई दिल्ली, प्रेट्र : चोट से उबारने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, शोधकर्ताओं ने एक ऐसी पारदर्शी फिल्म (पट्टी) का आविष्कार किया है जो बायोडिग्रेडेबल होने के साथ किफायती भी है।

इसका आविष्कार करने वाले दल के अनुसार, सिंथेटिक पालीमर के एकीकरण पर आधारित इसका मैटेरियल प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। साथ ही यह मैटेरियल एक नम वातावरण बनाता है, जो शरीर के एंजाइमों के माध्यम से चोट को अपने आप ठीक करने में सक्षम है। प्रयोगशाला स्तर पर इसे तैयार करने की कीमत वर्तमान में मौजूद पट्टियों की तुलना में 50 फीसद कम है। इस आविष्कार से संबंधित निष्कर्षों को इंटरनेशनल जर्नल आफ बायोलाजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स में प्रकाशित किया गया है।

आइआइटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई पारदर्शी फिल्म, जो चोट से उबारने का काम करेगी। सौ. इंटरनेट मीडिया

आइआइटी गुवाहाटी में पीएचडी स्कालर अरित्रा दास के मुताबिक, सामान्य तौर पर सूती ऊन, लिंट और गाज (जालीदार पट्टी) का प्रयोग चोट को ठीक करने वाली सामग्री में किया जाता है। इन्हें घाव के रिसाव को रोकने और उपचार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

हालांकि, ऐसी सामग्रियों का एक बड़ा नुकसान यह होता है कि ये सही टिशू (ऊतक) को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के चलते शोधकर्ताओं ने एक बेहतर विकल्प की तलाश की दिशा में काम किया।

इस तरह किया तैयार : दास के मुताबिक, यह आविष्कार इस क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। हमने इसे तैयार करने के लिए एक सिंथेटिक पालीमर, जिसका नाम पालीविनाइल अल्कोहल (पीवीए) है का नेचुरल पालीमर स्टार्च (एसटी) के साथ एकीकरण पर जोर दिया, जिससे किफायती, बायोडिग्रेडेबल, गैर-विषाक्त और पारदर्शी मिश्रित हाइड्रोजेल तैयार हो सका। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस उत्पाद में हाइड्रोलाइटिक वातावरण के तहत सूजन हो जाने के बाद भी चोट में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने की क्षमता है।

स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों का करता है विकास : आइआइटी, गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर चंदन दास के मुताबिक, यह नया मैटेरियल घायल कोशिकाओं के सुधार के लिए उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के अलावा, स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों के विकास में भी मदद करता है।

और अध्ययन की जरूरत

शोधकर्ताओं ने बताया कि इसे प्रयोगशाला में तहत तैयार किया गया है। इसके शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं। हालांकि, अभी इस पर और कार्य करने की जरूरत है।

कई तरह से लाभकारी साबित होगी यह फिल्म

शोधकर्ताओं के मुताबिक, लैब में तैयार की गई यह फिल्म कई तरह से लाभकारी साबित हो सकती है। पहला तो यह कि इसे तैयार मैलिक एसिड का प्रयोग किया गया है, न कि साइट्रिक एसिड का। इससे घाव तो जल्द ठीक होंगे ही साथ ही इसे तैयार करने में लागत भी कम आएगी।

बच्चों में शारीरिक श्रम से दूर हो सकती है मोटापे की समस्याएं

4,661 बच्चों पर अध्ययन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

बचपन से ही जो बच्चे डिजिटल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें किशोरावस्था तक आते-आते मोटापे की समस्या होने लगती है। बाद में मोटापे से जुड़ी कई दिक्कतों का ऐसे बच्चों को सामना करना पड़ता है। एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर डिजिटल मीडिया पर अधिक समय बिताने से उत्पन्न खतरों को कम किया जा सकता है। इस अध्ययन के परिणाम जर्नल आफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं। इस अध्ययन से पता चला है कि जो बच्चे डिजिटल मीडिया का बहुत उपयोग करते हैं और वे 11 साल की उम्र से सप्ताह में छह घंटे भी शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं तो 14 साल की उम्र तक उनमें मोटापा होने के खतरे कम हो जाते हैं। वर्तमान में बच्चों में मोटापा संबंधी स्वास्थ्य समस्या विश्व स्तर पर तेजी से एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी आफ हेलसिंकी व फोखलसन रिसर्च सेंटर ने व्यापक अध्ययन किया है। अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गई कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों में डिजिटल मीडिया के अधिक उपयोग और किशोरावस्था में मोटापे के बीच क्या कोई संबंध है।

अध्ययन में 4,661 बच्चों को शामिल किया गया। इन सभी बच्चों के डिजिटल मीडिया के उपयोग और उनके शारीरिक गतिविधियों को करने के संबंध में पूरा डाटा तैयार कर उसका अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि जो बच्चे सप्ताह में छह घंटे शारीरिक गतिविधियां यानी एक्सरसाइज या फिर खेलकूद में भाग लेते हैं, उनमें मोटापे की समस्या का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

मुश्किलों से बाहर आना है तो काम करते रहें : शिखा

वीरे दी वेडिंग फिल्म की शिखा तलसानिया ने किया मराठी वेब सीरीज में डेब्यू।

वीरे दी वेडिंग और वेक अप सिड जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकीं अभिनेत्री शिखा तलसानिया ने अब मराठी वेब सीरीज में भी डेब्यू कर लिया है। वह शांतित क्रांति नाम की वेब सीरीज में नजर आएंगी। दैनिक जागरण से बातचीत में शिखा ने कहा कि मराठी कंटेंट मैं खुद देखती हूं। मुंबई में पली-बढ़ी हूं तो 10 साल स्कूल में मराठी पढ़ी है। इसलिए इस भाषा को समझने में दिक्कत नहीं है। हमारे शो के लेखक ही मेरे मराठी कोच थे। रोज शूटिंग शुरू होने से एक-दो घंटे पहले हम मराठी स्क्रिप्ट साथ पढ़ते थे। शो का नाम समझाते हुए शिखा कहती हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रांति ही होती रहती है। जिंदगी में जो क्रांति चल रही है, उसमें शांति कैसे ढूंढें, इसी के बारे में शो है। मुझे भी जीवन में शांति ढूंढने के लिए अलग-अलग चीजें ट्राई करते रहना पड़ता है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में होती हैं। काम करते रहना ही इससे बाहर निकलने का तरीका है। शांतित क्रांति शो सोनी लिव पर 13 अगस्त से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा शिखा जहां चार यार फिल्म की शूटिंग भी कुछ ही दिनों में शुरू करने वाली हैं। वीरे दी वेडिंग फिल्म की सीक्वल को लेकर शिखा ने कहा कि हम तो तैयार हैं। बस रिया (फिल्म वीरे दी वेडिंग की निर्माता रिया कपूर) के फोन का इंतजार है।

'हमने सिर्फ चार दिनों में पूरी की अपनी शार्ट फिल्म की शूटिंग'

कोरोना काल ने फिल्मकारों को सावधानी बरतते हुए सुनियोजित तरीके से तेज काम करना सिखा दिया है। तभी तो महीनों चलने वाली फिल्मों की शूटिंग अब चंद दिनों में खत्म हो जाती है। फुकरे और प्रस्थानम जैसी फिल्मों के अभिनेता अली फजल ने अपनी अनाम शार्ट फिल्म की शूटिंग सिर्फ चार दिनों में पूरी कर ली। आरती कादव द्वारा लिखित और निर्देशित इस शार्ट फिल्म का नाम अभी नहीं तय है। जल्द ही निर्माता इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। साइंस फिक्शन फिल्में बनाने के लिए जानी जाने वाली आरती ने इससे पहले शार्ट फिल्म 55 किमी/सेकेंड का निर्देशन किया था, जिसमें उन्होंने अली की गर्लफ्रेंड रिचा के साथ काम किया था।

अनाम शार्ट फिल्म में काम कर रहे हैं अली।

इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में अली ने बताया, 'आरती के साथ इस शार्ट फिल्म में काम करना वास्तव में एक शानदार अनुभव रहा। शूटिंग के दौरान हमने काफी मजे किए। हमने पूरी शार्ट फिल्म महज चार दिनों में मुंबई में शूट कर ली। काश कि मैं इस फिल्म के बारे में आप लोगों को और ज्यादा बता पाता, लेकिन निर्माताओं की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा के बाद ही ज्यादा बातें हो पाएंगी।' अली फिलहाल रिचा के साथ मिलकर अपने प्रोडक्शन के अंतर्गत बन रही फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल पर काम कर रहे हैं।

एजाज के पापा ने कहा था, अजीब है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हैं : पवित्रा

रियलिटी शो बिग बास 14 के घर से एजाज खान और पवित्रा पुनिया के प्यार के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। पवित्रा एजाज के परिवार में घुलमिल भी चुकी हैं। दोनों ने एक लाइव चैट के दौरान इस बारे में बात की। पवित्रा ने कहा कि एजाज के पिता बहुत ही कूल और सुलझे हुए इंसान हैं। एजाज मुझे कई बार चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे दोस्त कम हैं, तुम बाहर पार्टी के लिए नहीं जाती हो। जब मैं एजाज के पापा से मिली तो मैंने बात शुरू करने के लिए एजाज की यह बात उनको बताई। मुझे लगा वह एजाज को डाटेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा यह तो अजीब है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तुम्हें बाहर जाना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। उनकी बातें सच में बहुत अच्छी लगीं। पवित्रा ने आगे बताया कि एजाज यूं तो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें खाना मिलने में थोड़ी भी देर हो जाए तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वहीं, एजाज ने बताया कि लाकडाउन के दौरान हमें एक-दूसरे को जानने का मौका मिला। बहुत सारा वक्त साथ बिताया है। रिश्ता कैसे निभाते हैं, मैंने वह सीख लिया है। जब मैं पहले दूसरे रिश्ते में था, तब भी बैचलर की ही तरह रहा हूं। काम के लिए अक्सर घर से बाहर ही रहता था। यह पहली बार है जब किसी को नजदीक से जाना है। पवित्रा से शादी को लेकर एजाज दैनिक जागरण से हुई बातचीत में कह चुके हैं कि जब वह शादी करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। फिलहाल उनके चेहरे पर खुशी की वजह पवित्रा ही हैं।

बिग बास 14 में एक-दूसरे के करीब आए थे एजाज और पवित्रा।

करीना कपूर के पहले बेटे का तैमूर नाम रखने पर भी लोगों ने खूब सवाल उठाए थे।

दूसरे बेटे के नाम को लेकर ट्रोल हुईं करीना

करीना ने कहा बेटे का नाम जेह अली खान ● इंस्टाग्राम

अपने बच्चे का नाम रखना माता-पिता का अधिकार होता है, लेकिन जब माता-पिता सेलिब्रिटी हों, तो फिर उन्हें बच्चों के नाम भी सोच-समझकर रखने पड़ते हैं। मंगलवार को फिल्म लाल सिंह चड्ढा की अभिनेत्री करीना कपूर खान को उनके दूसरे बेटे के नाम को लेकर ट्विटर पर ट्रोल कर दिया गया। ट्रोल्स के मुताबिक करीना ने अपनी किताब करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबिल में अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर बताया है। हालांकि इस किताब को करीना ने जब करण जौहर के साथ इंस्टाग्राम पर लांच किया, तब उन्होंने अपने बेटे का नाम जेह अली खान बताया। करण ने लाइव चैट के दौरान करीना से पूछा कि क्या अब आप अपने दूसरे बच्चे के नाम के बारे में सबको बता सकती हैं, इस पर करीना ने कहा कि उनके दूसरे बेटे का नाम जेह अली खान है। हालांकि बताया जा रहा है कि करीना की इस किताब के आखिरी पन्ने पर उनके बेटे की तस्वीर के साथ नाम जहांगीर लिखा गया है। एक यूजर ने लिखा कि लगता है करीना और सैफ अली खान मुगल शासकों की टीम बना रहे हैं। पहले तैमूर और अब जहांगीर। इससे पहले जब उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम तैमूर अली खान रखा था, तब भी लोगों ने उस नाम पर सवाल उठाया था। उल्लेखनीय है कि मुगल बादशाह अकबर के बेटे सलीम का ही नाम जहांगीर था। जहांगीर का अर्थ दुनिया को जीतने वाला बताया जाता है।

आडिशन से डार्लिंग्स मिली : रोशन

दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा के कलाकार एक-दूसरे की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री का काम करने का अपना तरीका होता है। मलयालम फिल्म के अभिनेता रोशन मैथ्यू भी हिंदी सिनेमा में कदम रख चुके हैं। नेटफ्लिक्स की चोक्ड फिल्म में नजर आ चुके रोशन अब शाह रुख खान और आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म डार्लिंग्स की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में रोशन ने बताया कि डार्लिंग्स बड़े स्केल वाली फिल्म है। मुझे इस फिल्म में काम आडिशन के जरिये मिला था। मैं मुंबई में साल 2014 से लेकर 2017 तक रहा हूं। उस दौरान आडिशन दिया करता था। डार्लिंग्स फिल्म के सेट पर शाह रुख खान से मिलने का इंतजार था। वह एक बार सेट पर आए थे। उनसे पहली बार वहीं मुलाकात हुई थी। मैं उनको देखकर बहुत प्रभावित था, कुछ बोल ही नहीं पाया और जो थोड़ा-बहुत बोला, उसका कोई मतलब ही नहीं था। उनसे मिलना जादुई अनुभव था। शूटिंग से जब घर लौट रहा था, तो यकीन नहीं हो रहा था कि शाह रुख खान से मिला हूं। बड़े बैनर की फिल्म करने को लेकर रोशन कहते हैं कि बड़े बैनर की फिल्मों की पहुंच बड़ी होती है, लेकिन सिर्फ वह मानदंड फिल्मों को चुनने के लिए नहीं हो सकता है। फिल्म अच्छे किरदार देखकर चुनी जाती है। रोशन अभिनीत मलयालम फिल्म कुरुथी आज (11 अगस्त) अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

शाह रुख को देखना जादुई अनुभव मानते हैं रोशन ● पीआर टीम

सोनू निगम ने मदद की : साहिल

अभिनेता, यूट्यूबर और एंकर साहिल खट्टर आगामी फिल्म 200 हल्ला हो में माफिया अक्कू यादव से प्रेरित किरदार में नजर आएंगे। हत्या और बलात्कार समेत कई संगीन अपराधों के आरोपी भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव को साल 2004 में नागपुर की जिला अदालत में करीब 200 महिलाओं ने पीट-पीटकर मार डाला था। साहिल के इस किरदार की तैयारी में गायक सोनू निगम की भी अहम भूमिका रही। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में साहिल बताते हैं, 'इस किरदार की तैयारी मैंने तीन चरणों में की। पहली शारीरिक, दूसरी मानसिक और तीसरी भाषा शैली। पिछले साल लाकडाउन के दौरान मेरी काफी तोंद निकल गई थी, जबकि इस किरदार के लिए मुझे पतला शरीर चाहिए था। यह बदलाव करना मेरे लिए बिना सोनू निगम जी मदद के संभव नहीं था। उन्होंने मेरे लिए अपना मुंबई का पर्सनल जिम खोल दिया था। मैं अपने ट्रेनर के साथ रोज उनके जिम में खूब पसीना बहाता था। इसके अलावा मैंने डाइट पर भी पूरा ध्यान दिया। किरदार की मानसिक तैयारी के लिए जितनी भी सीरियल किलर पर बनी फिल्में और डाक्यूमेंट्रीज बनी हैं, मैंने उन सब को देख लिया था। उसके साथ-साथ मैंने कई किताबें पढ़ीं। भाषाशैली पर काम करने के लिए मैंने लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ली।' साहिल के अलावा अमोल पालेकर, बरुण सोबती अभिनीत यह फिल्म 20 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।

फिल्म 200 हल्ला हो में अक्कू से प्रेरित किरदार में हैं साहिल ● इंस्टाग्राम

खुद किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद नई प्रतिभाओं को मौका दें : प्रिंस

किसी प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंच जाने के बाद कला और प्रतिभा के विकास के लिए नए और युवा कलाकारों को भी मंच मुहैया कराना जरूरी होता है। लाल इश्क और नागिन जैसे धारावाहिकों और रियलिटी शो रोडीज कर चुके अभिनेता और गायक प्रिंस नरूला भी फिलहाल युवा कलाकारों को मौके देने में जुटे हैं। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में प्रिंस बताते हैं, 'मैंने कुछ दिनों पहले ही अपना लेबल लांच किया है। उस पर मैं कई नए-नए गानों के साथ युवा कलाकारों को भी लांच कर रहा हूं। ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट है पर पैसा नहीं है, उनके ऊपर मैं इनवेस्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जब आप खुद किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, नाम और पैसा कमा लेते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जूनियर प्रतिभाशाली कलाकारों को भी मौका दें। यह साल मेरा इसी में जाने वाला है। मैं अभी आठ-नौ गाने शूट करके आया हूं और फिर जल्द ही पांच-छह गाने शूट करने जाने वाला हूं। इस तरह से हर 10-15 दिन में मेरा एक गाना आने वाला है। मेरा अगला गाना जेलेसी 15 अगस्त को रिलीज होगा। इस गाने में बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है। इसे मुझ पर और मेरी पत्नी युविका पर फिल्माया गया है। इसके अलावा मैं एमएक्स प्लेयर की एक वेब सीरीज और एक पंजाबी फिल्म पर भी काम कर रहा हूं।'

फिलहाल अपने लेबल के अंतर्गत युवा प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं प्रिंस।

सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम

फिल्म जी ले जरा से निर्देशन में वापसी करेंगे फरहान

साल 2001 में फिल्म दिल चाहता है से बतौर निर्देशक, निर्माता और लेखक करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने अपने निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म का एलान किया है। मंगलवार को दिल चाहता है की रिलीज के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर फरहान ने बतौर निर्देशक अपनी अगली फिल्म जी ले जरा की घोषणा की। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कट्रीना कैफ और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में होंगी। फिल्म को फरहान ने अपनी बहन जोया अख्तर और रीमा कागती के साथ मिलकर लिखा है तथा वह अपने प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले ही इस फिल्म का निर्माण करेंगे। यह फिल्म भी उनके बैनर तले बनी पिछली फिल्मों दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह दोस्ती और रोड ट्रिप की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। इसमें तीनों लड़कियां एक साथ रोड ट्रिप पर निकलेंगी। फिल्म का पहला पोस्टर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए फरहान ने लिखा, 'क्या किसी ने रोड ट्रिप के बारे में कहा? बतौर निर्देशक अपनी अगली फिल्म का एलान करते हुए रोमांचित हूं। इसके लिए दिल चाहता है की 20वीं सालगिरह से बेहतर और क्या हो सकता था। इसकी शूटिंग वर्ष 2022 में शुरू होगी। इस फिल्म के लेकर अब इंतजार नहीं कर सकता हूं।' बता दें कि फरहान करीब 10 वर्ष बाद दोबारा निर्देशक की कुर्सी संभालने जा रहे हैं।

जी ले जरा में मुख्य भूमिका में होंगी प्रियंका, कट्रीना और आलिया ● इंस्टाग्राम